अपने अथक परिश्रम व अनुपम प्रतिभा से भारतीय क्रांति के पटल पर अमिट छाप छोड़ जाने वाले

आदर्शपूर्ण व महान कम्युनिस्ट नेता, सर्वहारा बुद्धिजीवी, पोलिटब्यूरो सदस्य व प्रवक्ता

कॉमरेड आजाद (राजकुमार) देश की हर सांस में जिंदा रहेंगे!

शोषित-उत्पीड़ित जनता के लिए 1 जुलाई 2010 भारी दुख का दिन था। फासीवादी ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत क्रांतिकारी नेताओं और आम जनता के कत्लेआम कर रहे लुटेरे शासक वर्गों ने इस दिन एक और निर्मम हत्याकाण्ड को अंजाम दिया। भारत की उत्पीड़ित जनता के प्यारे नेता, भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी व पोलिटब्यूरो के सदस्य और प्रवक्ता कामरेड आजाद को एक स्वतंत्र पत्रकार हेमचंद्र पांडे के साथ महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास से आंध्रप्रदेश की खुफिया एजेंसी एसआईबी और केन्द्रीय खुफिया संस्थाओं ने उठा लिया। उस समय वह पार्टी कैडरों को राजनीतिक अर्थशास्त्र की कक्षा चलाने के सिलसिले में दण्डकारण्य जा रहे थे। क्रांतिकारियों के खून की प्यासी एसआईबी ने उसी रात आदिलाबाद जिले के जोगापुर व सरकेपल्ली के जंगलों में ले जाकर दूसरे क्रांतिकारी नेताओं की तरह उनकी भी ठंडे दिमाग से गोली मारकर हत्या कर दी। सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम गिरोह की साजिश के तहत की गई इस जघन्य हत्या के बाद वही रटी-रटाई खबर फैलाई गई कि आदिलाबाद के जंगलों में हुई एक मुठभेड़ में आजाद और एक अज्ञात व्यक्ति मारे गये थे।

क्रांतिकारी संघर्ष का लम्बा अनुभव, अनोखी प्रतिभा, गहरी सैद्धांतिक व राजनीतिक समझ और शोषित जनता के प्रति असीम प्रेम के धनी कॉमरेड आजाद हमारी पार्टी के अग्रणी नेताओं में से एक थे। पिछले करीब चार दशकों से भारतीय क्रांति को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया। कामरेड आजाद की शहादत न केवल भारतीय क्रांति के लिए, बल्कि विश्व की तमाम संग्रामी जनता के लिए एक बड़ा धक्का है। पार्टी, पीएलजीए, जन संगठन, जनताना सरकार और तमाम क्रांतिकारी जनता की ओर से दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सिर झुकाकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजली पेश करती है और उनके उच्च आदर्शों को ऊंचा उठाए रखती है। उनके अधूरे लक्ष्य को पूरा करते हुए क्रांतिकारी संघर्ष को तेज करने का संकल्प लेती है। आज दुश्मन का खेमा खुशियां मना रहा है कि उसने आजाद की हत्या कर क्रांतिकारी संघर्ष की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। लेकिन शोषित जनता और समूचे क्रांतिकारी खेमे से हम आंखों से आंसुओं को पोंछकर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम दुश्मनों को ऐलान करते हैं कि देश में माओवादी जनयुद्ध को नई बुलंदियों पर पहुंचाकर उसे कोने-कोने में फैलाकर हम आजाद की हत्या का जरूर बदला लेंगे।

कॉमरेड चेरुकूरी राजकुमार (आजाद) का जन्म आंध्रप्रदेश के कृष्णा जिले में मई 1954 में हुआ था। मां करुणा और पिता लक्ष्मैया चौधरी की कुल पांच संतानों में वह दूसरी संतान थे। उनके पिताजी अबसे कुछ ही साल पहले गुजर गए थे, जबकि उनकी उम्रदराज मां जीवित हैं। वो चार भाई और एक बहन हैं। उनके बड़े भाई भारतीय सेना में कैप्टन रहे। उनके दो छोटे भाई डॉक्टर हैं। उनके पूर्वज कृष्णा जिले के पमिडिमुक्कला मण्डल के पेनुमत्सा के निवासी थे। उनके दादा के समय में ही उनका परिवार नूजिवीडु चला आया था। लक्ष्मैया चौधरी ने भी कुछ समय तक भारतीय सेना में काम किया था। बाद में नूजिवीडु में होटल का व्यवसाय चलाया था। उसके बाद

वर्ष-23

अंक-3

जुलाई-सितम्बर 2010

सहयोग राशि-10 रुपए

प्रभात

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

कॉमरेड आजाद का सफरनामा

(संक्षेप में)

1954	में जन्म (आंध्रप्रदेश के कृष्णा जिले में)
1972	में वरंगल में बी.टेक. की पढ़ाई के दौरान पार्टी से परिचय और पार्टी सदस्यता
1975	में रैडिकल छात्र संगठन का वरंगल जिला अध्यक्ष
1977	में पार्टी द्वारा विशाखापटनम में स्थानांतरित और जिला पार्टी कमेटी का सदस्य बने
1978	में रैडिकल छात्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष
1981	में मद्रास में राष्ट्रीयता के सवाल पर आयोजित सेमिनार में प्रमुख भूमिका
1983	में कर्नाटका राज्य में स्थानंतरित
1987	में कर्नाटका में गठित पहली राज्य पार्टी कमेटी का सचिव
1990	में आयोजित पार्टी के केन्द्रीय प्लीनम में सीओसी सदस्य के रूप में चुनाव
1990-2010	तक 20 साल केन्द्रीय कमेटी में रहे
1995-2001	केन्द्रीय कमेटी का सचिवालय सदस्य
2001	में आयोजित पुरानी भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) की 9वीं कांग्रेस में फिर से केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में चुनाव; पोलिटब्यूरो सदस्य के रूप में चुनाव
2004	में विलय में प्रमुख भूमिका, नई पार्टी - भाकपा (माओवादी) के गठन के बाद एकीकृत केन्द्रीय कमेटी और पोलिटब्यूरो का सदस्य
2007	में एकता कांग्रेस - 9वीं कांग्रेस में केन्द्रीय कमेटी में सदस्य के रूप में चुनाव
2001-2010	तक पोलिटब्यूरो सदस्य की जिम्मेदारी
2007-2010	तक केन्द्रीय कमेटी के प्रवक्ता 'आजाद' के रूप में जिम्मेदारी
2010	- 1 जुलाई को शहादत (आंध्रप्रदेश के आदिलाबाद के जंगलों में)

उनका परिवार पूरा हैदराबाद आकर बस गया जहां कॉमरेड आजाद के पिताजी ने होटल चलाया था। पढ़े-लिखे व खाते-पीते परिवार में पले-बढ़े कॉमरेड आजाद शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहे। पहले हैदराबाद के एक कॉन्वेंट स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें विजयनगरम जिले में स्थित भारत सरकार की कोरुकोण्डा सैनिक स्कूल में भर्ती कराया गया जहां से उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। खेल-कूद में भी आगे रहने वाले कॉमरेड राजकुमार शुरू से ही एक पढ़ाकू छात्र थे. .. साहित्य के प्रेमी भी थे। स्कूल के दिनों से ही छात्रों के अलावा शिक्षक भी उन्हें पसंद करते थे।

कॉमरेड आजाद का प्रेरणादायक क्रांतिकारी जीवन

कॉमरेड आजाद के जुझारू व गतिशील क्रांतिकारी जीवन की शुरूआत 1972 से होती है जब उन्होंने वरंगल के रीजनल इंजिनीयरिंग कॉलेज (आरईसी) में बी.टेक. में दाखिला लिया था। वहां से उन्होंने एम.टेक भी पूरा किया था। 1970 और 80 के दशकों में वरंगल का रीजनल इंजिनीयरिंग कालेज नक्सलबाड़ी राजनीति का गढ़ रहा। चूंकि आजाद को शुरू से ही पढ़ने का शौक रहा, इसलिए सम-सामयिक सामाजिक व राजनीतिक विषयों को लेकर उन्होंने सोचना शुरू किया। उस समय वरंगल शहर की दीवारों पर 'वरंगल को एक और श्रीकाकुलम बनाएंगे' और 'सामंतवाद मुर्दाबाद' के नारों को देखकर काफी प्रभावित हुए थे क्योंकि श्रीकाकुलम संघर्ष के प्रति उनके दिल में पहले से सहानुभूति थी। शहीद सूरपानेनी जनार्दन, जो बाद में तीन अन्य छात्रों के साथ आपातकाल के अंधेरे दिनों में गिराईपल्ली के जंगलों में झूठी मुठभेड़ में मारे गए थे, की प्रेरणा से राजकुमार क्रांतिकारी राजनीति में आए थे। उस समय रीजनल इंजिनीयरिंग कॉलेज में जनार्दन एक लोकप्रिय क्रांतिकारी छात्र नेता थे। कई छात्र उनके इर्द-गिर्द इकट्ठे हो जाते थे। आजाद उनके हॉस्टल रूम में रात-रात भर जनार्दन से क्रांतिकारी राजनीति पर बहस करते थे। ऐसी कई बहसों और अध्ययन के परिणामस्वरूप ही वह क्रांति की अवधारणा से पूरी तरह सहमत हुए थे। जब एक बार उन्होंने इस रास्ते को तहेदिल से अपना लिया, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस तरह 1972 से 2010 तक, यानी कुल 38 सालों तक उनकी क्रांतिकारी यात्रा बिना रुके व अविश्रांत जारी रही।

इस कॉलेज के छात्रों ने अक्टूबर 1974 में आंध्रप्रदेश रैडिकल छात्र संगठन (आरएसयू) का गठन करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस कॉलेज ने कई नेताओं, कार्यकर्ताओं व योद्धाओं को जन्म दिया, जिन्होंने न सिर्फ आंध्रप्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में योगदान दिया। कइयों ने अपने प्राणों को क्रांति के लिए न्यौछावर कर दिया। 1975 में कॉमरेड जनार्दन की हत्या से आजाद बेहद दुखी हुए थे और जल्द ही अपने दुख को दृढ़

शहीद आजाद की मां करुणा ने पत्रकारों को बताया-

"बचपन से ही राजकुमार गरीबों के प्रति सहानुभूति रखता था। हर दम उनके लिए कुछ भी करने की सोचता था। बचपन से ही आंदोलन के विचारों से प्रेरित होकर 38 साल पहले ही घर छोड़कर चला गया था। अपना नाम 'आजाद' बदल दिया। अपने पिता के गुजर जाने पर भी घर नहीं आया था। कहीं भी कोई मुठभेड़ की खबर आती थी तो मेरा कलेजा कांप उठता था। मैं यही कामना करती थी कि जहां भी रहे, मेरा बेटा सलामत रहे। लेकिन वह दिन आ ही गया, जिसको लेकर मैं डरती थी। मेरे बेटे ने निस्वार्थ जीवन जिया।"

विगत मार्च महीने में जब कॉमरेड शाखामूरी अप्पाराव की फर्जी मुठभेड़ में हत्या हुई थी, तब कॉमरेड आजाद से पार्टी नेतृत्व का संपर्क कट चुका था। इससे यह आशंका उत्पन्न हुई थी कि शायद कॉमरेड आजाद को दुश्मन ने उठा लिया होगा। इस आशंका से देश भर में जनवादी ताकतों ने चिंता प्रकट की थी। और आजाद की मां करुणा ने अदालत में एक याचिका भी दायर की थी। बाद में आजाद ने खुद ही बयान जारी कर कहा था कि वो ठीकठाक हैं, कुछ तकनीकी वजहों से भ्रम की स्थिति निर्मित हुई थी। उस मौके पर उन्होंने यह बताया था "मुझे इस याचिका के जरिए ही मालूम हो गया कि मेरी मां अभी भी जीवित हैं, वरना मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि वह कैसी हैं।" ★

संकल्प में बदलकर क्रांति के पथ पर आगे बढ़ते गए। इस दौरान कॉमरेड आजाद को सरकार ने मीसा के तहत गिरफ्तार कर छह महीनों तक जेल में रखा था। आपातकाल के हटने के बाद गिराईपल्ली की बदनाम फर्जी मुठभेड़ पर बनाई गई तार्कुंडे कमेटी और बाद में गठित भार्गव कमिशन के साथ मिलकर छात्र-नेता कॉमरेड आजाद ने कई जगहों का दौरा किया और उल्लेखनीय काम किया था ताकि उसका पर्दाफाश किया जा सके। रैडिकल छात्र संगठन (आरएसयू) की स्थापना से लेकर वह उससे जुड़े रहे। उन्होंने न सिर्फ छात्रों को, बल्कि प्रोफेसरों व बुद्धिजीवियों को भी बेहद प्रभावित किया था। उन दिनों वरंगल शहर में हुए तमाम छात्र आंदोलनों में कामरेड राजकुमार की नेतृत्वकारी भूमिका रही।

नक्सलबाड़ी व श्रीकाकुलम संघर्षों की अस्थाई पराजय के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों का केन्द्र तेलंगाना बन गया। अतीत का मूल्यांकन कर गलतियों से सबक लेकर काम शुरू करने से जनता के साथ संपर्क बढ़ने के साथ-साथ सभी तबकों के लोगों के संगठित होने का सिलसिला शुरू हुआ। वह जन आंदोलन का रूप लेने लगा। बाद में उभरकर आए सभी आंदोलनों ने यही साबित किया कि उत्पीड़ित जनता को पहले विचारों से जीत लिया जाए तो कार्याचरण में वही हथियार बन जाएंगे। इसी क्रम में आजाद में जो चेतना पैदा हुई उसने छात्र शक्ति का रूप धारण किया और आगे जाकर भारतीय क्रांति की अगुवाई में प्रमुख भूमिका निभाई। नक्सलबाड़ी व श्रीकाकुलम संघर्षों की पीछेहट के बाद मिले सबकों के आधार पर पार्टी को नए सिरे से संगठित कर व्यापक जनाधार तैयार करने में और व्यापक जन आंदोलनों का निर्माण करने में जिस पहली पीढ़ी ने आगे आकर पहलकदमी ली, उस पीढ़ी के प्रतिनिधि थे कॉमरेड आजाद।

कॉमरेड आजाद का क्रांतिकारी छात्र जीवन

क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता के चलते 1972 में ही वह पार्टी सदस्य बने थे। वरंगल शहर में कई मुद्दों को लेकर छात्रों को गोलबंद करने और छात्र-नौजवानों के आंदोलन खड़ा करने में कॉमरेड आजाद की पहलकदमी रही। उन्होंने प्रोफेसरों और पढ़ाने वाले अन्य स्टाफ से सम्बन्ध स्थापित किए। कालेज में काम करने वाले कई कर्मचारियों से भी उनके अच्छे सम्बन्ध बने थे। 1974 में उन्हें वरंगल जिला आरएसयू का अध्यक्ष चुन लिया

कॉमरेड आजाद का मृत शरीर : मुठभेड़ की झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए पुलिस ने घटना स्थल पर एक एके-47 और एक 9 एमएम पिस्तौल फेंककर उन्हें बरामद करने का दावा किया!

गया था। जब वरंगल शहर में छात्र आंदोलन विकसित होने लगा था, तब ऐसी स्थितियां सामने आई थीं कि गुण्डों का मुकाबला किए बिना आगे बढ़ना असंभव था। आरएसएस, कांग्रेसी हयग्रीवाचारी और सीपीएम वाले ओंकार के गुण्डों से दो-दो हाथ करना पड़ा था। कई बार झड़पें हुई थीं। छात्र गिरफ्तार हुए थे। उन्हें रिहा करवाने में आजाद ने कानूनी कामकाज भी किया।

1974 में जब अवसरवादियों ने क्रांतिकारी छात्र आंदोलन में फूट डालकर पी.डी.एस.यू. का गठन करने की कोशश की तो उन्हें राजनीतिक तौर पर हराकर रैडिकल छात्र संगठन खड़ा करने में आरईसी के छात्रों की भूमिका अहम थी जिनमें आजाद भी शामिल थे। छात्रों के बहुमत को हमारे पक्ष में लाने में कॉमरेड आजाद समेत कई कॉमरेडों ने प्रयास किए। उनके प्रयासों की बदौलत ही क्रांतिकारी छात्रों ने अवसरवादी व दक्षिणपंथी राजनीति को हराकर 1974 में आरएसयू की स्थापना की। इस बीच 1975 में आपातकाल लागू हुआ। उस समय आपातकाल के खिलाफ सांझे आंदोलन चलाने के कारण कॉमरेड आजाद दुश्मन के निशाने पर आए थे।

विशाखापटनम में निभाई जिम्मेदारी

छात्र आंदोलन की जरूरतों के मद्देनजर उन्हें पार्टी ने 1977 में विशाखापटनम भेजने का फैसला लिया। वहां जाकर उन्होंने आंध्रा विश्वविद्यालय में एम.टेक. में दाखिला लिया था ताकि छात्रों के बीच काम करने में सहूलियत हो सके। वहां पर पहले से मौजूद चंटी, गंटी रमेश, प्रसन्न जैसे कॉमरेडों को उत्साहित करते हुए उन्होंने छात्र आंदोलन को मजबूत बनाने पर पूरा जोर लगाया। सिटी बसों के राष्ट्रीयकरण की मांग से विशाखा शहर में एक प्रभावी व जुझारू जन आंदोलन चलाया गया था जिसने उस जमाने में पूरे शहर को झकझोर दिया था। इस आंदोलन का आरएसयू ने नेतृत्व किया था। यह आंदोलन सफल हुआ था जिससे संगठन की प्रतिष्ठा भी बढ़ी थी। इसके पीछे कॉमरेड आजाद की भूमिका अहम रही। उन दिनों आंध्रा विश्वविद्यालय में जातिवाद का बोलबाला था। कम्मा, रेड्डी आदि तथाकथित ऊंची जातियों के छात्र दलित व कथित रूप से पिछड़ी जातियों के छात्रों पर कई तरीकों का उत्पीड़न करते थे। इसके खिलाफ किए गए संघर्ष में आरएसयू की अगुवा भूमिका रही। कॉमरेड आजाद ने विश्वविद्यालय में प्रगतिशील व जनवादी सोच के तमाम छात्रों और अध्यापकों को इस संघर्ष के समर्थन में गोलबंद किया। साथ ही, जाति के सवाल को वर्ग दुष्टिकोण से देखने की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। इसका प्रभाव शहर के तमाम तबकों पर भी पड़ा। वरंगल की तरह विशाखा में भी कॉमरेड आजाद ने सभी तबकों के लोगों को क्रांतिकारी खेमे में आकर्षित किया और उनका स्नेह व विश्वास जीत लिया।

आपातकाल के बाद रैडिकल छात्र-नौजवानों ने 'चलो गांवों की ओर' के नारे के साथ ग्रामीण इलाकों में जाकर क्रांतिकारी राजनीति का प्रचार शुरू किया। यह अभियान हर साल खासकर गर्मी के दिनों में चलता था। व्यापक जनता के साथ पार्टी का संपर्क बढ़ाने और आगे चलकर मजबूत क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करने में यह काफी सहायक सिद्ध हुई। कॉमरेड आजाद वरंगल की ही तरह विशाखा में भी इस गांव चलो अभियान को सफल बनाने की पूरी कोशिश की। इस मौके पर प्रचार में जाने वाले छात्रों को क्रांतिकारी राजनीति पर कक्षाएं चलाने में उनका योगदान रहा। उनकी अगुवाई में छात्रों ने श्रीकाकुलम के उद्दानम इलाके से लेकर राजमण्ड्री तक व्यापक रूप से प्रचार अभियान चलाया जिससे जनता के साथ पार्टी के सम्बन्ध व परिचय बढ़ गए।

1977 में विशाखापटनम जाने के बाद कॉमरेड आजाद पहले श्रीकाकुलम-विशाखा संयुक्त जिला कमेटी का सदस्य चुन लिए गए थे। उसके बाद जिला कमेटी को कॉमरेड आजाद ने दोबारा संगठित किया जिसमें शहीद गंटि रमेश को भी शामिल किया गया। उन्होंने 1980 में आयोजित पार्टी के 12वें आंध्रप्रदेश अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। अधिवेशन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चली बहसों में उन्होंने उत्साह के साथ भाग लिया।

आरएसयू के अध्यक्ष के रूप में...

1978 में वरंगल शहर में आयोजित आरएसयू के दूसरे प्रदेश अधिवेशन में कॉमरेड आजाद को अध्यक्ष चुन लिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने देशव्यापी छात्र आंदोलन को संगठित करने का बीड़ा भी उठाया। इसी सिलसिले में 1981 में मद्रास शहर में एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसका विषय था 'राष्ट्रीयता का सवाल'। इसे सफल बनाने के लिए कॉमरेड आजाद ने करीब-करीब देश के हर हिस्से का दौरा किया। कई छात्र संगठनों, अन्य संगठनों और अलग-अलग शख़्सों से मिलकर उनसे चर्चा की। भारत में राष्ट्रीयता के प्रश्न को गहराई से समझने, विभिन्न संगठनों के दृष्टिकोणों को समझने और क्रांतिकारी संगठन के दृष्टिकोण से सभी को अवगत कराने में यह सेमिनार सफल रहा। राष्ट्रीयता के सवाल पर कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की नीति को स्पष्ट करने में तथा विभिन्न संगठनों से एकजुटता बनाने में कॉमरेड आजाद ने सराहनीय भूमिका निभाई। 1981 में आयोजित यह सेमिनार ही 1985 में स्थापित अखिल भारतीय क्रांतिकारी छात्र संघ (एआईआरएसएफ) की आधार-शिला थी। इस तरह एआईआरएसएफ की स्थापना में कॉमरेड आजाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

लगभग इसी समय करीमनगर-आदिलाबाद संघर्ष पूरे उत्तर तेलंगाना आंदोलन के रूप में विकसित हो चुका था। इस पर दमन चलाने के लिए शासक वर्गों ने पहले 'अशांत क्षेत्र अधि नियम' लागू किया। दमन और तीखा होता ही गया। इसी समय में हथियारबंद गुरिल्ला दस्तों के गठन का सिलसिला शुरू हुआ।

आधार इलाकों के निर्माण के लक्ष्य से दण्डकारण्य में गुरिल्ला जोन बनाने का फैसला लेकर गुरिल्ला दस्तों को भेजा गया। दण्डकारण्य में गुरिल्ले दस्तों ने काम करते हुए आदिवासियों को संगठित करना शुरू किया। इसी समय कॉमरेड आजाद को पार्टी ने कर्नाटका राज्य में तबादला किया ताकि वहां पर क्रांतिकारी आंदोलन की नींव डाली जा सके।

जेल की सलाखों की नहीं की परवाह

जुलाई 1975 में उन्हें मीसा कानून के तहत गिरफ्तार कर छह महीनों तक वरंगल जेल में रखा गया था। उस समय उनके परिवार सदस्य, दोस्त, अध्यापक, मजदूर और विभिन्न तबकों के लोग जेल और कोर्ट में जाकर आजाद से मिलते थे। वह उस समय छात्र-नौजवानों के लिए एक रोल मोडल से थे। उनके प्रभाव व संपर्कों का दायरा काफी बड़ा था। जेल से रिहा होने के बाद आपातकाल के समय हुई 'गिराईपल्ली मुठभेड़' के खिलाफ अदालतों में हुई बहस के लिए आवश्यक तमाम सबूत कॉमरेड आजाद ने जुटाए थे। उस समय भार्गव कमिशन और तार्कुंडे कमेटी का कॉमरेड आजाद ने काफी सहयोग किया था ताकि झूठी मुठभेड़ों का पर्दाफाश किया जा सके। कई बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मिलकर काम किया। इस तरह छात्र आंदोलन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही उन्होंने कानूनी और अदालती कार्रवाइयों पर काफी समझ बना ली जिससे उन्हें खुले संघर्षों को विकसित करने में मदद मिली। इन सारे प्रयासों के जरिए उन्होंने राज्य की पाशविकता का बढ़िया पर्दाफाश किया। उसके बाद अगस्त 1978 से अप्रैल 1979 के बीच में भी उन्हें विशाखापटनम में रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून - नासा) के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर आंध्रा विश्वविद्यालय में सरकारी झण्डा हटाकर काला झण्डा फहराने का केस लगाया गया था। दोनों बार गिरफ्तारी के दौरान वह मजबूत संकल्प के साथ खड़े रहे।

कर्नाटका में क्रांतिकारी आंदोलन का 'उदय'

आंध्रप्रदेश के क्रांतिकारी आंदोलन की एक खासियत यह थी कि उसने ऐसे कई कार्यकर्ता व नेता पैदा किए जिन्होंने देश के अलग-अलग प्रांतों में जाकर क्रांति का झण्डा गाड़ दिया। पार्टी नेतृत्व काफी सचेत व सजग था क्योंकि आंदोलन के साथ जुड़ने वाले छात्र-बुद्धिजीवियों और नौजवानों को परखते-पहचानते हुए उन्हें मा-ले-मा विचारधारा से शिक्षित कर संगठनकर्ता के रूप में देश के कई हिस्सों में भिजवा दिया ताकि क्रांतिकारी संघर्ष का विस्तार किया जा सके। इसी सिलसिले में कॉमरेड आजाद को 1983 में कर्नाटका राज्य में संगठनकर्ता के रूप में भिजवा दिया गया। वहां के तेलुगू बोलने वाले लोगों, बुद्धिजीवियों और छात्रों के साथ अपने सम्बन्धों के आधार पर उन्होंने पार्टी का काम शुरू किया। जल्द ही कर्नाटका में पार्टी व जन संगठनों का निर्माण शुरू किया। शहीद साकेत राजन जैसे मेधावी छात्रों को उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में आकर्षित किया। छात्रों, महिलाओं, मजदूरों व किसानों के बीच कॉमरेड आजाद ने काम किया। इससे वहां पार्टी व क्रांतिकारी आंदोलन का विकास होने लगा। कई जन संगठन खड़े हो गए। पार्टी का ढांचा भी तैयार हो गया। इसका मार्गदर्शन करने के लिए 1985 में एक नेतृत्वकारी टीम का गठन किया गया, जो 1987 तक राज्य कमेटी के रूप में विकसित हो गई। कॉमरेड आजाद कर्नाटका राज्य कमेटी के पहले सचिव बने थे।

शिमोगा क्षेत्र में राष्ट्रीयता के प्रश्न पर शुरू हुए एक आंदोलन का समर्थन करते हुए उसे जुझारू तरीके से चलाने में कॉमरेड आजाद का खासा योगदान रहा। कर्नाटका में रहते हुए ही उन्होंने अखिल भारतीय क्रांतिकारी छात्र संगठन के निर्माण में योगदान दिया। कई इलाकों का दौरा किया। कर्नाटका में युवा संगठनों, महिला आंदोलन, मजदूर संघर्षों और सांस्कृतिक संस्था को विकसित करने में कॉमरेड आजाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कर्नाटका के ग्रामीण इलाकों में क्रांतिकारी आंदोलन का निर्माण करने के लक्ष्य से हैदराबाद-कर्नाटका इलाके में, मुख्य रूप से रायचुर क्षेत्र में वहां की पार्टी ने काम को केन्द्रित किया। कर्नाटका के ग्रामीण इलाकों की परिस्थितियों का अध्ययन कर सामंतवाद-विरोधी संघर्षों को तेज करने के संकल्प से आजाद ने अपने कॉमरेडों को राजनीतिक रूप से प्रेरित किया। उस क्षेत्र में किसान संघर्षों को तेज करने में कॉमरेड आजाद का उल्लेखनीय योगदान रहा। शहीद साकेत राजन ने कर्नाटका के इतिहास का अध्ययन कर 'मेकिंग हिस्टरी' नामक एक किताब लिखी जिसे कर्नाटका के समाज में काफी महत्वपूर्ण स्थान हासिल हुआ। फिलहाल कर्नाटका के विश्वविद्यालयों में उस किताब को पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया। उसकी रचना करने में कॉमरेड आजाद ने साकेत का कई रूपों में सहयोग किया।

आंतरिक संघर्षों में किया क्रांतिकारी झण्डा ऊंचा

1985 में पुरानी भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) में चिन्हित की गई छह बुराइयों पर भूल-सुधार आंदोलन चलाने का फैसला हुआ था। इसके तहत कर्नाटका में भूल सुधार अभियान संचालित करने और पार्टी में राजनीतिक एकता कायम करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1984 में तत्कालीन पीपुल्सवार पार्टी में पहला आंतरिक संघर्ष हुआ था। उस समय सत्यमूर्ति, वीरास्वामी और माणिक्यम ने पार्टी में संकट की स्थिति पैदा की थी। भ्रम जैसा वातावरण निर्मित हुआ था। कॉमरेड आजाद ने तमिलनाडु के कैडरों को पार्टी की लाइन पर एकजुट रखने तथा कर्नाटका में पार्टी को मजबूती से खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे अवसरवादियों को अलग-थलग करने में मदद मिली।

1990 में आयोजित पुरानी भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) की केन्द्रीय प्लीनम में कॉमरेड आजाद को केन्द्रीय सांगठनिक कमेटी (सीओसी) सदस्य चुन लिया गया। इसके कुछ ही समय बाद, 1991 में फिर एक बार पुरानी पीपुल्सवार पार्टी में

आंतरिक संघर्ष छिड़ गया। इस बार संकट का कारण बने थे खुद पार्टी के उस समय के सचिव के.एस.। इस मौके पर के.एस, बंडैया आदि अवसरवादियों और पदलोलुपों की फूटपरस्ती राजनीति का कॉमरेड आजाद ने प्रशंसनीय ढंग से विरोध किया। उन्होंने कर्नाटका राज्य कमेटी की तरफ से तैयार की गई आलोचनात्मक रिपोर्ट में अवसरवादियों का बखूबी से पर्दाफाश किया। के.एस. को पार्टी से बरखास्त करने के बाद केन्द्रीय स्तर पर जो नया व युवा नेतृत्व उभरकर आया, उस टीम में कॉमरेड आजाद भी एक थे। दरअसल इस नई नेतृत्वकारी टीम की सामूहिक कोशिशों की बदौलत ही अवसरवादियों का पर्दाफाश कर पार्टी को एकजुट रखने और पार्टी की लाइन को समृद्ध बनाने में कामयाबी मिली।

क्रांतिकारियों की एकता के लिए की पहल

कॉमरेड आजाद ने क्रांतिकारियों, क्रांतिकारी पार्टियों और संगठनों के साथ एकता हासिल करने का पूरा प्रयास किया। खासकर पुरानी भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) और भाकपा (मा-ले) पार्टी यूनिटी के बीच विलय में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। उसके बाद भारत की दो प्रमुख क्रांतिकारी धाराओं - सीपीआई (एम-एल) की धारा और एमसीसी की धारा - के बीच ऐतिहासिक एकता कायम करने में कॉमरेड आजाद की भूमिका महत्वपूर्ण रही। दोनों पुरानी पार्टियों के बीच कई दफे चली द्विपक्षीय बैठकों में कॉमरेड आजाद ने भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) के प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में भाग लिया। उस दौरान दस्तावेजों का आदान-प्रदान, अध्ययन, दोनों पुरानी पार्टियों के व्यवहार के सकारात्मक पहलुओं का संश्लेषण कर उसे नए एकीकृत पार्टी के दस्तावेजों में समाहित करने आदि काम में कॉमरेड आजाद ने अविस्मरणीय योगदान दिया। इसके अलावा भी कई देश-विदेश के प्रतिनिधिमण्डलों से हुई चर्चा में कॉमरेड आजाद ने कई बार हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एकता का जो अध्याय होगा उसमें कॉमरेड आजाद का नाम जरूर दर्ज होगा।

आंध्रप्रदेश के क्रांतिकारी संघर्ष का किया मार्गदर्शन

कॉमरेड आजाद ने कर्नाटका राज्य कमेटी की जिम्मेदारी को देखते हुए भी आंध्रप्रदेश के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जीवंत रिश्ता बनाए रखा। केन्द्रीय कमेटी के सदस्य के रूप में उन्होंने कई बार उत्तर तेलंगाना का दौरा कर व पार्टी कमेटियों की बैठकों में भाग लेकर वहां के आंदोलन को मार्गदर्शन दिया। 2001 में आयोजित पुरानी पीपुल्सवार की पार्टी कांग्रेस के बाद उन्होंने पोलिटब्यूरो सदस्य के रूप में आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी की जिम्मेदारी भी ली। राज्य कमेटी की बैठकों में शामिल होकर आंदोलन का मार्गदर्शन किया करते थे। खासकर 2004 में जब सरकार के साथ वार्ता चली थी, उस समय उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वार्ता के लिए एजेण्डे से लेकर हरेक राजनीतिक मुद्दे को तय करने में उन्होंने अहम योगदान दिया। उस समय कई लेखों, बयानों और पत्रिकाओं में साक्षात्कारों के जरिए उन्होंने लुटेरे शासकों के दोगलेपन व दमनकारी चरित्र का पर्दाफाश किया। वार्ता के टूट जाने के तुरंत बाद संभावित क्रूर शत्रु हमले का माकूल जवाब देने के लिए पार्टी व पीएलजीए को मुस्तैदी से तैयार रखने पर उन्होंने जोर दिया और राज्य कमेटी को इस दिशा में मार्गदर्शन दिया।

अदम्य सैद्धांतिक योद्धा

कॉमरेड आजाद ने पार्टी में राजनीतिक व सैद्धांतिक शिक्षा चलाने के लिए गठित 'स्कोप' (राजनीतिक शिक्षा पर सब-कमेटी) में अहम भूमिका निभाई थी। 1995 से 2004 तक उन्होंने स्कोप के इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाली। 1985-95 के बीच की अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति पर नोट्स तैयार करने और उसके लिए आवश्यक शब्दकोश तैयार करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। भारतीय अर्थव्यवस्था पर पाठ्य पुस्तक बनाई। वह विभिन्न स्तर के कॉमरेडों को व्यक्तिगत रूप से भी सूचित करते थे कि किन-किन किताबों व लेखों को पढ़ना चाहिए और किसे किस रूप में समझना चाहिए। दुनिया भर के कम्युनिस्ट खेमे से और प्रतिक्रियावादी खेमे से निकलने वाले नए साहित्य पर हमेशा उनकी नजर रहती थी। पार्टी के अधिवेशनों और कांग्रेसों के दौरान दस्तावेजों की तैयारी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सैद्धांतिक व राजनीतिक मामलों में तथा कार्यक्रमों को तय करने में उन्होंने कमेटी में गतिशील व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजाद को जनता पर और मा-ले-मा सिद्धांत पर अटल विश्वास था। और सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ने तथा व्यवहार से मिलनी वाली शिक्षा से फिर सिद्धांत को विकसित करने की मार्क्सवादी पद्धति को कॉमरेड आजाद ने पूरी तरह आत्मसात किया।

रैडिकल छात्र संगठन का नेतृत्व करते समय से लेकर आखिर तक उन्होंने पार्टी में विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन किया, कई पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे। आलोचनाएं लिखीं। उन्हें तेलुगू के अलावा इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ व तमिल भाषाओं में भी अच्छी-खासी पकड़ थी। खासकर इंग्लिश में उनका ज्ञान काफी समृद्ध था जिससे पार्टी को व क्रांतिकारी आंदोलन को काफी मदद मिली। उन्होंने खुद इंग्लिश में कई लेख, दस्तावेजों के प्रारूप, सरकुलर आदि लिखे और बहुत कुछ उन्होंने अंग्रेजी से अनुवाद भी किया ताकि कॉमरेडों से पढ़ाया जा सके। पहले 'रैडिकल मार्च' और 'कलम' पत्रिकाओं की जिम्मेदारी संभाली थी जोकि छात्र संगठन की पत्रिकाएं थीं। 'वैनगॉर्ड', 'पीपुल्समार्च', 'माओइस्ट इन्फर्मेशन बुलिटिन' आदि पत्रिकाओं के लिए उन्होंने कई राजनीतिक व सैद्धांतिक लेख लिखे थे। पार्टी की 'पीपुल्सवार' आदि पत्रिकाओं के संचालन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा कई राज्यों से संचालित पार्टी की विभिन्न पत्रिकाओं को वो जब भी मौका मिले, पढ़कर अनमोल सुझाव

दिया करते थे और खामियां बताया करते थे ताकि पत्रिका एक संगठनकर्ता के रूप में सुचारू रूप से काम कर सके।

पार्टी के सिद्धांत, व्यवहार व लाईन के खिलाफ जब भी किसी ने हमला किया, कॉमरेड आजाद ने हमेशा अपनी कलम से डटकर मुकाबला किया। एक जमाने के क्रांतिकारी बुद्धिजीवी बालगोपाल ने 1993 में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता पर कुछ बुनयादी सवाल उठाए थे जिससे कई अन्य बुद्धिजीवियों में भी भ्रम की स्थिति व्याप्त हुई थी। उस मौके पर पार्टी की ओर से कॉमरेड आजाद ने 1995 में एक लेख और 2001 में 'समीर' के छद्म नाम से तेलुगू में एक जबर्दस्त किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने बालगोपाल के दार्शनिक भ्रमों की प्रतिभाशाली ढंग से आलोचना की। इस किताब में उत्तर-आधुनिकतावाद के दिवालिए और प्रतिक्रियावादी चरित्र का भी उन्होंने पर्दाफाश किया। इस किताब को क्रांतिकारी खेमे के तमाम लेखकों व बुद्धिजीवियों ने सराहा। विभिन्न किस्म के दक्षिणपंथी अवसरवादियों और संशोधनवादियों के राजनीतिक दिवालिएपन व झूठे आरोपों का जवाब देने में कॉमरेड आजाद आगे रहे।

'शहरी कामकाज पर हमारा दृष्टिकोण' दस्तावेज को तैयार करने में कॉमरेड आजाद का योगदान महत्वपूर्ण था। पिछले कुछ सालों से वह हमारी पार्टी के शहरी कामकाज के प्रभारी थे। इस तरह शहरी कामकाज के मामले में उन्होंने खासा अनुभव हासिल किया और पार्टी कैडरों को इस पर शिक्षित भी किया। महिला के सवाल पर बनाए गए दस्तावेज को अंतिम रूप देने में भी कॉमरेड आजाद की भूमिका रही। एक शब्द में कहा जाए, पिछले 40 वर्षों से हमारी पार्टी की राजनीतिक व सामरिक लाईन व सैद्धांतिक समझदारी में आए विकासक्रम से कॉमरेड आजाद को अलग करके देखा नहीं जा सकता।

दुश्मन के मनोवैज्ञानिक युद्ध के खिलाफ कलम का सेनानी बनकर...

2007 से वह केन्द्रीय कमेटी के प्रवक्ता नियुक्त किए गए थे। तभी से उनका नाम देश-दुनिया के लिए 'आजाद' बन गया। पार्टी के अंदर उन्हें अलग-अलग जगहों पर उदय, मधु, गंगाधर, दिनेश, परिमल आदि नामों से बुलाते थे। 21 सितम्बर 2004 को नई पार्टी के उदय के बाद देश के लुटेरे शासक वर्गों ने क्रांतिकारी आंदोलन का जड़ से सफाया करने की मंशा से दमनात्मक अभियानों में तेजी लाई। दण्डकारण्य में सलवा जुडूम के नाम से, झारखण्ड में सेंदेरा व नागरिक सुरक्षा समिति के नाम से, आंध्रप्रदेश में विभिन्न किस्म के काले गिरोहों के नाम से, पश्चिम बंगाल में हर्मद बाहिनी के नाम से और ओड़िशा में शांति सेना के नाम से फासीवादी व चौतरफा हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद 2009 से केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच तालमेल के साथ एक देशव्यापी फासीवादी सैन्य-दमन आक्रमण शुरू हुआ। दुश्मन के इन आक्रमणों का आधार साम्राज्यवादियों की एलआईसी की रणनीति व काउण्टर-इंसर्जेन्सी की नीतियां है। इसमें एक बड़ा रोल दुष्प्रचार युद्ध का है जो उसके मनोवैज्ञानिक युद्ध का प्रमुख हिस्सा है। दुश्मन मीडिया का बेशर्मी के साथ दुरुपयोग करते हुए, कार्पोरेट आकाओं के तलवे चाटने वाले चंद मीडिया एंकरों व पत्रकारों के जरिए एक भारी दुष्प्रचार युद्ध छेड़ दिया।

एक प्रवक्ता के रूप में कॉमरेड आजाद ने इस हमले का मुकाबला बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया। ऑपरेशन ग्रीनहंट की असली मंशाओं का पर्दाफाश करते हुए देश-दुनिया को अवगत करवाया कि साम्राज्यवादियों व बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए ही भारत सरकार ने जनता पर यह घृणित व नाजायज युद्ध छेड़ दिया है जिससे खासकर आदिवासी जनता के अस्तित्व को खतरा है। सोनिया-मनमोहन-चिदंबरम गिरोह के दुष्प्रचार व मनोवैज्ञानिक युद्ध के खिलाफ उन्होंने माकूल क्रांतिकारी प्रचार अभियान लगातार चलाया। समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर जनता के सामने पार्टी का पक्ष पेश किया। जब लोगों को गुमराह करने के लिए शासक गिरोह 'शांति वार्ता', 'हिंसा त्यागने' आदि ढोंगी प्रस्तावों को उछालता रहा, तो कॉमरेड आजाद ने साक्षात्कारों व बयानों के जरिए पार्टी का मत स्पष्ट करते हुए ही उनके दमनकारी व खूंखार चेहरे को उजागर किया कि शांति का घोर विरोधी खुद शासक गिरोह है। यही कारण है की चिदंबरम गिरोह को आजाद का भूत नींद में भी सताने लगा था। आज उनकी मृत्यु से भारतीय क्रांति ने एक बेमिसाल सैद्धांतिक योद्धा खो दिया है।

सतत अध्ययनशील होने के साथ-साथ वह एक तेज, सृजनशीन, गंभीर, अथक व गहन लेखक भी थे। आर्थिक मंदी से लेकर नेपाल के परिणामों तक हर मुद्दे पर उनकी कलम चलती रही। 1990 के दशक में आए साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण

4 जुलाई 2010 - हैदराबाद में हजारों जनता ने दी कॉमरेड आजाद को अंतिम विदाई

पर पार्टी पत्रिकाओं में उन्होंने लगातार लेख लिखे। कई प्रेस बयानों, माओइस्ट इन्फर्मेशन बुलेटिन के नियमित प्रकाशन, साक्षात्कार और लेखों के जरिए उन्होंने ऐसा काम किया जो आने वाले समय में समूची पार्टी कतारों के लिए एक नमूना के रूप में रहेगा। हमारी पीएलजीए व जनता द्वारा की जाने वाली जवाबी हिंसा की कार्रवाइयों के खिलाफ, कार्रवाइयों के दौरान होने वाली कुछ गलतियों के बहाने और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ दुश्मन ने बड़े पैमाने पर विभिन्न किस्म का दुष्प्रचार किया ताकि माओवादी संगठन को एक आतंकवादी संगठन के रूप में चित्रित कर शहरी मध्यम वर्ग व बुद्धिजीवियों को क्रांतिकारी संघर्ष से विमुख बनाया जा सके तथा पार्टी कतारों में भ्रम का माहौल निर्मित किया जा सके। लेकिन समूची पार्टी ने इस दुष्प्रचार युद्ध का बेहतर तरीके से मुकाबला किया जिसमें मुख्य व प्रेरणादायी भूमिका कॉमरेड आजाद की रही।

कॉमरेड आजाद एक ही आंख से देख पाते थे। दूसरी आंख में रोशनी चली गई थी। और जिस आंख से देखते थे वह भी कमजोर थी। लेकिन इस कमी के कारण देश-दुनिया को हर पल जानने-समझने में वह कभी पीछे नहीं रहे। वह घण्टों काम करते थे। और गहन अध्ययन करते थे। वह जहां भी रहें, जंगल में, शहर में, बस में या चाय की दुकान में, हर दम पढ़ने, सीखने व समझने को तत्पर रहते थे। एक आंख से ही वो घण्टों कम्प्यूटर के सामने बैठ जाते थे। एक प्रवक्ता के रूप में उन्होंने करीब-करीब हर मुद्दे पर पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह चाहे डेमाक्रटिक ओबामा की नीतियों का मामला हो, भगवा आतंकियों की काली करतूतों का मामला हो, गाजा पर इज्राएल के हमले का विषय हो, या फिर विश्व अर्थव्यवस्था में छाई मंदी... हर मुद्दे पर, हर मसले पर उन्होंने बयान जारी किया या लेख लिखे। अभी हाल में बी.जी. वर्घीस नामक एक नामी लेखक/पत्रकार ने 'आउटलुक' पत्रिका में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने अपने नव-उपनिवेशवादी दिमाग का नंगा परिचय दिया था। इसके खिलाफ कॉमरेड आजाद ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने वर्घीस की आलोचना तो की ही, पर देश के विकास को लेकर माओवादी अवधारणा को जनता के सामने बेहद प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। इत्तेफाक है कि यह लेख उनके शहीद होने के बाद ही प्रकाशित हो पाया। इसके पहले अप्रैल में 'दि हिंदू' अखबार को उन्होंने एक लम्बा साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने वार्ता या संघर्ष विराम के मुद्दे पर पार्टी का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के साथ-साथ माओवादी संघर्ष के कई पहलुओं पर उन्होंने रोशनी डाली। यह उनका आखिरी साक्षात्कार था। इसके पहले इकॉनमिक एण्ड पोलिटिकल वीक्ली तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए भी पार्टी की तरफ से कई लेख लिखे।

कॉमरेड आजाद ने क्रांति के दुश्मनों के खिलाफ, खासकर चिदम्बरम, जी.के. पिल्लै, रमनसिंह, अर्णाब गोस्वामी, विश्वरंजन जैसे कार्पोरेट घरानों के नमकहलाल सेवकों के खिलाफ जबर्दस्त व्यंग्य का प्रयोग किया। उनके झूठों, बेतुके तर्कों और दिवालिया दलीलों पर वह अपने व्यंग्य से निर्मम प्रहार करते थे। उनकी लेखन-शैली राजनीतिक तौर पर आक्रामक तथा व्यावहारिक दृष्टि से संतुलित व संयमित हुआ करती थी। अप्रैल 2010 में लोकसभा में बहस के दौरान जवाब देते हुए चिदम्बरम ने हमारी पार्टी के दस्तावेजों से उद्धृत करते हुए अपनी ही संसद को कितनी बार 'सुअर का बाड़ा' बताया था, इस पर भी कॉमरेड आजाद ने अपनी हंसी साथियों को लिखे पत्रों में व्यक्त किया। प्रतिक्रियावादियों, रंग-बिरंगे संशोधनवादियों, दक्षिणपंथी अवसरवादियों और फूटपरस्ती लोगों के खिलाफ उनकी कलम काफी तल्ख हुआ करती थी। व्यापक जनता को क्रांति के पक्ष में जीतने वाली विनम्र लेखन-शैली भी थी उनकी। किसी भी मुद्दे पर गहरा विश्लेषण, सटीक समझ और ठोस समाधान - ये उनके पाठकों को मिल जाते थे। कोरी बौद्धिक क्षमताओं का प्रदर्शन, गैर-जरूरी विवरण और संदर्भरहित दलीलों को उनके लेखन में कोई जगह नहीं थी। लेखन में उनके तर्क और उनकी पुष्टि करने के लिए पेश किए जाने वाले सबूत इतने जबर्दस्त और तगड़े होते थे कि विरोधियों के लिए उनको काट पाना करीब-करीब असंभव होता था। आज आजाद की मौत से शोषित जनता ने अपनी एक मुखर आवाज व पैनी कलम भी खो दी।

दण्डकारण्य संघर्ष का साथी

कॉमरेड आजाद दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन से भी घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। वह जहां भी रहें दण्डकारण्य में घटने वाली हर घटना पर नजर रखते थे। यहां फौजी मोर्चे पर जनता और पीएलजीए द्वारा हासिल हर कामयाबी पर वह प्रसन्नता व्यक्त करते थे। 6 अप्रैल 2010 को ताड़िमेट्ला (मुकरम) के पास पीएलजीए द्वारा किए गए ऐतिहासिक हमले के बाद, जिसमें 76 भाड़े के जवानों की मौत हुई थी, कॉमरेड आजाद ने यहां के तमाम कॉमरेडों को लाल अभिनंदन प्रेषित किया और शहीदों को श्रद्धांजली पेश की। और इस हमले की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अंग्रेजी में एक जबर्दस्त कविता भी लिखी। वह जनता से जितना प्यार करते थे, उतनी ही वर्ग दुश्मनों के प्रति नफरत रखते थे। शहादत की हर घटना पर, हर शहीद कॉमरेड पर वह संवेदना व दुख प्रकट करते थे और वर्ग दुश्मनों व उनके भाड़े के गुर्गों का खात्मा करने में पीएलजीए द्वारा हासिल हर कामयाबी पर खुशी प्रकट करते थे।

2005 में दण्डकारण्य के बस्तर क्षेत्र में सलवा जुडूम शुरू हुआ था और शोषक-शासकों के तलवे चाटने वाले मीडिया ने उसे 'जनता का सस्फूर्त आंदोलन' के रूप में खूब प्रचारित किया। उसका विरोध करते हुए तथा क्रांतिकारी संघर्ष का जोरदार समर्थन करते हुए कामरेड आजाद ने अथक प्रचार किया। पार्टी व जन-पक्षधर बुद्धिजीवियों के अथक प्रयासों की बदौलत ही पूरी दुनिया को इस बात से अवगत करवाया गया कि

वह पूरी तरह सरकार-प्रायोजित फासीवादी दमन अभियान था। प्रति-क्रांतिकारी सलवा जुडूम को पराजित करने के लक्ष्य से राजनीतिक प्रचार के मोर्चे पर किए गए प्रयासों में कॉमरेड आजाद का योगदान महत्वपूर्ण था। ऑपरेशन ग्रीन हंट के शुरू होने के बाद से दण्डकारण्य में आदिवासियों के नरसंहार की घटनाओं में तेजी आई। वेच्चापाड़, गगनपल्ली, सिंगनमडुगु, गोमपाड, गुमियापाल.... आदि कई नरसंहारों का पर्दाफाश करने और इस ओर देश भर के जनवादी ताकतों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कॉमरेड आजाद ने अथक प्रयास किया। फील्ड से भेजी गई रिपोर्टों का उन्होंने अनुवाद व संपादन कर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किया था। दण्डकारण्य संघर्ष की 25वीं बरसी के अवसर पर कॉमरेड आजाद ने बधाई संदेश के साथ-साथ एक लेख लिखा था। जिसमें उन्होंने दण्डकारण्य में मौजूद अनमोल प्राकृतिक संपदाओं को लूटने की ताक में बैठी बहुराष्ट्रीय व बड़े दलाल पूंजीपतियों की कम्पनियों के खिलाफ व्यापक व जुझारू संघर्ष व शक्तिशाली संयुक्त मोर्चे की जरूरत पर जोर दिया था। आज जब दण्डकारण्य संघर्ष अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, कॉमरेड आजाद की कमी बहुत खलेगी। दण्डकारण्य के नेतृत्वकारी कैडरों को राजनीतिक अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनकी क्लास सुनने से वंचित होना पड़ा। उनकी मृत्यु से दण्डकारण्य की जनता ने अपने एक प्यारे व शुभचिंतक नेता खो दिया जिन्होंने उनका हर दुख-दर्द में और हर कामयाबी में साथ दिया था।

आजाद के आदर्शों को ऊंचा उठाए रखेंगे!
हजारों 'आजाद' पैदा करने की कसम खाएंगे!!

कामरेड आजाद एक महान कम्युनिस्ट थे जो 'सादी जिंदगी और कठोर परिश्रम' के उसूल पर न सिर्फ यकीन किया, बल्कि अमल भी कर दिखाया। उन्होंने अपने करीब चार दशकों के क्रांतिकारी जीवन में एक मिनट भी फिजूल खर्च नहीं किया। हंसमुख, हास्यप्रिय, रचनात्मक और सतत चिंतनशील रहने वाले कॉमरेड आजाद हर स्तर व हर उम्र के साथियों से इस कदर घुलमिल जाते थे कि लगता ही नहीं था कि वह इतने बड़े बुद्धिजीवी या नेता होंगे। लुटेरे शासक सोचते होंगे कि कॉमरेड आजाद को हमसे छीनकर वे क्रांति को रोक लेंगे। लेकिन खुद क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास ही इस बात का गवाह रहा कि कैसे हम अपनी पराजय को भी विजय में तब्दील कर सकते हैं। दरअसल जनता और क्रांतिकारी आंदोलन ने ही 'आजाद' को पैदा किया और कठोर वर्ग संघर्ष ने ही उन्हें तराशा। आगे भी ऐसे कई 'आजाद' जरूर पैदा होते रहेंगे और वर्ग संघर्ष की आग में तपकर फौलाद बनते रहेंगे। इतिहास की गति का अकाट्य नियम है यह।

पत्रकार हेमचंद्र के साथ उनकी हत्या की खबर सुनकर देश-विदेशों से कई जनवादी, प्रगतिशील व क्रांतिकारी संगठनों और अमनपसंद शख़्सों ने हत्यारी शोषक सरकारों के प्रति अपना गुस्सा प्रकट किया। कई मानवाधिकार संगठनों, जनवादी संगठनों, अलग-अलग लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों, मीडियाकर्मियों ने आजाद की हत्या की निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग की। कई प्रमुख पत्रिकाओं में लेख लिखे गए। देश-विदेश के कई क्रांतिकारी संगठनों व पार्टियों ने कॉमरेड आजाद की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए हमारी पार्टी के नाम संदेश भेजे। एक शब्द में कहें तो देश-दुनिया के समूचे मेहनतकश अवाम और जनवादी व क्रांतिकारी खेमे ने इसे अपना खुद का नुकसान माना। इसे अपने खुद के दुख के रूप में महसूस किया। देश के तमाम गुरिल्ला जोनों में जनता और जन-सैनिकों ने अपने आंसुओं को पोंछकर शपथ ली कि कॉमरेड आजाद के अधूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनयुद्ध को देश के कोने-कोने में फैलाते हुए तेज करेंगे... हजारों-लाखों लोगों को क्रांतिकारी संघर्ष से जोड़ेंगे... हजारों 'आजाद' पैदा करेंगे। ★

जन पक्षधर व स्वतंत्रता-प्रेमी पत्रकार

हेमचंद्र पाण्डे को जन-जन का लाल सलाम!

कॉमरेड आजाद के साथ पुलिस के हाथों पाशविकता से मारे जाने वाले दूसरे व्यक्ति हेमचंद्र पाण्डे एक स्वतंत्र पत्रकार थे जो उत्तराखण्ड के पिथोरागढ़ जिले के देवरथल गांव के निवासी थे। मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मे हेमचंद्र ने कुमायूं विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी। अनुवाद की प्रक्रिया में उन्होंने डिप्लोमा भी किया। पत्रकारिता में डिप्लोमा कर उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। फिलहाल वो गैर-सरकारी संगठनों पर पीएच.डी. कर रहे थे। नई दुनिया, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा आदि दैनिक समाचार-पत्रों के लिए उन्होंने कई लेख लिखे। 'चेतना' नामक एक पत्रिका के लिए वह सब-एडिटर के रूप में भी काम कर रहे थे। उनकी जीवनसंगिनी का नाम बबिता है। पत्रकारिता को हेमचंद्र ने न सिर्फ आजीविका के साधन के रूप में, बल्कि सामाजिक दायित्व के साथ तथा शोषितों के प्रति प्रतिबद्धता से चुना था। इसी सामाजिक बोध से उन्होंने अल्मोरा में जंगल बचाओ और पृथक उत्तराखण्ड आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) में सक्रिय

काम किया था। जहां भी अन्याय होता है तो उस पर उनकी मानवीय प्रतिक्रिया रहती थी। जनवादी मूल्यों की स्थापना के लिए वह समर्पित थे। दरअसल एक पत्रिकार के अंदर जो-जो गुण होने चाहिए, वो सब उनमें थे। शायद यही वजह होगी कि वह दण्डकारण्य में ग्रीन हंट के जुल्म-अत्याचारों को जानने-समझने के लिए कॉमरेड आजाद के साथ निकले हुए होंगे।

स्वतंत्र पत्रकार हेमचंद्र पाण्डे का मृत शरीर

इंसानों के अंदर इंसानी गुणों का होना, इंसानियत के साथ बरताव करना आज शासक वर्गों की नजरों में गुनाह हो गया। यही वजह है कि हेमचंद्र पाण्डे के वजूद को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। खासकर हाल के समय में अरुंधति राय जैसे जनवादी बुद्धिजीवियों का दण्डकारण्य का दौरा करना, यहां पर जारी ग्रीन हंट के जुल्मों को उजागर करना यह सब चिदम्बरम गिरोह के गले नहीं उतर रहा है। ऐसे लोगों को एक चेतावनी देने के आशय से भी उसने हेमचंद्र पाण्डे की हत्या करवाई। यही नहीं, आजाद की हत्या का कोई सबूत न रहे, इसलिए भी उन्होंने इस पाशविक हत्या को अंजाम दिया। प्रेस की आजादी पर यह कुठाराघात सा है।

पत्रकार हेमचंद्र की हत्या को लेकर देश भर में, खासकर आंध्रप्रदेश में मीडिया, जनवादियों और बुद्धिजीवियों ने सरकार की जमकर निंदा की। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र के नाम से फासीवाद लागू है। उनके शव को लेने के लिए दिल्ली से आई उनकी पत्नी बबिता के साथ आंध्रप्रदेश के पत्रकारों ने भाईचारा प्रकट किया और चंदा जुटाकर उनकी आर्थिक मदद भी की। दिल्ली में स्वामी अग्निवेश के कार्यालय में एक मीटिंग हुई जिसमें बी.डी. शर्मा, अरुंधति राय, गौतम नवलखा आदि प्रमुखों ने भाग लिया। सभी ने हेमचंद्र को श्रद्धांजली दी और इस फर्जी मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्हें अंतिम विदाई देने के बाद में बबिता ने शव को एम्स अस्पताल को सौंप दिया जोकि हेम की इच्छा रही।

आंध्रप्रदेश से कहीं दूर उत्तराखण्ड में पैदा होकर सरकारी हिंसा व खतरों की परवाह किए बगैर जनता के पक्ष में खड़े होकर शहादत की घड़ी में कॉमरेड आजाद का साथ निभाने वाले इस जन पक्षधर व चेतनाशील पत्रकार को माओवादी पार्टी के तमाम कतार और क्रांतिकारी जनता हमेशा याद रखेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में शहीद होने वाले साथियों के साथ हेम को भी समुचित व सम्मानपूर्वक दर्जा होगा। सभी उनकी शहादत का गुणगान करेंगे। ✶

(... पेज 17 का शेष)

ने उन्हें मलकनगिरी डिवीजन के पप्पुलूर एरिया में स्थानांतरित किया। वहां पर उन्होंने दस्ता कमाण्डर के रूप में काम करते हुए कोण्डारेड्डी समुदाय की जनता का असीम प्रेम हासिल किया। उनके साथ घुलमिलकर उन्हें कई संघर्षों में गोलबंद किया। बाद में मोटू इलाके में स्थानांतरित होकर एरिया कमेटी सचिव की जिम्मेदारी लेकर काम किया। इस तरह उन्होंने एओबी की जनता के दिलों में सदा के लिए अपनी छाप छोड़ दी।

दस साल बाद, 2006 में कॉमरेड शारदा को पार्टी ने फिर से दण्डकारण्य में स्थानांतरित किया। माड़ डिवीजन के आंदोलन का वह फिर एक बार हिस्सा बन गईं। उन्हें इंद्रावती एरिया के आदेड़ इलाके में संगठन की जिम्मेदारियां दी गईं। तब तक माड़ डिवीजन में क्रांतिकारी आंदोलन काफी विकास कर चुका था। गांव-गांव में जनताना सरकार, ग्राम पार्टी कमेटी और जन मिलिशिया का विकास हो चुका था। अपने इलाके में इनके सुचारू संचालन के लिए कॉमरेड शारदा ने अथक परिश्रम किया। जनताना सरकार के तहत गांवों में विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें लागू करने में कॉमरेड शारदा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। गावों में और पार्टी के भीतर पितृसत्ता के खिलाफ उन्होंने आखिर तक संघर्ष किया।

कॉमरेड शारदा की गुरिल्ला जिंदगी के बारे में भी विशेष रूप से उल्लेख करना जरूरी है। 1996 में दण्डकारण्य में आयोजित विशेष महिला मिलिटरी प्रशिक्षण कैम्प में उन्होंने काफी उत्साह के साथ भाग लिया था। कैम्प के आखिर में आयोजित प्रतिस्पर्धाओं में उन्होंने अपना कौशल दिखाकर इनाम जीते थे। दुबली-पतली और कमजोर सी दिखने वाली कॉमरेड शारदा ने अपनी पूरी ताकत को बाहर लाकर फौजी प्रशिक्षण हासिल करने में पहलकदमी दिखाई। 2001 में पार्टी द्वारा संचालित पहले कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान (टीसीओसी) के दौरान कलिमेला थाने पर किए गए हमले में उन्होंने एक टीम की कमान संभाल ली और अतिरिक्त बलों के आने के रास्ते को जाम करने की जिम्मेदारी संभाली। हमले की सफलता और 42 हथियारों की जब्ती में कॉमरेड शारदा ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। शत्रु बलों के साथ हुई कुछ मुठभेड़ों में भी वह दृढ़ता से डटी रही।

कॉमरेड रामक्का की असमय मृत्यु से माड़ डिवीजन की जनता बुरी तरह आहत हुई। उनके अधूरे सपनों को साकार बनाने का संकल्प लेते हुए जनता, क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं और पार्टी ने संघर्ष को तेज करने की कसम खाई। उनके दृढ़ संकल्प, अटल विश्वास और मेहनती स्वभाव हम सभी के लिए आदर्श होंगे। ✶

जनता के मुक्ति संग्राम की अगुवाई करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर जाने वाले

कॉमरेड वीरेश (सूर्यम/प्रकाश/जीवन) और नंदा (जगदीश) की शहादत को ऊंचा उठाओ!

9 मई 2010 को ओड़िशा के कोरापुट जिले के नारायणपटना इलाके में दुश्मन द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पीएलजीए की सेन्ट्रल रीजनल कम्पनी के राजनीतिक कमिस्सार कॉमरेड सूर्यम (वीरेश) और उनके गार्ड कॉमरेड नंदा (जगदीश) शहीद हो गए। नारायणपटना में जारी आदिवासी किसानों का संघर्ष देश की तमाम जनता का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। इस संघर्ष को कुचलने के लिए सरकारें घोर दमनचक्र चला रही हैं। ऐसी स्थिति में उस संघर्ष की मदद में हमारी केन्द्रीय कमेटी ने कॉमरेड सूर्यम की अगुवाई में पीएलजीए की रीजनल कम्पनी-1 को वहां पर भेज दिया। छह महीनों तक हमारी पीएलजीए ने दुश्मन के नाक में दम करके रख दिया। कॉमरेड सूर्यम की अगुवाई में प्रधान, माध्यमिक और आधार बलों द्वारा किए गए एक हमले में एक एसओजी जवान मारा गया जबकि 17 घायल हो गए थे। पीएलजीए बलों के हमलों की बदौलत ही नारायणपटना के किसानों ने अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाया। जमींदारों की फसलों को जब्त कर लिया।

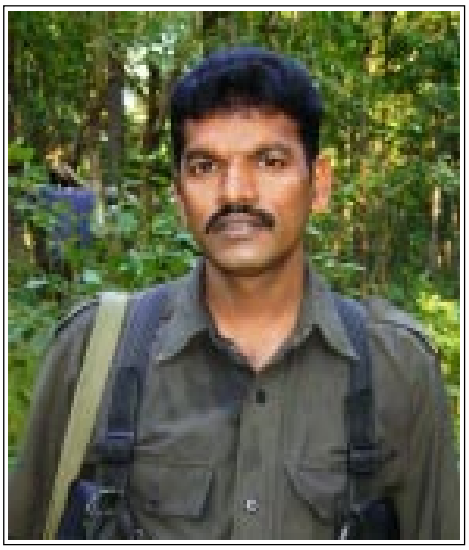

अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर जब कॉमरेड सूर्यम अपनी कम्पनी के साथ लौट रहे थे तब शत्रु बलों ने संघर्ष के गांवों पर हमला शुरू किया। यह खबर पाकर 8 मई 2010 को कॉमरेड सूर्यम ने अपनी कम्पनी के साथ दुश्मन पर ऐम्बुश की योजना बनाई। कुछ देर लड़ाई के बाद हमारे कॉमरेडों ने दुश्मनों की बड़ी संख्या, प्रतिकूल भौगोलिक धरातल और दुश्मन की फॉर्मेशन को देखते हुए पीछे हटने का फैसला लिया। पीछे हटने के दौरान कॉमरेड सूर्यम के साथ तीन कॉमरेड अलग हो गए। अगले दिन की सुबह जब वे तयशुदा मिलन-स्थान पर जा रहे थे तब वे दुश्मन के एम्बुश में फंस गए। दुश्मन का मुकाबला करने के दौरान कॉमरेड जगदीश मौके पर ही शहीद हो गए जबकि कॉमरेड सूर्यम बुरी तरह घायल हो गए। फिर भी उन्होंने पूरा जोर लगाकर 10 मीटर तक रेंगते हुए एक पहाड़ी के टीले पर पहुंच गए। लेकिन वहां से आगे बढ़ना मुश्किल हुआ तो फिसलकर नीचे गिर गए। ज्यादा खून बहने से कुछ देर बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। साथियों को इन दोनों के शव 17 मई को मिल गए। क्रांतिकारी जनता और पीएलजीए के साथियों ने नम आंखों से दोनों कॉमरेडों का अंतिम संस्कार किया। लम्बे अरसे से पार्टी में काम करते हुए कदम-ब-कदम तरक्की करने वाले कॉमरेड सूर्यम की मौत हमारी पार्टी के लिए, खासकर सेन्ट्रल रीजनल कमान के लिए तथा पीएलजीए के कतारों के लिए बड़ा नुकसान है। आइए, दुश्मन के साथ दो-दो हाथ करते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले कॉमरेड्स सूर्यम और जगदीश को विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि पेश करें।

41 वर्षीय सूर्यम का जन्म आंध्रप्रदेश के करनूल जिले के आदोनी मण्डल के तहत आने वाले ग्राम कड़ितोटा में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एल्लैया है। माता-पिता ने सूर्यम का नाम 'वीरेश' रखा था। उनके एक भाई और एक बहन हैं। जब वे छोटे थे तभी गरीबी के कारण वीरेश का परिवार 1978 में गुंटूर शहर के पास एटुकूर गांव में आ बसा था। उनके पिताजी शहर के एक काटन मिल में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। उन दिनों गुंटूर में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज थीं। बस्तियों में रैडिकल युवा संगठन के कामकाज चलते थे। वीरेश अपने पिता और भाई के साथ-साथ काटन मिल में काम करते हुए ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। इस तरह उन्होंने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उन्होंने उस समय क्रांतिकारी गीत सुनते हुए और खुद गरीबी में पैदा होने के कारण समाज में जारी शोषण को समझ लिया। समाज में जारी शोषण-उत्पीड़न को खत्म करने के लिए क्रांति ही एक मात्र रास्ता है, इस सच्चाई को समझते हुए उस दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला लिया। तभी से उन्होंने रैडिकल युवा संगठन की क्रियाकलापों में भाग लेना शुरू किया। 1987 में पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर पार्टी में शामिल हो गए।

शुरू में गुंटूर शहर में ही युवा संगठन का काम किया। 'प्रकाश' के नाम से युवाओं को गोलबंद करने की कोशिश की। अनुशासनप्रिय और कम बोलते हुए ज्यादा काम करने का स्वभाव वाले कॉमरेड प्रकाश को 1987 के आखिर में जिला कमेटी सचिव के कुरियर नियुक्त किया गया। 1985 में एनटीआर सरकार ने हमारी पार्टी पर अघोषित युद्ध चलाया था, जिसका असर गुंटूर जिले में भी देखा गया। उस दमन के माहौल में कॉमरेड प्रकाश ने समय का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया।

नल्लमला के जंगलों को लाल बनाने के प्रयास में...

1989 में हमारी पार्टी ने नल्लामला क्षेत्र में गुरिल्ला जोन बनाने के लक्ष्य से कार्यकर्ताओं को भिजवाने का फैसला लिया। हालांकि ऐसी कोशिशें एक दशक से चल रही थीं, लेकिन सफल नहीं हो पाईं। इसलिए पार्टी ने मजबूत कैडरों और ग्रामीण इलाकों में टिककर काम करन वाले कैडरों को चुनकर जंगलों में भेज दिया। इसके तहत 1989 के मध्य में कॉमरेड प्रकाश को एक संगठनकर्ता के साथ पुल्ललचेरवू इलाके में भेजा गया था। तबसे लेकर नल्लामला के जंगलों को क्रांति का गढ़ बनाने के लिए जारी अविराम परिश्रम में कॉमरेड प्रकाश ने दस्ता सदस्य के रूप में, कमाण्डर के रूप में और डिवीजनल कमेटी सदस्य के रूप में आदर्शपूर्ण भूमिका निभाई।

नल्लामला जंगलों में जब उन्होंने कदम रखा था, तभी तेंदुपत्ता संघर्षों में हासिल जीत के प्रभाव से गांवों में जनता से व्यापक सम्बन्ध स्थापित हो गए। दूसरी ओर वन विभाग के अधिकारियों के जुल्म-अत्याचारों के खिलाफ सभी इलाकों में व्यापक संघर्ष फूट पड़े। पुल्ललचेरवू इलाके में भी वन अधि कारियों को जनता की अदालतों में पेश कर उन पर जन सुनवाइयां आयोजित की गईं। इन सब में कॉमरेड प्रकाश ने उत्साह के साथ भाग लिया। इससे जनता से वसूले जाने वाले हर प्रकार के जुर्मानों से छुटकारा मिल गया। शराब बंदी को लेकर 1990 के दशक में किए गए संघर्षों में भी कॉमरेड प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन सभी संघर्षों के जरिए जनता में पार्टी की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। इससे जनता का उत्साहित होकर संगठनों में शमिल होना शुरू हुआ। जमींदारों के खिलाफ किए गए जन पंचायतों में भी कॉमरेड प्रकाश ने भाग लिया। वन विभाग के दमन-शोषण को खत्म करने के बाद लोगों ने कई गांवों में जंगल काटकर खेती के लिए जमीनें बना लीं।

हालांकि सरकारी दमन शुरू से ही था, लेकिन ज्यों-ज्यों जनता के संघर्ष बढ़ने लगे थे, दमन की तीव्रता भी बढ़ने लग गई। उस समय पार्टी के संगठनकर्ता के साथ सुरक्षा की दृष्टि से एक ही सदस्य रहा करते थे। जंगली रास्तों को याद रखना, रात में भी बिना लाईट लिए चलना और संगठनकर्ता के लिए गांव में जाकर खाना लाना, घण्टों संतरी करना आदि कामों में कॉमरेड प्रकाश उत्साह से भाग लेते थे। वह खुद ही गांवों में घर-घर जाकर लोगों व जन संगठन कार्यकर्ताओं को जंगल में ले आते थे। इस तरह गांवों में घर-घर के साथ कॉमरेड प्रकाश का परिचय काफी बढ़ गया। वह जनता का चहेता बन गए। खासकर दलित बस्तियों में उन्हें लोग बेहद पसंद करते थे जहां पार्टी का प्रभाव ज्यादा था। धीरे-धीरे उनकी टीम दस्ते में तब्दील हो गई और सहज ही वह उस दस्ते के उप-कमाण्डर बनाए गए। 1993 में एक कार्रवाई के लिए गए उनके कमाण्डर के गिरफ्तार हो जाने से बाद में उन्हें दस्ता कमाण्डर बनाया गया।

इस तरह गुरिल्ला दस्तों के प्रवेश से नल्लमला के किनारे पर स्थित पुल्ललचेरवू इलाके में तथा गुंटूर जिले के पलनाडु इलाके में भी हमारी पार्टी के नेतृत्व में जन संघर्ष तेज हुए। तेंदुपत्ता संघर्ष, शराब बंदी संघर्ष, जंगल व बंजर जमीनों को कब्जाने वाले संघर्ष आदि के अलावा गुंटूर जिले के दाचेपल्ली इलाके के रामापुरम गांव में एक बड़ा संघर्ष फूट पड़ा था। वहां के दलितों ने हमारी पार्टी की अगुवाई में जमींदारों का सफाया किया। इसके अलावा शिरिगिरिपाडू गांव के जमींदारों के खिलाफ भी जन संघर्ष उठा था। इस पृष्ठिभूमि में सरकार ने दमन में बढ़ोत्तरी की। तेलंगाना क्षेत्र में क्रूरता का पर्याय बन चुके पुलिस अधिकारियों को इस इलाके में लाकर दमन बढ़ाया गया। 1 अप्रैल 1992 में एसपी आरपी मीणा के नेतृत्व में पुलिस वालों ने हमारे तीन कॉमरेडों और चार मछुवारों की हत्या कर मुठभेड़ की कहानी गढ़ दी। हमले बढ़ गए। जनता में दहशत का माहौल बन गया। ऐसे समय में दमन के बीचोबीच भी जनता को गोलबंद करते हुए अकाल की समस्या को लेकर संघर्ष चलाया गया। इस संघर्ष में कॉमरेड प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दोरनाला इलाके में रजक समाज के लोगों से ऊंची जाति के जमींदार बेगारी करवाते थे। इसके खिलाफ कॉमरेड प्रकाश ने जन संघर्ष का नेतृत्व किया। जनता को व्यापक रूप से गोलबंद कर धरना-प्रदर्शनों को आयोजित करवाया। इस संघर्ष से उन्हें बेगारी से मुक्ति मिल गई। इस तरह उन लोगों के दिलों में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। इसी इलाके के कुछ गांवों में ऊंची जाति के जमींदारों ने दलितों का गांव निकाला कर दिया तो कॉमरेड प्रकाश ने दलितों के समर्थन में सभी जातियों के लोगों को एकजुट कर छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया। कई जमींदारों के सिर झुकाकर सरेआम दलितों से माफी मंगवाई ताकि दलितों का आत्मसम्मान बढ़ सके। कुछ कट्टर जमींदारों का उस दौरान खात्मा भी किया गया।

नल्लमला क्षेत्र में चेंचू आदिवासियों की समस्याओं को लेकर भी उन्होंने संघर्ष का निर्माण किया। दोरनाल कस्बे में एक जुलूस निकला गया था जिसमें दर्जनों गांवों से चेंचू आदिवासियों ने भाग लिया। इसके पीछे कॉमरेड प्रकाश का योगदान रहा। शिक्षा, अस्पताल, वनोपजों को वाजिब दाम, गांवों में नलकूप आदि हासिल करने के लिए आदिवासियों ने कई संघर्ष किए। इस इलाके में दुश्मन ने क्रांतिकारी आंदोलन का उन्मूलन करने की मंशा से बड़े पैमाने पर मुखबिर तैयार करने की साजिश की। इसे विफल करते हुए कई मुखबिरों और जनता के कट्टर दुश्मनों का सफाया करने और उन्हें काबू करने में कॉमरेड प्रकाश का योगदान रहा।

टाइगर प्राजेक्ट इलाके में सामंत-विरोधी संघर्ष को तेज करते हुई कई गांवों में जमींदारों की पट्टा जमीनों और मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने के लिए कॉमरेड प्रकाश ने किसानों को गोलबंद किया। कई जमीन संघर्षों का उन्होंने नेतृत्व किया। ऊंची जाति के जमींदारों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ भी कॉमरेड प्रकाश ने जनता को, खासकर महिलाओं को गोलबंद किया। ऐसे कुछ जालिम जमींदारों का

सफाया कर उनकी सारी सम्पत्तियों को जब्त कर जनता के हवाले करने की कार्रवाइयों का भी कॉमरेड सूर्यम ने नेतृत्व किया। इस दौरान महिला टीमों का गठन कर उस इलाके में महिला आंदोलन को मजबूत बनाने का भी उन्होंने काफी प्रयास किया। इसी संदर्भ में 2000 में उन्हें नल्लामला डिवीजनल कमेटी सदस्य के रूप में चुन लिया गया।

गुंटूर जिले में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व

आंदोलन की जरूरतों के हिसाब से उन्हें 2002 में गुंटूर जिले में स्थानांतरित किया गया था। वहां चंद्रावंका एरिया कमेटी की जिम्मेदारी के साथ-साथ डिवीजनल कमाण्डर-इन-चीफ और रीजनल कमाण्ड सदस्य की जिम्मेदारी भी निभाई। जब कॉमरेड प्रकाश ने जिले में जिम्मेदारी ली, उस समय आंदोलन के अंदर कई गैर-सर्वहारा रुझान पनप चुके थे। उन्हें ठीक करने में कॉमरेड प्रकाश की भूमिका भी रही। उसी समय जिले में वर्ग संघर्ष भी तेज हुआ था। उस समय उस इलाके में कई जन संघर्ष सामने आए। उन्हें संगठित करने और आगे बढ़ाने में कॉमरेड सूर्यम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जन मिलिशिया का निर्माण कर उसे प्रशिक्षित करने में कॉमरेड सूर्यम का योगदान रहा। जिले में कई जन कल्याणकारी कदम भी उठाए गए। 2002 में जन कार्य और फौजी कार्य को तालमेल के साथ संचालित करने के कारण जिला आंदोलन एक कदम आगे बढ़ गया।

2003 में गुंटूर जिले में पहली बार गठित प्लटून के कमाण्डर की जिम्मेदारी कॉमरेड प्रकाश ने ली। 2004 के आखिर में उन्होंने जिला कमेटी सचिव की जिम्मेदारी ली। तबसे जीवन के नाम से उन्होंने पूरे जिले का दौरा करते हुए आंदोलन को विकसित करने का पूरा प्रयास किया। जिले के आंदोलन को गुरिल्ला जोन के स्तर पर विकसित करने में कॉमरेड जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फरवरी 2006 में उन्हें आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी में को-ऑप्ट किया गया था।

2004 में सरकार के साथ वार्ता के संदर्भ में मिले खुले अवसरों का फायदा उठाते हुए पूरे इलाके में हजारों एकड़ पट्टा जमीनों को जमींदारों के कब्जे से मुक्त कर किसानों में बांटने और कई संगठनों में जनता को संगठित करने में कॉमरेड जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने हजारों लोगों को उस समय खुले संघर्षों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उसी समय गुत्तिकोण्डा के पास, जहां कॉमरेड चारु मजुमदार ने एक बैठक की थी, एक ऐतिहासिक स्मारक (65 फुट ऊंचा) बनाने में कॉमरेड जीवन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस स्मारक के पास आयोजित आमसभा में 10 लाख लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा जूलाकल्लू गांव में जिले के अमर शहीदों की याद में एक स्मारक बनाया गया।

फौजी मोर्चे में कॉमरेड सूर्यम की भूमिका

कई फौजी कार्रवाइयों में कॉमरेड सूर्यम ने कमाण्डर के रूप में नेतृत्व किया। पहलकदमी को हमेशा अपने हाथ में रखते हुए उन्होंने कई कार्रवाइयों की योजना बनाई। दुश्मन को समझ में न आए, इस प्रकार ऐम्बुश की योजना बनाने और दुश्मन को हमारे लिए अनुकूल जगह में फंसाने आदि में उन्होंने खासा अनुभव हासिल किया।

पीएलजीए की स्थापना के बाद फरवरी 2001 में चलाए गए पहले कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान (टीसीओसी) के तहत श्रीशैलम व सुन्निपेंटा के सांझे हमले में उन्होंने श्रीशैलम में कमाण्डर की भूमिका निभाई। मई महीने में एर्रागोण्डापालेम के पास किए गए रेड में उन्होंने हमलावर टुकड़ी के कमाण्डर के रूप में नेतृत्व किया। नवम्बर 2001 में नरसरावपेटा के एसएसएन कॉलेज पर हमला कर पुलिस के 30 रायफलें और एक एलएमजी छीनने की कार्रवाई का भी नेतृत्व कॉमरेड प्रकाश ने ही किया था।

2002 में एक पैसेंजर बस में आ रहे पुलिस वालों पर रेमिड़िचरला के पास किए गए हमले का, बोल्लापल्ली थाने पर राकेट लांचर से किए गए हमले का और अड़िगोप्पुला के पास पैदल आ रहे ग्रेहाउण्ड्स बलों पर हमला कर चार भाड़े के बलों का सफाया करने की कार्रवाई का कॉमरेड सूर्यम ने ही नेतृत्व किया था। राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड कारुमंची प्रसाद की फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ 2003 में अद्दंकि पुलिस थाने पर हमला कर 24 हथियार और 5 हजार कारतूस जब्त करने की कार्रवाई का भी कॉमरेड प्रकाश ने ही नेतृत्व किया था।

2004 में मानाला फर्जी मुठभेड़ (जिसमें एक कोवर्ट के कारण 10 कॉमरेड शहीद हुए थे) के विरोध में चिलकलूरीपेटा थाने पर किए गए हमले का भी कॉमरेड सूर्यम ने ही नेतृत्व किया था। इसके अलावा छोटी व मध्यम किस्म की कई कार्रवाइयों का उन्होंने नेतृत्व किया था। कई जन विरोधी होमगार्डों, मुखबिरों, जालिम जमींदारों और दलालों को चिन्हित कर उन्हें दण्डित करने में कॉमरेड जीवन ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई।

इसके अलावा कॉमरेड जीवन ने दर्जनों बार दुश्मन के कई हमलों का मुकाबला किया। कई मुठभेड़ों में उन्होंने अपने बलों का कुशल नेतृत्व किया। कई जगहों पर अपने साथियों को सुरक्षित रूप से रिट्रीट कराने में उनकी पहलकदमी और सूझबूझ अच्छा काम आई। 2004 में पंचायत चुनावों के मौके पर दुश्मन के ऐम्बुश में फंसने से कॉमरेड जीवन को कंधे में गोली लगी थी। फिर भी उन्होंने बिना किसी हड़बड़ाहट के मुकाबला करते हुए ही सभी कॉमरेडों के सकुशल रिट्रीट में मदद की। 2006 में एक बार जब वह राज्य कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए अकेले और निहत्थे जा रहे थे, तब दुश्मन ने एक मुखबिर की पक्की सूचना के आधार पर उन पर फायरिंग की। इसमें भी वह घायल हुए थे। इसके बावजूद भी अपनी पूरी ताकत को बाहर लाते हुए पूरी रात चलकर जनता की मदद से फिर से पार्टी के संपर्क में आ गए थे।

2006 में नल्लामला इलाके में आंदोलन पर दमन ने भयावह रूप ले लिया। राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड माधव के अलावा सदस्य कॉमरेड श्रीधर, राघवुलु जैसे कई नेतृत्वकारी कॉमरेडों के साथ-साथ कई कार्यकर्ता शहीद हो गए। ऐसे मुश्किल भरे समय में भी कॉमरेड जीवन ने बचे हुए कॉमरेडों का ढाढ़स बंधाते हुए दुश्मन के घेराव-उन्मूलन हमलों के बीच ही आंदोलन को टिकाए रखने की पूरी कोशिश की। नुकसानों को सहकर भी दुश्मन से जरा भी खौफ न खाते हुए नल्लामला और गुंटूर जिलों को मिलाकर प्लटून के फॉर्मेशन में रहकर दुश्मन का मुकाबला करते हुए ही जनता के साथ जीवंत सम्बन्ध बनाए रखने की कोशिश की।

सेन्ट्रल रीजियन में राजनीतिक कमिस्सार की भूमिका में कॉमरेड सूर्यम

जून 2007 में कॉमरेड जीवन को सेन्ट्रल रीजियन की पीएलजीए कम्पनी-1 में राजनीतिक कमिस्सार की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने यहां आकर अपना नाम सूर्यम बदल लिया। सेन्ट्रल रीजियन में, जिसमें दण्डकारण्य, आंध्रप्रदेश व ओड़िशा के इलाके आते हैं, जनयुद्ध को तेज करने के लक्ष्य से गठित सेन्ट्रल रीजनल कमान में वह सदस्य बन गए। मूलत: आदिवासी बहुल इस इलाके की कई भाषाओं को सीखने की उन्होंने काफी कोशिश की। हिंदी भी सीखने की उन्होंने पूरी कोशिश की। अपनी कम्पनी में हिंदी सीखने के लिए वह रोज स्कूल जाया करते थे। कोया भाषा पर पकड़ हासिल कर उन्होंने अपनी कम्पनी के कॉमरेडों को क्लास भी बताया।

ऐतिहासिक नयागढ़ हमले में सूर्यम का योगदान

करीब 600 किलोमीटर का पैदल मार्च कर पीएलजीए बलों द्वारा ओड़िशा के नयागढ़ जिला मुख्यालय पर किए गए ऐतिहासिक हमला - 'ऑपरेशन रोप वे' को सफल बनाने के लिए गठित कोर ग्रूप में कॉमरेड सूर्यम भी एक सदस्य थे। इस शानदार हमले ने शासक वर्गों के दिलों में हड़कम्प मचा दी। इसमें कॉमरेड सूर्यम ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी कुशलता से पूरी की। एक तरफ गोसामा में बहादुराना लड़ाई लड़ते हुए ही सैकड़ों हथियारों और हजारों कारतूस को बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंककर काम किया। इस ऑपरेशन के बाद जब रीजनल कम्पनी-2 का निर्माण हुआ तो कॉमरेड सूर्यम को उसमें राजनीतिक कमिस्सार के रूप स्थानांतरित किया गया।

अगस्त 2008 में आयोजित केन्द्रीय फौजी प्रशिक्षण कैम्प में उन्होंने भाग लिया। वहां पर सीखे विषयों पर उन्होंने अपनी कम्पनी के कॉमरेडों और उत्तर तेलंगाना के कॉमरेडों को प्रशिक्षित करने में कॉमरेड सूर्यम की भूमिका रही। जून 2008 में बंडा के पास किए गए हमले और अप्रैल 2009 में ओड़िशा के नाल्को खदानों पर किए गए हमलों में उन्होंने गुरिल्ला बलों का नेतृत्व किया। नाल्को में दुश्मन के साथ 8 घण्टों तक जूझने का अच्छा अनुभव हासिल किया उन्होंने।

नारायणपटना सामंतवाद-विरोधी संघर्ष की रक्षा में

ओड़िशा के नारायणपटना इलाके में पिछले साल सामंतवाद-विरोधी आदिवासी किसान संघर्ष का एक उभार आया। वहां की फासीवादी सरकार ने उसे पाशविकता से कुचलने का फैसला कर बर्बर हमला छेड़ दिया। इस आंदोलन के अहम नेता कॉमरेड सिंगन्ना और कार्यकर्ता कॉमरेड आंद्रु की पुलिस ने क्रूरतापूर्वक हत्या की। इस पृष्ठभूमि में यह स्थिति सामने आई थी कि इस आंदोलन को सशस्त्र किसान आंदोलन में तब्दील किए बिना उसे विकसित करना मुश्किल था। ठीक इसी समय वहां की कुई आदिवासियों के संघर्ष के समर्थन में कॉमरेड सूर्यम की अगुवाई में पीएलजीए की कम्पनी वहं पहुंच गई। नारायणपटना आंदोलन को हथियारबंद समर्थन मिल गया। वहां के प्रधान व माध्यमिक बलों को मिलाकर बनाई गई कमान की उन्होंने अगुवाई की। जमींदारों से छीनी गई जमीनों से जब जनता ने फसलें काटीं तो पीएलजीए के साथियों ने एक घेरा बनाकर जनता को सुरक्षा पहुंचाई। इसमें जनता और जन मिलिशिया की भूमिका को बढ़ाने पर कॉमरेड सूर्यम ने विशेष जोर दिया। जब शत्रु बल रात के समय हमले करने लगे थे तो उसका पलटा जवाब देने के लिए पीएलजीए ने रात के समय ऐम्बुश की योजना बनाई। ऐसी एक कार्रवाई में कॉमरेड सूर्यम के नेतृत्व में हमारे कॉमरेडों ने सूझबूझ के साथ हमला कर दिया जिसमें एसओजी का एक जवान मरा और तीन अन्य बुरी तरह घायल हुए थे। बाकी बल नारायणपटना तक भाग गए। हालांकि यह छोटी सी कार्रवाई ही थी लेकिन उस इलाके की जनता का आत्मविश्वास बढ़ाने में काफी उपयोगी साबित हुई। इसके साथ ही फसलें काट लेने का अभियान सफलता से संपन्न हुआ।

इसके बाद इस इलाके के कत्तुलापेट गांव में शांति सेना के नाम से संगठित हुए प्रतिक्रियावादी गुण्डा गिरोह के खिलाफ कॉमरेड सूर्यम ने जनता को गोलबंद किया। संशोधनवादी पार्टी से जुड़े जमींदारों के खिलाफ सैकड़ों जन मिलिशिया को ले जाकर हमला किया। कई ऐम्बुशों का उन्होंने खुद नेतृत्व किया। नारायणपटना के सामंत-विरोधी आंदोलन से पैदा हुई क्रांतिकारी जन मिलिशिया को फौजी प्रशिक्षण देने में कॉमरेड सूर्यम की पहलकदमी रही।

एक तरफ फौजी कार्रवाइयों का संचालन करते हुए ही केन्द्र-राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ प्रचार कार्यक्रमों को सफल बनाने में भी कॉमरेड सूर्यम का योगदान रहा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सौवीं वर्षगांठ को सफल बनाते हुए नारायणपटना में हजारों लोगों से जुलूस निकाले गए। इस पूरे जन कार्य में कॉमरेड सूर्यम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

1998 में कॉमरेड सूर्यम ने अपने ही दस्ते में काम करने वाली एक कॉमरेड को अपनी जीवन-संगिनी बनाई। इन दोनों की जोड़ी ने पार्टी और जनता के हितों को हमेशा ऊंचा उठाते

हुए ही वैवाहिक जीवन बिताया। कॉमरेड सूर्यम अपनी जीवन-साथी का हर पहलू में सहयोग करते थे।

सूर्यम के आदर्शों को ऊंचा उठाएं!

कॉमरेड सूर्यम सीधे-सादे इंसान थे। वह जहां भी रहे जनता और कैडरों के साथ घुलमिलकर रहे। हमेशा उनका विश्वास हासिल किया। वह जिस इलाके में भी गए वहां की परिस्थितियों के बारे में समझने-जानने की पूरी कोशिश करते थे। जनता की जीवन परिस्थितियों और संघर्ष की चेतना का अध्ययन करते थे। आदिवासी भाषाओं को समझने-सीखने की पूरी कोशिश की। वह श्रम का सम्मान करते थे। वह खुद मेहनत करते हुए दूसरों को इसके लिए प्रोत्साहित करते थे। गुरिल्ला जिंदगी में हर मुश्किल का उन्होंने मुस्कराते हुए सामना किया। जहां कठिनाई है, वहां चाहकर जाते थे। कॉमरेड सूर्यम ने कम्युनिस्ट मूल्यों और संस्कृति को हमेशा ऊंचा रखा, साम्राज्यवादी व सामंती संस्कृति के खिलाफ निर्मम संघर्ष किया। कैडरों के साथ वह घुलमिलकर रहते थे। महिला कॉमरेडों के साथ उनका व्यवहार सम्मानपूर्वक रहता था। उनके विकास के लिए वह हमेशा प्रयास करते थे।

कॉमरेड सूर्यम एक अच्छे आलोचक है। अपनी गलतियों पर आत्मालोचना करने और साथियों की गलतियों की आलोचना करने में वह आगे रहा करते थे। आज सूर्यम की मौत से पार्टी ने एक साहसिक कमाण्डर, आदर्शपूर्ण राजनीतिक कमिस्सार, एक उन्नत श्रेणी के कम्युनिस्ट और एक स्नेहिल इंसान को खो दिया। उनके दिखाए रास्ते में आगे बढ़ते हुए संघर्ष को अविश्रांत जारी रखेंगे, वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजली होगी।

कॉमरेड कल्मा नंदा

दण्डकारण्य के दंतेवाड़ा जिले के ऊसूर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मुरकुम में कॉमरेड नंदा पैदा हुए थे। गरीब आदिवासी

परिवार में जन्मे कॅमरेड नंदाल के पिता कॉमरेड कल्मा लिंगाल हैं। वह एक समय डीएकेएमएस में रेंज कमेटी सदस्य की जिम्मेदारी में थे। गिरफ्तार होकर दंतेवाड़ा जेल में दो साल बिताए थे। जेल से छूटने के बाद भी वह क्रांतिकारी क्रियाकलापों में लगे रहे। बल्कि अपने बच्चों को भी उन्होंने प्रोत्सहित किया। इसके तहत ही नंदाल जो गंगनपाडू गांव में एक धनी किसान के घर में नौकर के रूप में काम करता था, बाल संगठन में शामिल हो गए। बाद में 2005 में वह मिलिशिया में सदस्य बन गए क्योंकि उन्होंने सलवा जुडूम के खिलाफ लड़ने की ठान ले रखी थी।

सलवा जुडूम के गुण्डों के जुल्म और आतंक को प्रत्यक्ष देखने वाले कॉमरेड नंदाल के दिल में उनके खिलाफ गुस्से की आग भड़कती थी। जहां भी दुश्मनों के आने का समाचार मिलता तो वह अपने तीर-धनुष लेकर तैयार हो जाते थे ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। दिसम्बर 2006 में उन्हें पीएलजीए में सदस्य के रूप में भर्ती किया गया। पहले उन्हें ऊसूर दस्ते में सदस्य के रूप में रखा गया था। जनवरी 2007 में कॉमरेड नंदाल को पार्टी सदस्यता प्रदान की गई। अप्रैल 2008 में उन्हें पार्टी ने रीजनल कम्पनी-2 में स्थानांतरित किया।

कॉमरेड जगदीश की अनुशासनप्रियता और राजनीतिक-फौजी चेतना को देखते हुए उन्हें कम्पनी के सचिव कॉमरेड सूर्यम के गार्ड रूप में रखा गया। कॉमरेड जगदीश अपने जिम्मेवार कॉमरेड सूर्यम को हर प्रकार का सहयोग देते थे। उनसे बहुत कुछ सीखते थे। जहां भी मौका मिला तो दुश्मन के खिलाफ हमलों में उत्साह के साथ भाग लेते थे। बंडा के पास हुए ऐम्बुश में उन्होंने गॉर्ड के रूप में अपनी भूमिका निभाई। दामनजोड़ी (नाल्को) में किए गए हमले में भी कॉमरेड जगदीश ने अपने जिम्मेवार कॉमरेड के साथ गार्ड की भूमिका निभाते हुए ही हमलावर टुकड़ी में रहकर लड़ाई में बहादुराना ढंग से भाग लिया। दिसम्बर 2009 में कोरापुट जिले के नारायणपटना इलाके में दाइगूड़ा के पास किए गए ऐम्बुश में भी उन्होंने भाग लिया।

इसके अलावा मुखबिरों, जमींदारों और क्रांति के दुश्मनों पर किए गए कई हमलों और सफाया कार्रवाइयों में कॉमरेड जगदीश ने बहादुरी से भाग लिया। कॉमरेड जगदीश अनुशासनप्रिय योद्धा थे। हर विषय को सीखने में वह उत्सुकता दिखाया करते थे। हमलों में रनर के रूप में अच्छी भूमिका निभाई ताकि बलों के बीच तालमेल बिठाया जा सके। हमलों के दौरान कम्युनिकेशन के जिम्मेवार कॉमरेड को भी वह सहयोग देते थे। नारायणपटना क्षेत्र की जनता के न्यायपूर्ण संघर्ष के समर्थन में बस्तरिया माटी-पुत्र कॉमरेड जगदीश ने भी अपनी भूमिका निभाई। जमींदारों से जब्त जमीनों में फसलें काटने में उन्होंने जनता का सहयोग किया। जनता की सुरक्षा में उन्हों जी-जान लगाया। सक्रियता, साहस, अनुशासन, दृढ़ संकल्प आदि कॉमरेड जगदीश के अच्छे गुणों को पीएलजीए के तमाम कतारों को आदर्श के रूप में लेना चाहिए। आइए, कॉमरेड जगदीश के अधूरे मकसद को पूरा करने की कसम खाएं। ✶

पाठकों से सम्पादकमण्डल की अपील

- **'प्रभात' के लिए रिपोर्टें नियमित रूप से भेजें।**
- **शहीदों की जीवनियां समय पर भेजें।**
- **सरकारी ग्रीन हंट अभियान में मारे जाने वाले लोगों के ब्यौरे भेजें।**
- **पत्रिका पर अपनी राय-सुझाव भेजें।**

दण्डकारण्य आंदोलन की पहली पीढ़ी की महिला नेता
कॉमरेड मड़ावी रामक्का (अनिता/शारदा) को लाल-लाल सलाम!

दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन की पहली पीढ़ी की महिला नेताओं में से एक कॉमरेड मड़ावी रामक्का (शारदा) का गंभीर बीमारी के चलते 29 जून 2010 की मध्यरात्री में आकस्मिक निधन हो गया। मुश्किलों से भरी लम्बी क्रांतिकारी जिंदगी के कारण बीमार होकर वह काफी समय से परेशान थीं। अपनी अस्वस्थता की परवाह किए बगैर ही वह क्रांतिकारी कामकाज में लगातार शिरकत करती आ रही थीं। पार्टी ने जहां तक संभव हो उनका इलाज करवाने की काफी कोशिश की। बीच में कॉमरेड रामक्का थोड़ी बेहतर हुई भी थीं, लेकिन पिछले कुछ समय से फिर से गंभीर अस्वस्थता का शिकार हुई थीं। आखिरकार वही उनकी मौत का कारण बना। उस कैम्प में, जिसमें उनके जीवनसाथी के अलावा कई नेतृत्वकारी कॉमरेड्स और दूसरे कॉमरेड्स मौजूद थे, सभी को गम में डुबोते हुए 29 जून की रात में उन्होंने अंतिम सांस ले ली। उन्हें बचाने के लिए की गई सारी कोशिशें विफल हुईं। उस इलाके की जनता, छापामार साथी और जनताना सरकार के नेताओं - सभी ने मिलकर उन्हें क्रांतिकारी सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। सैकड़ों लोगों के मुंह से निकले 'कॉमरेड शारदक्का अमर रहें' के बुलंद नारों के बीच उनकी चिता को अग्नि दी गई। सभी ने कॉमरेड शारदा के अधूरे मकसद को पूरा करने की कसम खाई। अगले दिन 1 जुलाई को आयोजित श्रद्धांजली सभा में पार्टी नेताओं और कई कार्यकर्ताओं ने क्रांतिकारी आंदोलन में करीब पच्चीस बरसों से कॉमरेड शारदक्का द्वारा दी गई सेवाओं को याद करते हुए अपनी बात रखी।

कॉमरेड शारदा का जन्म महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले के अहेरी तहसील में आने वाले गांव गुड्डिगूड़ेम में 1962 में हुआ था। वह गरीब किसान परिवार से थीं। माता-पिता की कुल पांच संतानों में वह तीसरी थीं। कॉमरेड शारदा की मौत से दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन ने एक अनमोल क्रांतिकारी को खो दिया जिसने दो दशकों से ज्यादा समय से पेशेवर क्रांतिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दीं। जबसे यहां क्रांतिकारी आंदोलन की शुरूआत हुई, तभी से क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन की गतिविधियों का हिस्सा बनकर, उसे आज की स्थिति में लाने के लिए नींव रखने वाले प्रमुख कॉमरेडों में कॉमरेड रामक्का एक थीं। उनकी शहादत से खासकर क्रांतिकारी महिला आंदोलन को बड़ा नुकसान हुआ है। 1980 के दशक के आखिर से ही दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने वाली कॉमरेड रामक्का 1988 तक एक सक्रिय कार्यकर्ता बनी थीं। जल्द ही वह कमलापुर रेंज कमेटी सदस्या के रूप में चुन ली गई थी। केएएमएस संगठनकर्ता के साथ घूमते हुए उन्होंने क्रांतिकारी महिला आंदोलन के विकास के लिए प्रयास किए। 1990 से पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनने वाली कॉमरेड रामक्का पार्टी की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थीं जिन्होंने महिला संगठन की संगठतकर्ता के रूप में, पार्टी की एरिया कमेटी सदस्या व सचिव के रूप में विभिन्न जिम्मेदारियों में 'अनितक्का' और 'शारदक्का' के नाम से गढ़चिरौली (महाराष्ट्र), माड़ (छत्तीसगढ़), श्रीकाकुलम (आंध्रप्रदेश) और मलकनगिरी (ओड़िशा) के विभिन्न इलाकों की जनता के बीच काम किया।

पहले पहल उन्होंने गढ़चिरौली जिले में क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन में काम कर उसके विकास में अपना योगदान किया था। अहेरी इलाके से क्रांतिकारी आंदोलन में आकर्षित हुई पहली पीढ़ी की महिला नेत्री थीं कॉमरेड रामक्का। कई बार प्रचार कैम्पेन चलाकर गांवों में क्रांति का प्रचार-प्रसार कर, विशेषकर महिलाओं को क्रांतिकारी आंदोलन में जोड़ने में कॉमरेड रामक्का ने उल्लेखनीय कार्य किया। 1980 में, आंदोलन के शरूआती समय में ही कॉमरेड पेद्दि शंकर की गोली मारकर हत्या कर लुटेरे शासक वर्गों ने यह सपना देखा था कि इससे वे क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार को रोक सकेंगे। कॉमरेड पेद्दि शंकर की शहादत और उनके द्वारा फैलाए गए क्रांति के संदेश को गांव-गांव में सुनाते हुए शहीदों के मकसद की पूर्ति करने का प्रचार करने में कॉमरेड रामक्का ने भाग लिया। सालों से जारी वन विभाग वालों के जुल्मों और अत्याचारों को खत्म करने में, पेपरमिल प्रबंधन की लूटखसोट व महिलाओं पर हो रहे यौन शोषण के खिलाफ जनता को संगठित करने में तथा जन संघर्षों को संचालित करने में कॉमरेड रामक्का अग्रिम पंक्ति में डटी रहीं। खासकर वन विभाग के अधिकारी आदिवासी महिलाओं को अपने कब्जे में रखकर उनका यौन शोषण करते थे। इसके खिलाफ संगठन के नेतृत्व में संघर्ष किया गया जिसमें कॉमरेड शारदा की नेतृत्वकारी भूमिका रही। पेपरमिल के मजदूरी दामों में बढ़ोत्तरी के लिए किए गए संघर्षों में गढ़चिरौली जनता ने कई बार कामयाबियां हासिल कीं। इस दौरान पार्टी के लिए कोष जुटाने के लक्ष्य से सामने आए 'वर्क डे' (श्रम दिवस) परम्परा

को जनता में स्थापित कर पार्टी के लिए एक दिन का सामूहिक श्रम करने की प्रेरणा देने वाले कॉमरेडों में रामक्का एक थीं। इसके अलावा कई अन्य कामों में मजदूरी दर बढ़ाने के लिए किए गए जन संघर्षों में कॉमरेड रामक्का आगे रहीं। गढ़चिरौली जिले में क्रांतिकारी आंदोलन को जड़ें जमाने से रोकने और अपनी सामंती पकड़ को ढीला पड़ने से बचाने के लिए उस समय के अहेरी महाराजा विश्वेश्वरराव ने कई साजिशें की थीं। उन्हें पराजित कर जनता पर जारी उनके जुल्म-शोषण के खिलाफ किए गए संघर्षों में कॉमरेड रामक्का का योगदान रहा। इस तरह अहेरी इलाके में किए गए तमाम सामंत-विरोधी व साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्षों में जनता को, खासकर महिलाओं को गोलबंद करने में कॉमरेड रामक्का ने सक्रिय भूमिका निभाई। राज परिवार के धर्माराव आत्रम ने कॉमरेड शारदा पर सरेंडर करने का काफी दबाव डाला था। लेकिन कॉमरेड शारदा ने उसे विफल कर दिया।

घर में रहते समय में ही पार्टी सदस्यता पाकर सेल सदस्या बनने वाली कॉमरेड रामक्का ने एक तरफ जन संगठन की गतिविधियों को सक्रियता से संचालित करते हुए ही दूसरी तरफ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी समर्पण की भावना के साथ पूरा किया। इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं को पार्टी में भर्ती करवाया। उस क्षेत्र की जनता को शारदा पर इतना विश्वास था कि डीएकेएमएस के रहने के बावजूद लोग हर प्रकार की समस्याओं को लेकर शारदा के पास ही जाया करते थे।

बाद में 1990 में पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन गईं। तबसे उन्होंने अपना नाम 'अनिता' बदल लिया। पहले कमलापुर इलाके में केएएमएस की सांगठनिक जिम्मेदारी उठाई थी। बाद में जिम्मलगट्टा इलाके में भी उन्होंने केएएमएस की संगठनकर्ता के रूप में काम किया था। सादे कपड़ों में निहत्थे ही गांवों में घूमती थीं। एक बार उनकी तीन सदस्यीय टीम एक गांव में ठहरी हुई थी तो एक मुखबिर ने पुलिस को इत्तला दिया था। पुलिस ने गांव में छापा मारा और घर-घर की तलाशी ली। वे तीनों गांव में ही थीं, लेकिन जनता ने उन्हें बचा लिया। इस तरह संगठन के काम पर घूमते समय वह कम से कम तीन बार दुश्मन के हाथों में पड़ने से बच गईं। बल्कि जनता ने उन्हें बचा लिया।

गरीबी के चलते बचपन से कुपोषण की शिकार कॉमरेड अनिता शारीरक रूप से काफी कमजोर रहती थीं। पतली सी व लम्बी सी दिखने वाली कॉमरेड अनिता में क्रांति के लक्ष्य के प्रति अटल प्रतिबद्धता थी। बचपन में पढ़ाई-लिखाई से वंचित कॉमरेड अनिता ने पार्टी में भर्ती होने के बाद दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ना-लिखना सीख लिया। 1990 में कॉमरेड अनिता ने पार्टी में केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड से शादी की।

पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में भर्ती होने के थोड़े ही समय बाद वह माड़ डिवीजन में स्थानांतरित की गई थीं। पहले एसजेडसी के विशेष दस्ते में काम करने के बाद सांगठनिक काम में आई थीं जिसमें उन्होंने 1996 तक वहां की माड़िया जनता को, खासकर महिलाओं को संगठित करने के कार्यों में हिस्सा लिया। 'सभ्यता' से कोसों दूर फेंक दिए जाने वाले माड़ इलाके की जनता के बीच क्रांतिकारी आंदोलन के निर्माण के प्रयास किए। मुख्य रूप से माड़िया समाज में प्रचलित महिलाओं के बलपूर्वक विवाहों के खिलाफ जनता को सचेतन करने में कॉमरेड अनिता ने बेहतरीन भूमिका निभाई। कबीलाई रीति-रिवाजों के तहत महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय का विरोध करने के लिए उन्होंने महिलाओं को एकजुट किया। माड़ इलाके में क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन के निर्माण की नींव रखने में कॉमरेड अनिता ने काफी मेहनत की। माड़ इलाके में पार्टी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को सफल बनाने की खातिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर काम किया।

1996 से 1999 तक आज के पूर्व बस्तर डिवीजन के कोण्डागांव इलाके में एरिया कमेटी सदस्या के तौर पर काम किया। बाबा बिहारीदास द्वारा इस इलाके के आदिवासियों को कई किस्म के प्रलोभन देकर हिंदू धर्म में आकर्षित कर आदिवासी संस्कृति को छिन्न-भिन्न करने का षड़यंत्र जारी था। इसके खिलाफ किए गए जन संघर्षों में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। भक्ति के नाम से आदिवासी युवतियों को गुमराह कर वहशीपन का शिकार बनाए जाने के खिलाफ महिलाओं को गोलबंद कर नाहकानार गांव में बाबा बिहारीदास को जनता के सामने लाकर गलती मनवाने की घटना में कॉमरेड अनिता शामिल थीं। कन्हारगांव में सुकडाल नामक मालगुजार के खिलाफ लड़कर करीब 150 एकड़ जमीन छीनकर जनता में बांटने के लिए किए गए संघर्ष में कॉमरेड अनिता ने जनता का नेतृत्व किया। वेडमाकोट गांव में तहसीलदार श्रीमाली और भाजपा नेता बालसाय वड्डे द्वारा आदिवासी महिलाओं पर किए जा रहे यौन शोषण और अत्याचार के खिलाफ जनता को, खासकर महिलाओं को एकजुट कर जन अदालत लगाकर उन्हें दण्डित करने की घटना में कॉमरेड अनिता ने एसी सदस्या के रूप में जिम्मेदारी के साथ काम किया। तेंदुपत्ता मजदूरी बढ़ाने के लिए किए गए संघर्षों में जनता को गोलबंद करने में कॉमरेड अनिता ने काफी प्रयास किया। ग्राम नरिया में लकड़ी कटवाकर ले जा रहे वन अधिकारियों के खिलाफ जनता को एकजुट करने में कॉमरेड शारदा ने योगदान किया।

1999 में पार्टी ने कॉमरेड अनिता को आज के आंध्र-ओड़िशा बार्डर स्पेशल जोन के श्रीकाकुलम डिवीजन में तबादला किया था। वहां पर उन्होंने उद्दानम इलाके की जनता में काम करते हुए वहां की भाषा को सीखने की कोशिश की। दस्ते में उप कमाण्डर की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने जनता का प्यार व विश्वास हासिल किया। वर्ष 2000 के आखिर तक श्रीकाकुलम डिवीजन में काम करने वाली कॉमरेड शारदा ने 2000 में आयोजित पूर्व रीजियन के पार्टी अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उसके बाद एओबी एसजेडसी

(शेष पेज 10 में...)

शोषणविहीन समाज के नव 'प्रभात' के लिए जारी संघर्ष में सरकारी आतंक की शिकार हुई कॉमरेड चैते को लाल सलाम!

17 अगस्त 2010 का दिन। देश को कथित रूप से मिली आजादी की 63वीं वर्षगांठ के जश्न का शोरगुल पूरी तरह थमा ही नहीं था। लाल किले से प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग की रटी-रटाई घोषणा कि 'मैं फिर एक बार माओवादियों से अपील करता हूं कि वे हिंसा छोड़कर सरकार के साथ वार्ता के लिए आएं...' अभी बासी पड़ी ही नहीं थी। इधर, बाहरी दुनिया के लिए 'अबूझ' माने जाने वाले माड़ अंचल के एक गांव के नजदीक जंगल में दस दिनों से एक हत्यारा गिरोह अपने 'शिकार' की ताक में बैठा हुआ था। इस गिरोह को प्रधानमंत्री की घोषणा से कोई लेना-देना नहीं और उसे इस घोषणा पर माओवादियों की प्रतिक्रिया का इंतजार भी नहीं था। इनका काम है बस, अपने 'शिकार' पर पंजा मारना। दरअसल यह खुद प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ग्रीन हंट का ही हिस्सा है। इसके तहत अगस्त 2009 से अब तक दण्डकारण्य में 150 से ज्यादा लोगों की जानें गईं और खूब सारी तबाही हुई। लेकिन माओवादियों से 'हिंसा छोड़ने' की 'अपील' पता नहीं इसके पहले कितनी बार की गई होगी। नक्सलवादियों को हिंसा छोड़ने की नसीहत देने वाले शासक अपने पुलिस, एसपीओ, मुखबिरों और अन्य पालतू गुण्डों के जरिए इन दूर-दराज के आदिवासी बस्तियों पर किस तरह हिंसा, आतंक और बर्बरता का कहर बरपा रहे हैं, इसे समझने के लिए 17 अगस्त की घटना एक ताजा उदाहरण है।

केसा बहरा (गांव कुत्तुल); दल्लू उर्फ अजय (गांव फरसबेड़ा); दुरगा, कोतवाल और बण्डू (गांव कोहकामेट्टा) इन पांच एसपीओ का हत्यारा गिरोह नारायणपुर जिला एसपी राहुल भगत के दिशा-निर्देश पर निकला हुआ था। इनके निशाने पर था दण्डकारण्य आंदोलन में अहम योगदान करने वाली प्रेस यूनिट। यह यूनिट जनता के समर्थन से व सक्रिय सहयोग से पिछले कई सालों से क्रांतिकारी पत्र-पत्रिकाओं की छपाई करती आ रही है। इस यूनिट पर चोट करके दण्डकारण्य के संघर्ष को नुकसान पहुंचाने की मंशा से इस गिरोह को उनके आकाओं ने यह 'टास्क' दिया। यह साजिश दरअसल डीजीपी विश्वरंजन, आईजी लांगकुमेर आदि बड़े अफसरों द्वारा रची गई है जिसे अंजाम देने के लिए इन भाड़े के गुण्डों व बेहद ओछी किस्म के दरिंदों को चुन लिया गया।

ये पांचों भी माड़ के ही निवासी थे। अपने गांवों में हत्या, बलात्कार, चोरी समेत कई अपराधों में शामिल इन असामाजिक व लम्पट तत्वों को जनता ने अलग-अलग समय में जन अदालतों में सजा देना चाहा तो ये भागकर पुलिस के शरण में चले गए थे। तबसे ये दरिंदे नारायणपुर व ओरछा में रहते हुए लोगों को गिरफ्तार करवाना, पुलिस से मारपीट करवाना, मुखबिर तैयार करना आदि प्रति-क्रांतिकारी हरकतों में लिप्त रहे हैं। इन्होंने दूर-दराज के गांवों में भी अपनी यारी-रिश्तेदारी के आधार पर कुछ लोगों को बहला-फुसलाकर और पैसों का प्रलोभन देकर मुखबिर बना लिया है। इस तरह पोदमगोटी और ऊसेवाड़ा गांवों के कुछ स्थानीय मुखबिरों के सहयोग से इन लोगों ने प्रेस यूनिट को निशाना बनाया। चूंकि स्थानीय मुखबिरों को इस यूनिट के कैम्प की पूरी जानकारी थी, इसलिए इनका काम आसान हो गया। और ग्रामीण इसके बारे में पूरी तरह बेखबर थे।

करीब दस दिनों तक कैम्प के इर्द-गिर्द अत्यंत गोपनीयता के साथ टोह लेने के बाद प्रेस यूनिट की सदस्या कॉमरेड चैते पर इन दरिंदों ने अपना खूनी पंजा मारा। उस समय कॉमरेड चैते अकेली ही नाले में नहाने निकली हुई थी, जो कैम्प से ज्यादा दूर नहीं था। अचानक हुए इस आक्रमण से वह संभल नहीं पाईं। उन्हें पकड़ते ही मुंह को कपड़े से ढंक दिया ताकि वह आवाज न कर सके। वहां से कुछ दूर ले जाकर इन दरिंदों ने कॉमरेड चैते के साथ पाशविकता से सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद चाकू से गला रेतकर उनकी हत्या की। उधर, यूनिट के कॉमरेडों ने चैते के लिए इधर-उधर ढूंढ़ा लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। अगले दिन की सुबह उनकी लाश बहुत ही बुरी हालत में पाई गई। उनके कपड़े फाड़कर इधर-उधर फेंक दिए गए। यूनिट के सदस्यों ने लाश को उठा लाकर जनता के समक्ष कॉमरेड चैते का अंतिम संस्कार किया। सभी जनता और साथी कॉमरेडों ने नम आंखों से कॉमरेड चैते को अंतिम विदाई दी और उनके हत्यारों पर बदला लेने की कसम खाई।

इसके पहले 10 फरवरी 2010 को दुमनार गांव में कुमली नामक कृषि कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की थी इसी केसा बहरा गिरोह ने। उसमें शामिल पिरतू नामक दरिंदे का कुछ ही दिनों के अंदर पीएलजीए ने सफाया कर दिया। और यह इस तरह का

दूसरा हमला था। कॉमरेड चैते के हत्यारों का पता लगाने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। जनता से मिली सूचनाओं से पता चला कि पोदमगोटी गांव के मोड्डा, सुक्कू और कोरिये तथा ऊसेवेड़ा का कोसा इस दरिंदगी में केसा बहरा गिरोह का पूरा साथ दिया था। इन्हें जनता ने मौत के घाट उतार दिया। ऊसेवेड़ा के कोसा का भाई कोहला उर्फ राजू 2002 में मुखबिरी के ही कारण जन अदालत के फैसले के मुताबिक मार डाला गया था। बाद में भाई कोसा भी पुलिस के साथ मिलकर काम करने लगा था। पोदमगोटी के मोड्डा की एक बहन ने एक एसपीओ से शादी की थी जो कुछ साल पहले नारायणपुर में पीएलजीए के हाथों मारा गया था। तबसे वह खुद भी एसपीओ बनकर नारायणपुर में ही रह रही है। और उसने पोदमगोटी में रहने वाले अपने भाई मोड्डा से नियमित संपर्क रखते हुए उसे इस साजिश का हिस्सा बनाया। मोड्डा ने अपने ही गांव के सुक्कू और कोरिये को पैसों के लालच में फंसाकर इस साजिश में भागीदार बनाया। इस तरह बाहर से आए 5 एसपीओ और 4 स्थानीय मुखबिर, कुल 9 लोगों ने इस जघन्य व अमानवीय अपराध को अंजाम दिया। केसा बहरा इस दरिंदगी का सूत्रधार था। हत्या के तुरंत बाद केसा बहरा इन्हें प्रत्येक को 8-10 हजार रुपए देकर नारायणपुर भाग गया, ताकि अपने आका एसपी राहुल भगत से शाबासी और इनाम की मोटी रकम हासिल कर सके। लेकिन जनता और जन संघर्ष इन दरिंदों को कभी माफ नहीं करेंगे। वो जहां भी छिपकर रहें, जितनी भी सुरक्षा हो, खोज निकालेंगे और उन्हें मौत के घाट उतारकर ही कुमली और चेते की निर्मम हत्याओं का बदला लेंगे। खासकर महिला कॉमरेडों को इस प्रकार निशाना बनाकर बलात्कार के बाद हत्या करने की पाशविक घटनाओं की साजिश कर रहे विश्वरंजन, लांगकुमेर, राहुल भगत को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी।

करीब 30 वर्ष की उम्र की कॉमरेड चैते का जन्म उत्तर बस्तर के बड़गांव इलाके के एनहूर गांव में हुआ था। घर पर माता-पिता का दिया नाम 'ललिता मण्डावी' था। जब वह छोटी थी तभी उनके सिर पर से पिता का साया उठ चुका था। वह गैर-आदिवासी कलार समुदाय के एक गरीब परिवार में पैदा हुई थीं। घर में मां और एक छोटा भाई हैं उनके। एनहूर गांव परतापुर इलाके के क्रांतिकारी गांवों में से एक है। इस गांव में क्रांतिकारी जन संगठन सक्रियता से काम करते थे। शुरू से ही इसका प्रभाव कॉमरेड ललिता पर था। कुछ समय तक केएएमएस में काम करने के बाद 1999 में उन्होंने पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में आंदोलन में भागीदार बनने का फैसला लिया। स्थानीय पार्टी ने उन्हें भर्ती करके महिला दस्ते में सदस्य के रूप में नियुक्त किया। महिलाओं का यह विशेष दस्ता खासकर महिलाओं को केएएमएस में संगठित करता था। इस दस्ते में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना नाम 'ज्योति' बदल लिया था। शुरू से ही कम बोलने वाली और अनुशासनप्रिय रही कॉमरेड ज्योति ने इस इलाके के लोगों, खासकर महिलाओं में अपनी खास पहचान बना ली। उनके मेहनती स्वभाव और प्रतिबद्धता को देखते हुए 2002 में उन्हें पार्टी ने प्रेस यूनिट में स्थानांतरित किया। तबसे वह 'चैते' बनकर इस यूनिट का अभिन्न हिस्सा बन गईं। उसके पहले ही उन्हें पार्टी सदस्यता प्रदान की गई थी। प्रेस में आने के बाद उन्होंने विभिन्न किस्म के तकनीकी कामों और छपाई सम्बन्धित विभिन्न कामों को मन लगाकर सीख लिया। प्रेस यूनिट के संचालन के लिए जरूरी सामानों की ढुलाई, रखरखाव और रवाना में भी कॉमरेड चैते ने भरपूर योगदान दिया। पत्र-पत्रिकाओं की छपाई में समय के दबाव के कारण कभी-कभी पूरी रात काम चलता था। ऐसे मौकों पर कॉमरेड चैते ने पार्टी व जनता के हितों को ऊपर उठाते हुए रातों में जगकर भी काम करती थीं।

2007 में कॉमरेड चैते को प्रेस यूनिट की पार्टी कमेटी (एसी स्तर) में लिया गया। वह घर पर पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने ध्यान देकर पढ़ना-लिखना सीख लिया। उनके योगदान व राजनीतिक चेतना को देखते हुए उनको यह पदोन्नति दी गई। यूनिट की सुरक्षा, संचालन और समस्याओं पर कॉमरेड चैते कमेटी की बैठकों में अपने विचार व्यक्त करते हुए यूनिट के विकास में अपना योगदान दिया। वर्ष 2005 में उन्होंने उसी यूनिट में काम करने वाले अपने पसंद के एक कॉमरेड से शादी कर ली। इन दोनों की जोड़ी ने यूनिट के काम को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दिया। कॉमरेड चैते दुबली-पतली थीं, बीच-बीच में बीमार भी पड़ जाती थीं। फिर भी वह अपने काम को मजबूत इरादों से अंजाम देती थीं। बीच में उनके घर और गांव पर पुलिसिया दमन का कहर टूटा था। गांव के कई संगठन नेता-कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके सगे भाई को भी पुलिस ने झूठे केस में फंसाकर एक साल से ज्यादा समय जेल में रखा था। इससे कॉमरेड चैते को मानसिक रूप से काफी दिक्कत हुई थी। वह उनकी बूढ़ी मां को लेकर चिंतित हो जाती थीं क्योंकि उनका एक मात्र सहारा इकलौता बेटा ही था। फिर भी कॉमरेड चैते ने घर की समस्याओं को अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों पर हावी होने नहीं दिया। 2008 के आखिर में घर वालों से मिलने के लिए जाकर मां और भाई का हौसला बढ़ाकर और उन्हें सरकार के आतंकी व दमनकारी स्वभाव से अवगत करवाकर वापस अपनी जिम्मेदारी पर लौट आई थीं।

आखिर चैते के साथ इतनी बर्बरता क्यों बरती? क्योंकि कॉमरेड चैते की हत्या कर वो प्रेस यूनिट के काम पर चोट करना चाहते थे। दण्डकारण्य आंदोलन की आवाज की तरह काम करने वाली इस यूनिट के हौसलों को पस्त करना चाहते थे। जनता की तरफ से उठने वाले विरोध-प्रतिरोध की आवाज को दबाना चाहते थे। उन्होंने एक महिला कॉमरेड को अपना निशाना क्यों बनाया? इसके जवाब के लिए खासकर माड़ अंचल के क्रांतिकारी आंदोलन की रचना को समझना होगा। माड़ डिवीजन के आंदोलन में खासकर पिछले दस सालों से महिलाओं की

भागीदारी प्रेरणादायक स्तर पर है। हालांकि यह पूरे दण्डकारण्य पर भी लागू होता है, लेकिन माड़ में इसे और भी स्पष्टता से देख सकते हैं। यहां पार्टी की डिवीजनल कमेटी और एरिया कमेटियों के अलावा विभिन्न विभागों के संचालन में भी महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। भर्ती होने वाले नए सदस्यों में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। दुश्मन ने इस पर भी चोट करना चाहा। ऐसी महिलाओं को आतंकित करने के लिए ही उसने इस प्रकार सामूहिक बलात्कार और बर्बर हत्या का तरीका चुन लिया। यह कोई केसा बहरा जैसे भाड़े के हत्यारे के दिमाग से पैदा हुई सोच नहीं है। यह रणनीतिक तौर पर उच्च स्तर पर ही लिया गया निर्णय है जो सरकारों के 'जनता के खिलाफ युद्ध' का हिस्सा है। लेकिन हत्याओं और आतंक के बल पर जनता के न्यायपूर्ण आंदोलन को कुचलना असंभव है, इसे समझने के लिए इतिहास की बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है। फासीवादी सलवा जुडूम और उसके बाद का इतिहास भी काफी है। कॉमरेड चैते के अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने और उनकी निर्मम हत्या का बदला लेने माड़ अंचल के महिला-पुरुष और भी जोशोखरोश के साथ आंदोलन के साथ जुड़ेंगे और इस शोषक व्यवस्था को दफनाने के लिए जारी संघर्ष को और तेज करेंगे।

कॉमरेड चैते कम बोलने वाली, हमेशा काम को महत्व देने वाली और हंसमुख स्वभाव वाली गंभीर कॉमरेड थीं। उन्होंने अपने 11 साल के क्रांतिकारी जीवन में पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन को अनमोल सेवाएं दीं। लेनिन ने कहा था कि 'पत्रिका एक संगठनकर्ता है।' कॉमरेड चैते ने 'प्रभात' पत्रिका समेत पार्टी की अनेक पत्रिकाओं की छपाई में, क्रांतिकारी साहित्य के प्रकाशन के कार्यों में और दुश्मन के खिलाफ जारी क्रांतिकारी प्रचार-युद्ध की हर सामग्रि की तैयारी में अपना योगदान दिया। इस तरह उन्होंने कई 'संगठनकर्ता'ओं को सजाने-संवारने का काम किया। उनकी उंगलियों से और उनके खून-पसीने से पिछले 8 सालों में लाखों कोरे कागज क्रांतिकारी साहित्य का आकार लेकर पीएलजीए के सैनिकों, जन संगठन सदस्यों और क्रांतिकारी जनता के हाथों में पुस्तक के रूप में, पत्रिका के रूप में और पर्चा-पोस्टर बनकर पहुंचता रहा। उन्हें शिक्षित करता रहा। शोषक-लुटरों के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देता रहा। पिछले करीब 15 वर्षों से चल रहे दण्डकारण्य प्रेस यूनिट में वह पहली शहीद बनी हैं। वह भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और सर्वहारा गुण हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। कॉमरेड चैते की शहादत को 'प्रभात' सम्पादकमण्डल विनम्रता से सिर झुकाकर लाल सलाम पेश करता है और उनके शोकसंतप्त प्रिय जनों और प्रेस यूनिट के तमाम कॉमरेडों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है। ★

(... पेज 21 का शेष)

की तरह देखते हैं। जेल सूपरिंटिंडेंट संतोषकुमार मिश्र, केके गुप्ता, एसएस थिग्गा - इन्होंने जेलों में हमारे कॉमरेड्स मालती, मीना, गोपन्ना मरकाम समेत कुछ अन्य कॉमरेडों को गुण्डों से पिटवाया। इन कट्टर प्रतिक्रियावादी अधिकारियों पर राजनीतिक कैदियों के अलावा साधारण कैदियों के साथ जुल्मों के कई आरोप हैं।

जेलों में नम्बरदारों का माफिया काम करता है जिन्हें वार्ड चक्कर इंचार्ज भी कहा जाता है। ये लोग वास्तव में कैदी ही होते हैं। लेकिन एक शब्द में कहें तो इन नम्बरदारों का जेल में आतंक और भ्रष्टाचार चलता है। जगह पर उनका कब्जा होता है। इसलिए पहले रहने के लिए जगह भी उनसे खरीदनी पड़ती है। इसके लिए 500 से 1000 रुपए तक देना पड़ता है। वरना शौचालय के बगल में, गंदगी में दिन और रातें काटनी पड़ती हैं। इसका विरोध करने पर ये गुण्डे जेल प्रशासन की सांठगांठ से मारपीट करते हैं।

जेलों में बंद कैदियों को नियमित मात्रा में राशन से खाना बनाकर देना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। छत्तीसगढ़ के जेलों में खाना बेचा जाता है। जेल के अंदर जाते ही कैदियों से सौदा किया जाता है। कैदियों को अगर आदमियों जैसा खाना खाना है तो घर से पैसे मंगवाकर इस माफिया से खरीदना ही पड़ेगा। वरना जेल में जो खाना मिलता है उसे 'पायली खाना' बुलाया जाता है जिसे जानवर तक छूना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के जेलों में 40 प्रतिशत कैदी इसी खाने से जिंदा रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खाना खरीदकर खा नहीं सकते। जेल में बाकायदा ढाबा चलता है जिसको जो चाहे मिल सकता है बशर्ते आपके पास पैसा हो। कमाई का एक बड़ा दुष्चक्र है यहां। इस पर जेल अधिकारी हर माह हजारों रुपए की कमाई करते हैं।

बीमार राजनीतिक बंदियों के साथ अमानवीयता बरती जा रही है। नारायण सान्याल व जयपाल जैसे उम्रदराज कॉमरेड तथा कई महिला कॉमरेड जेलों में कई बीमारियों से पीड़ित हैं। लेकिन उनके इलाज करवाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा कई बार एस्कॉर्ट के अभाव का बहाना बनाकर पेशियों में नहीं ले जाया जाता है। जमानत से वंचित करके झूठी गवाहियों से सजाएं दी जा रही हैं। कॉमरेड्स मालती और सुरेंद्र कोसरिया को 10 साल की सजा पूरी तरह झूठे गवाहों और सरकारी साजिश का परिणाम है।

राजनीतिक कैदियों को अखबार तक नहीं दिया जाता। कोई पुस्तक नहीं। 16-17 घण्टों तक लाकप में रखते हैं, सिर्फ 4 घण्टे ही बैरक से बाहर आने देते हैं। खासतौर पर राजनीतिक कैदियों को मनमानी प्रताड़नाएं दी जा रही हैं ताकि उनके मनोबल को तोड़ा जा सके। यह अमानवीय व अवैध है।

जेलों में व्याप्त इन दूभर हालात और अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार के खिलाफ हर इंसाफ-पसंद व जनवाद-पसंद इंसान को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों को कानूनी तौर पर मदद पहुचाने के लिए आगे आना चाहिए। ★

छत्तीसगढ़ के जेलों में व्याप्त दूभर हालात और राजनैतिक कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय दुरव्यवहार की निंदा करो!

दुर्ग जेल में यातनाओं से शहीद होने वाले कॉमरेड सुकदास उसेण्डी अमर रहें!

करीब 30 साल के नौजवान कॉमरेड सुकदास उसेण्डी नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड के नेलंगूर गांव के निवासी थे। यह गांव माड़ डिवीजन के अंतर्गत आता है। माड़ के सभी गांवों की तरह इस गांव में भी विभिन्न क्रांतिकारी जन संगठन सक्रिय हैं। कॉमरेड सुकदास भी सहज ही जन संगठन के आम सदस्य के रूप में गांव में होने वाली हर गतिविधि में भाग लेते थे। उनके पिता का नाम दुग्गा उसेण्डी और माता का नाम मासे है। उनकी शादी हुई थी और वह एक बच्ची व एक बच्चे के बाप भी थे। 2006 में सुकदास को पुलिस ने उस समय पकड़ लिया था जब वह नारायणपुर हाट बाजार गए हुए थे। उनके साथ में उनके ही गांव के इरपा उसेण्डी और परपा गांव के बुधू वेडदा को भी गिरफ्तार कर लिया। सोनी नामक एक महिला एसपीओ ने पुलिस को दिखाकर उन्हें पकड़ा दिया था। यह दरअसल नारायणपुर और ओरछा में आम तौर पर होता है। पूरे हाट बाजार में जगह-जगह मुखबिर और एसपीओ तैनात रहते हैं। चूंकि वो दूर-दराज के गांवों से आने वाले ग्रामीणों को पहचानते हैं, इसलिए किसी को भी दिखाकर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवा देते हैं। जरूरी नहीं कि वो जन संगठनों के सदस्यों को ही दिखाते हों। अक्सर ऐसे पकड़े गए लोगों पर मुखबिर या एसपीओ बनने का दबाव डाला जाता है।

बहरहाल, पुलिस ने खूब मारपीट कर पैसों का प्रलोभन देने से भी कॉमरेड सुकदास और उनके साथियों ने मुखबिर या एसपीओ बनने से इनकार किया। पैसों के लालच में अपनी ही जनता के साथ गद्दारी करने से साफ मना कर दिया। इसलिए पुलिस अधिकारियों ने उन्हें इनामी नक्सलवादी के रूप में चित्रित कर कई झूठे मुकदमों में फंसाकर पहले जगदलपुर जेल भेज दिया जहां से उन्हें बाद में दुर्ग जेल भेज दिया गया था। मोड्डा नामक एसपीओ की हत्या का मामला इनके खिलाफ दर्ज किया गया था। जेल में व्याप्त घोर व दयनीय हालात में वे बड़ी मुश्किल से दिन काटते रहे।

जंगल में आजाद पंछियों की तरह जिंदगी जीने वाले आदिवासियों को जेल नरक से कम नहीं है। वहां का खाना, पीना, रहना, दिन भर चार दीवारों के बीच घुटन सी जिंदगी जीना यह सब उनकी कल्पना से परे है। फिर भी कॉमरेड सुकदास ने इसे झेला। ठीक से खाना नहीं मिलने के कारण वह बीमार भी पड़े थे। फिर भी दुर्ग जेल में राजनीतिक कैदियों द्वारा किए गए संघर्ष में उन्होंने भाग लिया। इसीलिए जेल प्रशासन ने उनकी हत्या कर पूरे राजनीतिक कैदियों को एक 'सबक' सिखाने का फैसला लिया। एक साजिश के तहत उसने अपने कुछ गुण्डों व दलालों के जरिए फरवरी 2010 में होली के दिन सुकदास की गला दबाकर हत्या करवाई। बाद में अधिकारियों ने यह घोषणा की कि बीमारी के चलते सुकदास की मृत्यु हुई थी।

कॉमरेड सुकदास के मारे जाने की खबर उनकी बूढ़ी मां को काफी देर से मिली थी और वह दुर्ग जेल गई भी थीं। लेकिन वह अपने बेटे की अस्थियों को भी नहीं ला सकीं। जेल प्रशासन इस बूढ़ी आदिवासी औरत को उसके बेटे की कब्र तक नहीं दिखाया जिस पर वह कम से कम मुठ्ठी भर मिट्टी डाल सके। आज आदिवासियों को बड़े पैमाने पर जेलों में कैद कर और हत्या कर शासक वर्ग सोच रहे हैं कि वे माओवादी आंदोलन पर 'अंकुश' लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ऐसी सैकड़ों माताओं की जली हुई कोख में से हजारों 'सुकदास' पैदा हो सकते हैं, जो इस सड़ी-गली व्यवस्था को कब्र में पहुंचाने तक आराम नहीं करेंगे।

जेलों के बदतर हालात - राजनीतिक कैदियों का दमन

कहते हैं जेल 'सुधार के मंदिर' होते हैं। 'सजा अपराध को दो, अपराधी को नहीं' - यह वाक्य लगभग हर जेल की दीवार पर लिखा जाता है। लेकिन सच यह है कि आज जेलों में, खासकर छत्तीसगढ़ के जेलों में कैदियों के साथ गुलामों सा या यूं कहें कि जानवरों सा बरताव हो रहा है। जहां एक कैदी को रखने की जगह है, वहां 10-10 कैदियों को ठूंसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चार केन्द्रीय जेल हैं। बस्तर क्षेत्र के माओवादी कैदियों को पहले आमतौर पर जगदलपुर और दंतेवाड़ा जेलों में ही ज्यादा रखा जाता था। लेकिन अभी 2005 से जारी व्यापक दमन अभियानों तथा 2007 दिसम्बर में घटित 'दंतेवाड़ा जेल ब्रेक' के बाद बस्तर के लागों को रायपुर व दुर्ग जेलों में रखा जा रहा है। फिलहाल सभी जेलों में मिलाकर सैकड़ों 'माओवादी' आदिवासी जेलों में कैद हैं।

हालांकि छत्तीसगढ़ के सभी जेलों का हाल करीब-करीब एक जैसा ही है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा बदतर हालत दुर्ग जेल की है। जेलों के अधिकारी सब हिटलर की औलादें ही हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अपने खिलाफ एक शब्द भी ये अधिकारी बर्दाश्त नहीं करते। और ये कैदियों को कीड़ों-मकोड़ों

(शेष पेज 20 में...)

भोपाल फैसला - मौजूदा अन्यायपूर्ण और उत्पीड़नकारी व्यवस्था का पर्दाफाश

साल था 1984। दिसम्बर महीने की कड़कड़ाती ठण्डी और गाढ़ी रात। 2 और 3 तारीखों की दरमियानी रात। भोपाल के लोग दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद रात को गहरी नींद में थे। उन्हें पता ही नहीं था कि रात की नींद में भी मौत चुपचाप उनके घरों के अंदर चली आ सकता है। यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक दवाएं बनाने वाले कारखाने में से जहरीले गैस का रिसाव हो जाने से चंद मिनटों में ही शहर में मातम छा गया। अपना दम क्यों घुट रहा है, इसे समझने से पहले ही कइयों ने दम तोड़ दिया। उसी रात में मारे जाने वालों की संख्या लगभग 8 हजार तक थी। अगले दो दिन तक हुई मौतों को मिलाने से कुल संख्या 15 हजार से ऊपर हुई थी। अभी तक दीर्घकालीन बीमारियों से 35 हजार लोग मारे जा चुके हैं। मौतों का सरकारी आंकड़ा तो 15,274 है। कम से कम 5 लाख लोगों के फेफड़ों में गैस चले जाने के कारण वे सभी आज भी कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इन बीमारियों से सालाना एक हजार लोग मारे जा रहे हैं। तबसे वहां पैदा हो रहे बच्चे अनुवांशिक बीमारियों से पीड़ित हैं। उस रात में और उसके बाद तीन-चार दिनों तक वहां मरे पशुओं की कोई गिनती नहीं है।

1984 - भोपाल गैस दुर्घटना के समय मौत का मंजर

7 जून 2010 - 26 सालों के लम्बे और पीड़ादायक इंतजार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा माने जाने वाले भोपाल गैसकाण्ड में मारे गए लोगों के सगे-सम्बधी, बचे हुए पीड़ित और पीड़ितों के पक्ष में लम्बी लड़ाई लड़ने वाले - हजारों लोग भोपाल के जिला न्यायालय के सामने को इकट्ठे हुए थे। और देश भर में करोड़ों लोग इस पर नजर रखे हुए थे कि क्या दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में भोपाल के लाखों पीड़ितों को न्याय मिलेगा। लोगों को न्यायालय परिसर से बाहर धकेलने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाईं। अंदर किसी को प्रवेश करने नहीं दिया गया। और अंदर गए थे सात भारतीय 'अभियुक्त', पूरे सम्मान के साथ और शान के साथ भी। मजिस्ट्रेट ने 100 पन्नों का फैसला सुनाया जिसमें उन्हें मात्र दो सालों की जेल की सजा सुनाई। अभियुक्तों में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष केशुब महींद्रा समेत कम्पनी के अन्य अधिकारी शामिल हैं। अमेरिका में बैठा मुख्य अभियुक्त वारेन एण्डरसन 26 सालों से चल रहे इस मुकदमे से दूर ही रहा। उसे 'फरार' घोषित कर भारतीय अभियुक्तों को अलग करके मुकदमा चलाया जाता रहा।

अदालत के अंदर नजारा यह था कि 'सजा' सुनाते समय सभी सातों अभियुक्त आरमदायक कुर्सियों में बैठे हुए थे, न कि कटघरे में खड़े थे। सुनाने के तुरंत बाद भी उन्हें उसी वक्त बैठे-बैठे ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। सजा भुगतने से पूरी छूट। और इस तरह 'सजा' पाने वाले सातों अधिकारी अदालत से 'बाइज्जात' बाहर निकलकर अपने-अपने घर चल दिए। और उन्हें सुरक्षित वहां से निकालने के लिए भोपाल की पूरी पुलिस व्यवस्था मुस्तैदी से तैनात थी जिसने फिर एक बार लोगों पर लाठियां बांझ दीं। इस घोर अन्याय से आक्रोशित हजारों लोग न्यायालय के बाहर चीखते-चिल्लाते रहे और नारे लगाते रहे। और देश भर में जनता इस शर्मनाक और देश की संप्रभुता के लिए भी अपमानजनक फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया की। बहती गंगा में हाथ धोने में माहिर विभिन्न संसदीय राजनीतिक पार्टियों ने इस जनाक्रोश को भुनाने के लिए अलग-अलग स्तर का 'विरोध' प्रकट किया और इस नाइंसाफी पर दिखावटी नाराजगी व्यक्त की। इस बीच लाखों भोपालवासियों की जिंदगी को अंधकारमय बनाने वाले मुख्य हत्यारे एण्डरसन को देश से बाहर चले जाने की छूट देने की जिम्मेदारी को लेकर बहस शुरू हुई। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं, खासकर पिछले 20 सालों से सरकारों द्वारा लागू नीतियों पर नजर रखने वालों को तो इसे समझना मुश्किल भी नहीं है।

भोपाल गैस त्रासदी और 7 जून 2010 को आये फैसले ने फिर एक बार उसी बात को साबित कर दिया जो हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) शुरू से कहते आ रही है - कि मौजूदा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था और भारतीय राज्य अर्ध-औपनिवेशिक और अर्ध-सामंती स्वभाव के हैं; कि हमारे देश के शासक वर्ग और विभिन्न संसदीय पार्टियों के रूप में मौजूद उनके राजनीतिक प्रतिनिधि साम्राज्यवादी ताकतों के मंजे हुए दलाल हैं जिन्हें मोटी रकम के एवज में हमारे देश और जनता के हितों को साम्राज्यवादी दैत्यों के चरणों में गिरवी रखने में जरा भी संकोच नहीं है; कि ये गद्दार अपने पास मौजूद सभी साधनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने साम्राज्यवादी आकाओं के हितों की रक्षा की जा सके और विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबा देते हैं; कि

ये दरिंदे पुलिस, अर्ध-सैनिक बल, सेना, न्यायव्यवस्था, नागरिक प्रशासन, विधायिका, संविधान आदि औजारों का दुरुपयोग करते हैं ताकि खून की प्यासी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके भारतीय दलालों की रक्षा की जा सके और जनता के हरेक प्रतिरोधी आंदोलन का दमन किया जा सके; कि मौजूदा अन्यायपूर्ण व उत्पीड़नकारी व्यवस्था जोकि गरीबों के खिलाफ पूरी तरह पक्षपातपूर्ण रवैया रखती है, के तहत गरीब कभी इन्साफ हासिल नहीं कर सकता।

भोपाल गैस हादसे में हजारों लोगों की जानें गईं थी। इस हादसे ने लाखों लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को तबाह कर दिया। भविष्य को अनिश्चित बना दिया। भारत की जनता की सार्वभौमिक सत्ता को मजाक बना दिया। इसके बावजूद भी, सरकारों, सत्ता की संस्थाओं, राजनीतिक दलों और न्यायव्यवस्था का इस पर जो रवैया रहा और छब्बीस सालों के बाद उस पर न्यायालय का जो फैसला आया, वो बेहद क्रूर और दरिंदगी भरे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से जो बात निकलकर आती है वो यह है कि इस देश पर अभी भी पराए देशों के रईसों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, उनके गुलामों व दलालों के गुट की ही हुकूमत चल रही है, न कि स्वतंत्र व जनता की सरकार। लोकतांत्रिक और सार्वभौमिक शासन के नाम पर हमारे देश में जो लागू है वह सत्ताधारी वर्गों की लूटखसोट के अलावा कुछ नहीं है। भोपाल त्रासदी स्पष्ट रूप से यही कहती है। भोपाल पांच लाख स्वरों से यही समझाता है कि यहां पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके दलालों का शासन ही चल रहा है जिन्हें गरीब जनता के प्राणों के प्रति, उनके हितों के प्रति और देश के संसाधनों के प्रति जरा भी ध्यान नहीं है।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 1968 से 1984 तक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के स्वामित्व में कीटनाशक दवाएं बनाने का एक कारखाना हुआ करता था। अमेरिका की यूनियन कार्बाइड नामक बहुराष्ट्रीय कम्पनी यूसीआईएल की माई संस्था है जिसके पूरे भारत में 14 कारखाने हैं। उसकी पूंजी में उसकी माई कम्पनी का हिस्सा 50.9 प्रतिशत है। यानी फैसले लेने के लिए पर्याप्त हिस्सा। भोपाल त्रासदी के बाद भोपाल स्थित उसका कारखाना बंद पड़ने के बावजूद उसका दूसरा कारोबार जारी ही था। 2001 में अमेरिका की माई संस्था को दि डाउ केमिकल्स कम्पनी (टीडीसीसी) नाम की एक और भारी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने खरीदकर अपने में मिला लिया। यानी भारत में दर्ज यूसीआईएल नामक कम्पनी और यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कम्पनी अब अस्तित्व में नहीं हैं। यह जानने के बावजूद भी कि इन कम्पनियों का हजारों लोगों को मारने, लाखों लोगों को बीमार बनाने और पर्यावरण को प्रदूषित करने का आपराधिक इतिहास रहा है, उनकी सम्पत्तियों को खरीदने वाली डाउ केमिकल्स को उस अपराध की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। इस खरीदी के समय डाउ केमिकल्स कम्पनी ने हमारे देश के दो प्रमुख वकीलों से यह पूछा था कि उसे इस अपराध की जिम्मेदारी लेनी तो नहीं पड़ेगी और मुआवजा भुगतान करने की जिम्मेदारी तो नहीं होगी। लेकिन उन दोनों वकीलों ने लिखित रूप से जवाब दिया था कि ऐसी कोई जिम्मेदारी इस कम्पनी पर नहीं रहेगी। उन दोनों में से एक था अभिषेक मनु सिंघवी जो आज कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है और दूसरा था अरुण जैटली जो भूतपूर्व मंत्री है और फिलहाल भाजपा का प्रवक्ता। यही नहीं, केन्द्रीय मंत्री चिदम्बरम, कमलनाथ और मोंटेकसिंह अहलूवालिया ने भी 2006-07 में घोषणा की कि डाउ केमिकल्स को न तो इस अपराध से और न ही मुआवजे की अदायगी से कोई लेना-देना रहेगा। उनका कहना है कि चूंकि 1984 में हुए गैस रिसाव से डाउ का कोई लेना-देना नहीं, इसलिए कचरा हटाने के लिए जरूरी 100 करोड़ रुपए देने के लिए भी उसे बाध्य न किया जाए। इससे भारत में विदेश निवेश प्रभावित होगा। गौरतलब है कि इसी सिलसिले में अमेरिकी सरकार ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष व साम्राज्यवादियों का नम्बर एक लाड़ला मोंटेकसिंह अहलूवालिया को एक ई-मेल भेजा जिसमें कोई कड़े कदम उठाने के बारे में न सोचने की 'हिदायत' दी गई।

कम्पनी के स्वामित्व और अपराध की जिम्मेदारी से जुड़े इस विवाद को छोड़ भी दें, तो उस कम्पनी के शुरूआती दिनों के बारे में ऐसी कई जानकारियां हैं जिनको कि जानना जरूरी है। दरअसल भोपाल कारखाने की स्थापना ही घपलेबाजी से ही हुई थी। घपलेबाजी से ही उसका काम चलता रहा।

1960 के दशक में देश में हरित क्रांति के नाम से चली प्रक्रिया ने कृषि क्षेत्र को वाणिज्यिक फसलों और बाजारू फसलों की बलि चढ़ाई। खेती में अधिक पैदावार हासिल करने के बहाने से चली उस प्रक्रिया ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग व व्यापार को बेहद बढ़ा दिया। स्थानीय बीजों के इस्तेमाल पर कटौतियां लागू कीं। कृषि क्षेत्र में जहां जरूरत नहीं है वहां भी मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं और मशीनें व उनके पुरजे ज्यादातर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पाद ही हैं। यानी हरित क्रांति ने भारत में कृषि में पैदावार बढ़ाने के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विशाल बाजार मुहैया करवाया। इस तरह हरित क्रांति ने भारतीय किसानों के जीवन को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास गिरवी रख दिया। इस विनाशकारी नीति के शुरू होने के बाद देश में रासायनिक दवाओं और कीटनाशक दवाओं की जरूरत बेहद बढ़ गई। हरित क्रांति की रणनीति को बेचने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और इन जहरीले रसायनों के कारोबार में लगी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं, जोकि आश्चर्य भी नहीं है। हरित क्रांति के शुरू होने के बाद पहले पांच सालों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तीन गुना बढ़ा था। 1960-61 में 2,92,000 टन उर्वरकों का इस्तेमाल हुआ था तो 1970-71 तक दस गुना बढ़कर 21,80,000 टन तक बढ़ा। उसी समय कीटनाशियों का प्रयोग भी 8,620 टनों से तीन गुना बढ़कर 24,320 टन तक बढ़ा है। यानी इन उर्वरकों और कीटनाशियों को बेचने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुनाफे तीन गुना से दस गुना बढ़े होंगे। दरअसल इस बढ़ोत्तरी को कृषि पैदावार की बढ़ोत्तरी से तुलना करके देखेंगे तो यह

साफ हो जाता है कि हरित क्रांति ने किसे फायदा पहुंचाया। जहां उर्वरकों का इस्तेमाल एक हजार प्रतिशत और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल 300 प्रतिशत बढ़ा, वहीं कृषि के पैदावार में बढ़ोत्तरी अधिक से अधिक 53 प्रतिशत ही है जोकि गेहूं में हुई। यह बढ़ोत्तरी धान में 10 प्रतिशत और तिलहनों में 14 प्रतिशत ही रही।

हरित क्रांति की कृषि प्रक्रियाओं से पैदावार तो नहीं बढ़ा, उलटा सैकड़ों नए कीट और बीमारियां कृषि क्षेत्र पर छा गईं। तब तक देश में मौजूद कीटनाशियों के उत्पादन को नाकाफी मानते हुए भारत सरकार ने 1966 में फैसला लिया कि विदेशी कीटनाशक कम्पनियों को आमंत्रित किया जाए। इस तरह भारत में 1966 से ही अपने कीटनाशकों को बेचने वाली शुरूआती कम्पनियों में से एक थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। उस दशक के आखिर तक उसने भोपाल में सेविन और टेमिक नामक कीटनाशक दवाएं बनाने का कारखाना शुरू किया था। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में जब तब खर्चे कम करने और आमदनी बढ़ाने के उपाय यह कम्पनी खोजती रही थी। इन प्रयोगों के तहत उसने मिथैल ऐसोसाइनेट (एमआईसी - मिक) नामक एक रसायन से सेविन और टेमिक बनाने की प्रक्रिया की खोज की। दरअसल एमआईसी (मिक) जहरीला है और बेहद खतरनाक है। इसकी बजाए कम खतरनाक और ज्यादा कीमत वाले एक और रसायन से इस कीटनाशक दवा को बनाया जा सकता है, जोकि यूनियन कार्बाइड को मालूम भी था। लेकिन कम खर्च से ज्यादा मुनाफा के लालच में इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने एमआईसी को ही चुन लिया।

एमआईसी के इस्तेमाल के समय भी आवश्यक सावधानियां ली जा सकती थीं। उसका भण्डारण ज्यादा मात्रा में न करते हुए कम मात्रा में किया जा सकता था। एक ही जगह पर बड़े-बड़े टैंकों में न रखते हुए छोटे-छोटे डिब्बों में रखा जा सकता था। उसे ले जाने वाली पाइप लाइनों को जंग न लगने वाले लोहे से बनाया जा सकता था। उसे हमेशा अत्यंत ठंडी जगह में रखकर उसे फैलने से रोका जा सकता था, उसमें पानी के प्रवेश को रोका जा सकता था और उसे विस्फोटित होकर हवा में फैलने से रोका जा सकता था। अगर वह इस तरह हवा में प्रवेश कर भी जाता है तो उसकी सांस लेने वालों को तुरंत सोडियम थयोसल्फेट नामक एक और रसायन देने के एहतियाती उपाय को आसपास के इलाकों में प्रचारित किया जा सकता था। यूनियन कार्बाइड ने यह सब जान-बूझकर भी, दूसरे देशों में इन पर अमल करते हुए भी भोपाल में इनमें से एक भी काम नहीं किया।

यह सब किसी को मालूम न रहा हो या गोपनीय तरीके से हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। लापरवाही या टालमटोल के चलते हुआ हो, ऐसा भी नहीं। इरादतन, हत्यारे स्वभाव से और जनता के प्राणों के प्रति तिरस्कार की भावना से काम करने वाली पूंजी का यही लक्षण है। मुनाफा या सुरक्षात्मकता और मनाफा या मनुष्य का प्राण - अगर इनमें किसी एक को चुनना है तो पूंजी हमेशा मुनाफे को ही चुन लेती है।

पूंजी के, खासकर साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पूंजी के इस हत्यारे स्वभाव पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं करती क्योंकि सरकार उनके हितों की रक्षा में समर्पित है। हालांकि वह अपने आपको कल्याणकारी राज्य के रूप में बताती है और उसने कथित रूप से पूंजी के बुरे लक्षणों के नियत्रण के लिए ही कई कानूनों और कल्याणकारी नियमों को तैयार किया है। ऐसे नियमों के मुताबिक कम से कम दो दर्जन सरकारी विभागों को ऐसे कारखानों के तौर-तरीकों पर हमेशा नजर रखते हुए समय-समय पर जांच करते हुए अव्यवस्थाओं की रोकथाम करनी चाहिए थी। लेकिन जांच करने का अधिकार महीनेवार घूस वसूलने की छूट में तब्दील हो गया। जनता और मजदूरों के कल्याण के लिए हम हैं, यह विचार ही उनके दिमाग से गायब हो गया।

भोपाल कारखाने में कानूनी नियमों का प्रबंधन ने किस तरह खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया, इसे जानने के लिए एक उदाहरण काफी है। जबकि वहां बनाए जाने वाले सेविन और टेमिक के लिए सालाना 3-4 टन एमआईसी ही चाहिए थी, तो हादसे के समय वहां पर 42 टन जहरीले गैस मौजूद था। जरूरत से दस गुना ज्यादा जहरीले रसायन का भण्डारण करने पर उस पर किसी भी सरकारी मशीनरी ने सवाल नहीं उठाया। कोई जरूरी कार्रवाई नहीं की।

इस तरह भोपाल दुर्घटना के लिए पहली जिम्मेदारी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की है जबकि अपनी नीतियों और दलाली के लालच के कारण शासकों ने तथा अपनी लापरवाही व रिश्वतखोरी के कारण अधिकारियों ने इसमें हिस्सेदारी की। इस तरह भारत सरकार को, मध्यप्रदेश राज्य सरकार को और शासन प्रणालियों को अपने दलाल और गुलाम बना चुकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने कम से कम ऐसे न्यूनतम एहतियाती कदम भी जो वह दूसरे देशों में और अपनी माई संस्था वाले अमेरिका में उठाती है, न उठाते हुए यहां पर उत्पादन शुरू किया।

1976 से हादसे के दो माह पहले तक कम से कम दो दर्जन बार चेतावनियां दी गई थीं कि भोपाल के फैक्टरी में उचित एहतिहाती कदमों का अभाव है, मजदूरों व जनता की सुरक्षा के जरूरी उपाय नहीं हैं और इससे मनुष्यों के प्राणों व स्वास्थ्य को खतरा है। कारखाने के अंदर मजदूर मारे गए। जनता ने शिकायतें कीं कि कारखाने के बाहर जहरीले गैसों का रिसाव हो रहा है। अंदरूनी जांच की रिपोर्टों में कई गड़बड़ियां सामने आईं। आखिर में 1982 से संभावित खतरे से आगाह करते हुए स्थानीय अखबारों में खबरों और लेखों का छपना शुरू हो चुका था। लेकिन न तो कम्पनी के प्रबंधन ने और न ही सम्बन्धित सरकारी विभागों ने खतरे के इन संकेतों पर ध्यान दिया। एक बड़ी कम्पनी को प्रदेश में लाने की डींगों से जनता को भ्रमित करने का मौका एक तरफ, तो दूसरी तरफ उस कम्पनी से मिल रही दलाली की मोटी रकम - दोहरे फायदे होने लगे थे राजनीतिक नेतृत्व को।

इस तरह एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी की मुनाफाखोरी, स्वदेशी शासकों की मिलीभगत और नौकरशाही तंत्र की उपेक्षा – इन सबकी सांझी भागीदारी से 1984 के दिसम्बर माह की 2-3 तारीखों की दरमियानी रात यह बेहद त्रासदपूर्ण हादसा हुआ था जिसने हजारों लोगों की जानें लीं और लाखों लोगों को बीमार बना दिया। वहां के आबोहवा में गैस मिल जाने के कारण उसके दुष्प्रभाव कितने सालों तक होंगे, इस पर पर्याप्त शोध तक नहीं हुआ था। शोध हुए भी थे तो सरकारी अधिकारियों ने कागजों को जब्त कर उन्हें लापता कर दिया। इस कारखाने के परिसर में जमा हुए जहरीले रसायनों की सफाई आज तक नहीं की गई। इन छब्बीस सालों से वो रसायन वहां की मिट्टी में मिलकर चारों तरफ फैलकर किस तरह का खतरा उत्पन्न कर रहे होंगे या उत्पन्न करेंगे, किसी को मालूम नहीं।

एक झटके में इतने सारे लोगों को मार डालने वाली इस दरिंदगी के प्रति भारत सरकार और मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने जिस तरह का बरताव किया वह बेहद नीचतापूर्ण है। उससे ठीक कुछ हफ्ते पहले इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाली थी। उसने घोषणा की थी कि वह तब तक चल रहे आयात वैकल्पिक नीति को बदलकर आयात उदारीकरण की नीति लागू करेगा। इस पृष्ठभूमि में शासकों की यह दरिंदगी भरी नीति लागू हो गई कि चूंकि किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी पर कड़ी कार्रवाई करने से विदेशी पूंजी देश में आने से कतराएगी, इसलिए यूनियन कार्बाइड पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी नीति के चलते जब यूनियन कार्बाइड का अध्यक्ष वारेन एण्डरसन भोपाल आया था उसे इस अपराध में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाने की बजाए पूरी विनम्रता और तमाम शाही सम्मानों के साथ गेस्ट हाउजों में मेहमाननवाजी की गई। बाद में मुख्यमंत्री के विशेष विमान में दिल्ली भिजवाकर वहां से अमेरिका जाने की छूट दी गई। उसके बाद उस पर नाम के वास्ते मुकदमा चलाया तो गया था, लेकिन उसे अदालत में उपस्थित होने पर बाध्य करने की कोई कोशिश नहीं की गई। 'फरार अभियुक्त' के रूप में उसका जिक्र किया जाता रहा।

एण्डरसन की ही बात नहीं, सरकार ने कभी नहीं चाहा कि असल में इस अपराध की ठीक से जांच हो और गुनाहगारों को उचित सजा मिले। सरकार की यह कोशिश कभी नहीं रही कि पीड़ितों को मुआवजा दिलवाया जाए, पुनर्वास की व्यवस्था हो जाए, हादसे की जगह की सफाई की जाए और तमाम पीड़ितों के स्वास्थ्य की ठीक से रिपोर्ट बनाकर उचित जांच की जाए। भोपाल के पीड़ित खुद ही या स्वयंसेवी संगठनों या जन संगठनों के जरिए अलग-अलग मुआवजा के लिए मुकदमा दायर कर बहुराष्ट्रीय कम्पनी को परेशन कर सकते हैं, इस डर से भारत सरकार ने 1985 में एक कानून लाया ताकि उस बहुराष्ट्रीय कम्पनी का बचाव किया जा सके। उस कानून के मुताबिक मुआवजा की मांग करने की जिम्मेदारी तथा अतीत में हो या वर्तमान में या फिर भविष्य में उस बहुराष्ट्रीय कम्पनी से सौदेबाजी करने का पूरा अधिकार भारत सरकार को ही होगा, पीड़ितों को नहीं होगा। इस कानून का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने 1989 में न्यायालय के बाहर अत्यंत अल्प मुआवजे के लिए समझौता कर लिया। 330 करोड़ डॉलर की बजाए मात्र 47 करोड़ डॉलर मुआवजा काफी है बताकर निर्लज्ज समझौता कर लिया। इस समझौते को उच्चतम अदालत ने भी मानते हुए तब तक चल रहे सभी मुकदमों को दरकिनार कर दिया।

इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को सजाएं देने का जहां तक सवाल है, सीबीआई (केन्द्रीय जांच ब्यरो) ने इस पर आपराधिक जांच के बाद 1987 में एक अभियोग पत्र दायर किया जिसमें अभियुक्तों पर धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) लगाई गई थी। लेकिन उच्चतम अदालत ने 1996 में उसे धारा 304-ए (लापरवाही से मौत) में बदल दिया। पहली धारा के तहत कम से कम 10 साल से आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान था, जबकि दूसरी धारा में अत्यधिक सजा मात्र 2 साल तक ही हो सकती है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एएम अहमदी जिसने इस केस में धारा नरम की थी, यूनियन कार्बाइड द्वारा भोपाल में स्थापित भोपाल हॉस्पिटल ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। साफ जाहिर से इस दलाल को अच्छा-खासा इनाम मिल गया। इसके बाद भी यह मुकदमा 12 साल चला। आखिरकार 7 जून 2010 को सुनाए गए फैसले में भारतीय प्रबंधन को बेहद कम सजाएं देने और जुर्माने लगाने के बाद मौके पर ही जमानत दे दी गई ताकि उन्हें जेल की सजा न भुगतनी पड़ सके।

भोपाल की यह त्रासद भरी अंतहीन कहानी छब्बीस साल पुरानी है। लाखों लोगों की है। इसके बारे में कितना भी कहा जाए तो कम ही होगा। लेकिन इस फैसले के बाद कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हें खास तौर पर चिन्हित करना चाहिए।

फैसले के बाद कई टिप्पणीकारों व राजनीतिक नेताओं ने इस फैसले पर और पूरे घटनाक्रम पर कई किस्म की टिप्पणियां की हैं। राजनीतिक पार्टियां और उनके विभिन्न गुट इस मौके पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए व निंदा करते हुए आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पूंजी का स्वभाव, सरकारी स्वभाव, प्रबंधन की लापरवाही, नौकरशाही की लापरवाही, राजनीतिक दलों की दरिंदगी, जांच एजेंसियों की गुलामी मानसिकता, न्यायव्यवस्था का पक्षपातपूर्ण रवैया, कुल मिलाकर भारत की जनता के साथ हुआ अपमान और अन्याय – इन सभी पर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन बहस को जानबूझकर दो-तीन मुद्दों पर ही केन्द्रित करते हुए खासकर मुआवजे तक सीमित किया जा रहा है। पूरी एहतियात बरत रहे हैं कि बहस राजनीतिक-आर्थिक कारणों और समाधानों की ओर तथा अपराधियों को सजा की तरफ न जाए।

उस समय मध्यप्रदेश में और केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेसी राजनेताओं से इससे हटकर दूसरी तरह से बरताव करने की उम्मीद ही नहीं कर सकते। देश को 21वीं सदी में ले जाने का दंभ भरकर, भारतीय समाज को साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पहियों से बांध देना ही उसके लिए उपाय मानने वाली राजीव गांधी सरकार ही पूरी तरह इसका दोषी है। मध्यप्रदेश के

तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने हादसे के तीसरे ही दिन हजारों शवों के ऊपर खड़े होकर शर्मोहया का लिहाज तक छोड़कर खुलेआम घोषणा की थी कि 'किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाएंगे और किसी को भी प्रताड़ित नहीं करेंगे' जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोपाल अपराध में कांग्रेस की क्या भूमिका रही। ऐसा करने का कारण भी है। यूनियन कार्बाइड ने 1 जून 1982 से लेकर 31 मई 1983 के बीच अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह की चुरहट चिल्ड्रंस वेलफेयर सोसाइटी को डेढ़ लाख रुपए चंदा दिया था।

सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आज कांग्रेस की आलोचना कर रही तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी भोपाल अपराध में भागीदारी है। इन छब्बीस सालों में मध्यप्रदेश में दस साल भाजपा की सरकार चली। उन दस सालों में सरकार की तरफ से भाजपा ने भोपाल के मामले में तिनका भर काम भी नहीं किया। अब अदालत द्वारा दोषियों को कम सजा देने पर हाय तौबा मचाने वाली भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2002 में यूसीआईएल के अध्यक्ष और इस अपराध के लिए मुख्य भारतीय जिम्मेदार केशुब महिन्द्रा को पद्मभूषण सम्मान दिया था। इन छब्बीस सालों में सीपीआई, सीपीएम समेत अन्य तमाम विपक्षी पार्टियां केन्द्र सरकार का अंदर से या बाहर से समर्थन करती आ रही हैं। इनमें से किसी एक पार्टी ने भी भोपाल के मामले में अपना मुंह तक नहीं खोला।

यह सिर्फ राजनीतिक पार्टियों तक सीमित मामला भी नहीं है। आधा-अधूरा अभियोग पत्र तैयार करने वाली सीबीआई, घोर विलम्ब करने वाली सभी अदालतें, अभियोग पत्र में कड़ी सजा की धारा को बदलने वाली सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत के उस फैसले को तुरंत नहीं बदलवाने वाली सरकारें, आखिर में यह फैसला सुनवाने वाला मजिस्ट्रेट - सबके सब इस अपराध में भागीदार ही हैं।

लेकिन इन सभी ने अपराध में सहयोग ही किया। अपराध दरअसल पूंजी का है, साम्राज्यवाद का है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का है, उनके हत्यारे स्वभाव का है। लेकिन यह सब जानने-बूझने के बाद भी भूमण्डलीकरण के नाम से इन हत्यारों को लाल कालीन बिछाकर देश में आमंत्रित किया जा रहा है।

1992 में शुरू होने वाली नई आर्थिक नीतियां, उदारीकरण व निजीकरण की नीतियां, नई वाणिज्य व आयात-निर्यात की नीतियां सभी भोपाल दुष्टता की धारावाहिकता ही हैं। उसके बाद इजारेदारी व अवैध व्यापार की रोकथाम करने वाले एमआरटीपी कानून को रद्द करना, विदेशी विनिमय मुद्रा को नियंत्रित करने वाले फेरा कानून को रद्द करना, विदेशी विनिमय मुद्रा के अवैध व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले फेमा कानून को लागू करना, भारतीय पेटेंट कानून में आमूलचूल बदलाव करने वाले सुधार करना, बैंकिंग व भीमा के क्षेत्रों में सुधार, डंकेल ड्राफ्ट को मानकर अपमानजनक शर्तों पर विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो जाना, शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी पूंजी का अनुमोदन करना, सभी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना, सभी क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व विदेशी पूंजी को अनुमति देना, विशेष अर्थिक क्षेत्रों के नाम से लाखों एकड़ जमीनें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके दलालों को सौंपना... इस तरह पिछले 20 सालों में भारत सरकार और राज्य सरकारों ने हजारों भोपालों के लिए जमीन तैयार की... कर रही हैं। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के एक मात्र लक्ष्य से काम कर रही हैं।

जनता के रोजगार, जीवन, सुरक्षा और भविष्य को बेहद खतरे में डालने वाली इन नीतियों को बनाने और लागू करने में इन राजनीतिक पार्टियों के बीच कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। तमाम राज्यों में जहां अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए लाल कालीन बिछाने वाली नीतियां ही लागू हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए जनता की बलि चढ़ाने वाली नीतियां ही लागू हैं।

भोपाल के हादसे से सौ गुना खतरनाक योजना के लिए फिलहाल केन्द्र सरकार जमीन तैयार कर रही हैं। पहले से किए गए नागरिक परमाणु बिजली उत्पादन समझौते की धारावाहिकता में अब लाए गए परमाणु दायित्व विधेयक से, बेशक, न सिर्फ भोपाल जैसी हजारों दुर्घटनाओं को दोहराया जाएगा, बल्कि परमाणु दुर्घटना से हजारों लोगों के मारे जाने से भी कम्पनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा इस विधेयक में सरकार ने लिखित रूप में पेश किया।

आज हमारे देश के शासक वर्ग साम्राज्यवादियों के सामने, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सामने पूरी तरह घुटने टेके हुए हैं। हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों और सस्ते मानव श्रम को लूटने के प्रयास में साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और उनके दलालों की कम्पनियां जनता की जानों और देश के पर्यावरण को होने वाले खतरे का जरा भी ख्याल नहीं रखतीं। अगर हादसे हो भी जाते हैं और मजदूर व जनता की बड़ी संख्या में मौतें भी होती हैं तो उन कम्पनियों की जवाबदेही को कम से कम करने पर भारत सरकार जुटी हुई है। दोषियों को सजा दिलवाने की संभावनों को न्यून से न्यूनतर करती जा रही है। साम्राज्यवादी कम्पनियां हमारे देश की सम्पदाओं को कम से कम जोखिम व जवाबदेही से लूटकर ले जा सकें, यही 'विकास' के नाम पर बनाई जा रही सरकारी नीतियों और कानूनों का निचोड़ है। अगर हमारे देश को ऐसे हादसों से बचाना है, हमारी सम्पदाओं को बचाना है और हमारे पर्यावरण को बचाना है, तो इन साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश से बाहर खदेड़ देना होगा। आत्मनिर्भरता पर आधारित होकर देश के संसाधनों और पर्यावरण का संतुलित व तर्कसंगत प्रयोग करते हुए, देश की विशाल श्रमशक्ति को सही उपयोग में लाते हुए एक जन-हितैषी राजनीतिक-आर्थिक नीति को अमल में लाने के लिए व्यापक रूप से व एकजुटता से संघर्ष करने होंगे। इस राह में सबसे बड़े रोड़े के रूप में मौजूद इस शोषणकारी व दमनकारी व्यवस्था को जड़ से बदलने के लक्ष्य से जारी क्रांतिकारी संघर्ष के साथ इन संघर्षों का तालमेल बिठाना होगा। यही एक मात्र विकल्प है। ★

नारायणपटना आदिवासी किसान संघर्ष :
जमीन के ज्वलंत सवाल को फिर एक बार लाया सामने!

20 नवम्बर 2009 के पहले 'नारायणपटना' के बारे में शायद ही किसी को मालूम होगा। कम से कम उसका नाम तक किसी ने नहीं सुना होगा। क्योंकि वह कोई खास शहर नहीं है या कोई बड़ा कस्बा भी नहीं जिसे लोग जान सकें, समझ सकें। वह एक ब्लॉक मुख्यालय भर है। एक आदिवासी बहुल इलाका है जिन्हें समाज उतनी तवज्जो नहीं देता। (हालांकि समाज की उदासीनता के बावजूद भी ऐसे आदिवासी इलाकों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ज्यादा 'तवज्जो' दे रही हैं जिससे वर्तमान इतिहास में उथल-पुथल मची हुई है।)

20 नवम्बर को हुई अंधाधुंध पुलिसिया गोलीबारी और इसके फलस्वरूप दो लोगों की जानें चली जाने के बाद 'नारायणपटना' देश की जनता से परिचित हो गया।

दो जानें जाने के बाद ही वहां हो रही हिंसा और आतंक का सिलसिला प्रकाश में भले ही आया हो, दरअसल उक्त गोलीबारी की घटना से कुछ महीने पहले से लेकर आज तक नारायणपटना का समूचा इलाका लौह जूतों तले रौंदा जा रहा है। फिलहाल सिर्फ नारायणपटना कस्बे में ही बीएसएफ और सीआरपीएफ की दो बटालियनें और अन्य बलों के साथ मिलकर कुल तीन हजार सशस्त्र बल तैनात हैं। पूरे दक्षिण ओड़िशा में पांच बटालियनें तैनात हैं।

छसि मुलिया आदिवासी संघो की एक रैली

देश की सरहदों पर शत्रु सैनिकों से लड़ने के लिए बनाए जाने वाले इन अर्ध-सैनिक बलों को आखिर इस आदिवासी इलाके में क्यों तैनात किया गया?

हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर आदिवासी इलाके पुलिस व अर्ध-सैनिक बलों के लौह पैरों तले कुचले जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर इसके कई कारण दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन अंतरवस्तु एक ही है - उस इलाके के लोगों का अस्तित्व शासक वर्गों को बर्दाश्त नहीं है। हालांकि शासक वर्ग जो कारण बता रहे हैं, खासकर हाल के दिनों में किसी भी संघर्ष को कुचलने के लिए वो जिस बहाने से काम चला रहे हैं, वह है उन इलाकों में माओवादियों की उपस्थिति। इस बहाने से चाहे कितनी भी हिंसा मचाई जा सकती है। चाहे कितनी भी हत्याएं की जा सकती हैं। और चाहे कितना भी खून बहाया जा सकता है। क्योंकि आखिर वो 'देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा' जो हैं।

दरअसल 'नारायणपटना' का दुनिया से परिचय पुलिस की गोलीबारी से या उसमें गई हुई दो जानों की वजह से नहीं होना चाहिए था। वहां जारी एक जीवन-संघर्ष की वजह से उसका दुनिया से परिचय होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह शासक वर्ग संघर्षों का दमन करते हैं, उसी तरह उनके तलवे चाटने वाले प्रसार माध्यम, यानी मीडिया संघर्ष की खबरों को दबाकर रखते भी हैं। वरना, उन्हें डर है, खबरों से ऐसे कई और संघर्षों की नींव पड़ सकती है। हालांकि कभी-कभी ऐसी अनिवार्य स्थिति आ ही जाती है जिसमें कुछ खबरें बाहर निकलकर आ जाती हैं जो अक्सर अर्ध-सत्य होती हैं या फिर तोड़ी-मरोड़ी गई होती हैं। ऐसे ही हालात में 'नारायणपटना' रोशनी में आ गया।

नक्सलबाड़ी की तर्ज पर आंध्रप्रदेश में जमीन के सवाल को मजबूती से एजेंडे पर लाने का श्रेय श्रीकाकुलम संघर्ष को जाता है। श्रीकाकुलम आदिवासी किसान संघर्ष की विरासत को जारी रखते हुए उसी तर्ज पर फिर एक बार जमीन के सवाल को केंन्द्र बिंदु बनाया है मौजूदा नारायणपटना संघर्ष ने। नारायणपटना संघर्ष किन हालात में उभरकर सामने आया, यह समझने के लिए हमें इतिहास पर सरसरी नजर डालनी होगी।

ओड़िशा राज्य के कोरापुट जिले का एक ब्लॉक (विकासखाण्ड) है नारायणपटना। भारत से भी ओड़िशा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। और ओड़िशा से कोरापुट पिछड़ा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही भारत में जहां गरीबी 26 प्रतिशत है, वहीं ओड़िशा में 47 प्रतिशत है। अविभाजित कोरापुट जिले को चार जिलों में - कोरापुट, रायगड़ा, मलकानगिरी और नवरंगपुर - बांटने से पहले वहां गरीबी 84 प्रतिशत थी।

इतने पिछड़े जिले में एक तहसील के रूप में रहे नारायणपटना फिलहाल दो ब्लॉकों - नारायणपटना और बंदुगांव - में बंटा हुआ है। नारायणपटना ब्लॉक में कुल 9 पंचायतें हैं। यहां प्रमुख रूप से कुई आदिवासी निवासरत हैं। पूरे ब्लॉक की आबादी 35 हजार से ज्यादा है जिसमें कुई आदिवासियों की संख्या 30 हजार से ऊपर (यानी 81.58 प्रतिशत) है और दलितों का प्रतिशत 7.13 है।

हालांकि यह इलाका ऊंचे पहाड़ों का है, लेकिन अपेक्षाकृत जंगल कम ही है। इसलिए वनोपजों से होने वाली आमदनी भी

नारायणपटना में संघर्ष के शोले भड़काने वाले कॉमरेड सिंगन्ना और आंद्रु को लाल सलाम!

'जंगल पर अधिकार आदिवासियों का है!' और 'जमीन पर शोषित जनता का हक हासिल करने के लिए संघर्ष ही एक मात्र रास्ता है!' – इन नारों से जमींदारों, जालिम मुखियाओं और भाड़े के पुलिस बलों का मुकाबला करते हुए 20 नवम्बर 2009 को नारायणपटना में हुई गोलीबारी में कॉमरेड सिंगन्ना और कॉमरेड आंद्रु शहीद हो गए। 30 वर्षीय कॉमरेड केंडरुका सिंगन्ना का जन्म एक बेहद गरीब कुई आदिवासी परिवार में हुआ था। उनका गांव पोड़ापोद्रा था। जबसे होश संभाला, उन्होंने अपने और आसपास के गांवों में गैर-आदिवासी लुटेरों, जमींदारों, वन विभाग के अधिकारियों और साहुकारों की लूटखसोट और जुल्मों को ही देखा। वह खुद भी इसका शिकार थे। बचपन से ही वह विद्रोही स्वभाव के थे और हर दम शोषण की खिलाफत ही की उन्होंने। 2004 में नारायणपटना में गठित छसि मुलिया आदिवासी संघो में कार्यकर्ता बनकर कदम-दर-कदम जनता के एक जुझारू नेता के रूप में उभरकर सामने आए थे। हथियार उठाए बिना जनता को कुछ भी हासिल नहीं होगा, इस सच्चाई को समझते हुए उन्होंने 'घेनुवा वाहिनी' के नाम से नौजवानों को लेकर एक मिलिशिया का गठन कर उसकी अगुवाई की। तमाम मिलिटेंट कार्रवाइयों और हमलों में आगे रहते हुए उन्होंने जनता का हौसला बढ़ाया और उत्साहित किया। जनता में यह विश्वास मजबूती से बैठ गया कि 'सिंगन्ना रहेंगे तो हम जरूर जीतेंगे...'। भोली-भाली जनता यह भी मानती थी कि सिंगन्ना को गोली नहीं लग सकती, उन पर बंदूक नहीं चल सकती और कोई भी ताकत उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता को उन पर कितना आराधना भरा विश्वास रहा होगा।

कॉमरेड नाचिका आंद्रु का जन्म बलियापुट गांव के एक गरीब कुई आदिवासी परिवार में हुआ था। छसि मुलिया आदिवासी संघो की गतिविधियों की शुरूआत इसी गांव से हुई थी। चूंकि संगठन के नेता नाचिका लिंगा उनके रिश्तेदार ही थे, इसलिए छोटी उम्र से ही वह संगठन की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने लगे थे। और बाद में गठित 'घेनुवा वाहिनी' में भी वह सदस्य बने थे। 20 नवम्बर को नारायणपटना में हुए विरोध प्रदर्शन में उन्होंने भी भाग लिया था, जिस दौरान हुई पुलिस की गोलीबारी में वह शहीद हो गए। शहादत के समय वह मात्र 25 बरस के नौजवान थे।

आदिवासियों के संघर्षमय इतिहास में शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ हुए अनगिनत विद्रोहों के दौरान कई योद्धा शहीद हो गए। उन्हीं के नक्शेकदम पर चलते हुए अब कॉमरेड्स सिंगन्ना और आंद्रु भी शहीद हुए। आइए... इन शहीदों की संघर्षशील विरासत को जारी रखने की कसम खाएं। ★

कम ही है। मुख्य रूप से खेतीबाड़ी पर ही निर्भरता है। इसलिए यहां की जनता ने काफी पसीना बहाकर ऊंचे पहाड़ों को भी खोद-खोदकर खेती योग्य जमीनें तैयार कर लीं। राजाओं के समय में ही उनके पट्टे भी हासिल किए थे। लेकिन ये जमीनें एक-एक कर उनके हाथों से चली गईं।

श्रीकाकुलम संघर्ष के दिनों में जमींदार और साहूकार जिला छोड़कर भाग गए थे, यह इतिहास हमें मालूम है। उस तरह भागे हुए लुटेरों में से ज्यादातर पड़ोस में स्थित कोरापुट जिले में बस गए थे। नारायणपटना इलाके में भी आकर बसे थे। उनमें साहूकार, सुंडी, ब्राह्मण और डुम्बा लोग थे। इन लुटेरों ने कई तरीकों में आदिवासियों की कृषि जमीन को कब्जा करना शुरू किया। इस तरह कब्जाने वालों में साहूकारों के साथ-साथ सुंडी प्रमुख हैं। आबादी के हिसाब से भी ये लोग ज्यादा हैं। डुम्बाओं को इन सभी से जोड़कर देखा नहीं जा सकता। मूलत: ये लुटेरे नहीं थे, पर आदिवासियों के भोलेभालेपन का फायदा उठाकर वो भी दबंग बन गए। हालांकि इन चारों जातियों में गरीब भी हैं।

इनमें से ज्यादातर लोग शराब के ठेकेदार बन गए। इन्होंने इस पूरे इलाके में बड़ी-बड़ी शराब भट्टियां खोलकर बड़े पैमाने पर शराब तैयार कर आदिवासियों को शराबखोर बना दिया। शराबखोरी के कारण कर्ज का बढ़ना और कर्ज के तहत आदिवासियों की जमीनें हड़पना, यह सिलसिला चलता रहा। पहले एकाध एकड़ जमीन खरीद लेते हैं और बाद में उसके इर्द-गिर्द मौजूद सारी जमीनों को हड़प लेते हैं। नहरों के नीचे स्थित आदिवासियों की जमीनों को पानी देना बंद करवा देते हैं और इस प्रकार पानी न मिलने के कारण दो साल खेती नहीं करने से उस बहाने जमीनें हड़प लेते हैं। ये लुटेरे वर्ग यहां दुकानें खोलकर उनके जरिए भी जनता का शोषण करते हैं। दुकानों से उधारी पर सामान देते हैं और झूठमूठ का हिसाब बनाकर कर्ज के तहत जमीनें भी छीन लेते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने यहां की संस्कृति को भी बदल डाला। शादियों और तीज-त्यौहारों में बाजा-गाजा और रिकॉर्ड डांस की आदत बनाई जिससे खर्च बढ़ गया। ऐसे खर्चों के बदले भी कई लोगों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार, कई किस्म के बहानों से ही नहीं, बल्कि बिना किसी बहाने के भी जोर-जबर्दस्ती से अपनी पसंद की जमीनें हड़पना उनके लिए आम है।

सभी आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की जमीनों पर कानूनी तौर पर हक जमाने के लिए गैर-आदिवासी सामंतों द्वारा अपनाई जाने वाली कुटिल चाल है आदिवासी महिलाओं से

दिखावटी शादी कर लेना। दूसरे शब्दों में बताया जाए तो 'रखैल' बनाकर रख लेना। इन महिलाओं के नाम से पट्टे बनवा लेना। नारायणपटना के कुछ जमींदारों के पास ऐसी चार-पांच आदिवासी 'पत्नियां' हैं, इससे समझा जा सकता है कि अपनी संपत्तियों और सत्ता को बचाने के लिए वो किस तरह पितृसत्ता का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से एक-एक जमींदार ने सैकड़ों एकड़ जमीनों पर कब्जा जमा लिया। यहां पर ज्यादातर लोगों के पास बेनामी पट्टे हैं। और बहुत सारी जमीनों को बिना किसी पट्टे के ही इन गैर-आदिवासी जमींदारों ने हथिया लिया।

इस तरह इस इलाके के आदिवासी कई प्रकार की धोखाधड़ियों और जोर-जबर्दस्ती का शिकार होकर अपनी पुश्तैनी जमीनों से वंचित हो गए जिन पर उन्होंने अपना खून-पसीना बहाया था। अब वे अपनी ही जमीनों पर मजदूरी करने पर विवश हो गए।

आदिवासियों की जमीनों की खरीद और बिक्री को प्रतिबंधित करने वाला कानून 2/56 भी जमीनों को आदिवासियों के हाथों से जमींदारों के कब्जे में जाने से रोक नहीं सका। (दरअसल यहां खरीद या बिक्री कम ही हुई है। चूंकि धोखाधड़ी या जोर-जबर्दस्ती से ही ज्यादातर जमीनें हड़प ली गईं, इसलिए क्या यह कहा जा सकता है कि कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है!?)

नारायणपटना की संघर्षरत महिलाएं

इस तरह आदिवासियों की जमीनें हड़प लेने वाले ये गैर-आदिवासी लुटेरे और भी कई रूपों में उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। आदिवासियों को उनकी खुद की जमीनों में मजदूर बनाने के बाद वो कम से कम मजदूरी का भुगतान भी न करते हुए बेगारी करवाते हैं जिससे आदिवासियों की जिंदगी बद से बदतर हो गई। खाने के लिए एक बैल देकर कई एकड़ जमीनों में फसलें कटवाना, मिंजाई और अनाज को अपने कोठे तक ढुलवाना, आदि सभी काम करवा लेते हैं। इसी प्रकार एक बैल देकर एक किलोमीटर के दायरे में इमली के सभी पेड़ों से इमली गिराकर बीज निकालकर देना होगा। पोडापोद्रा नामक एक गांव में एक हजार इमली के पेड़ हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासियों के श्रम का जमींदार कितना ज्यादा शोषण करते हैं।

शोषण की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उल्टे-सीधे बहानों से आदिवासियों पर अंधाधुंध जुर्माना लगा देते हैं। गिरी हुई इमली को कोई बीन लेता है तो भी जुर्माना लगाते हैं। हाथ में पकड़कर ले जाने से 50 रुपए और लंगोटी में बांधकर ले जाने से 80 रुपए का जुर्माना वसूलते हैं। ऐसे जुर्मानों के तहत भी जमीनें हड़प लेते हैं।

सूदखोरी से भी ये लुटेरे जनता का शोषण करते हैं। मनमानी ब्याज दर और चक्रब्याज से जनता को बेतहाशा लूट लेते हैं। इन कर्जों के तहत भी जमीनों को कब्जा लेते हैं। जमीनें ही नहीं, आदिवासियों के कल्याण के नाम से सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली छिटफुट तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं का भी यही लोग फायदा उठा लेते हैं। आदिवासियों के नाम से बने छात्रावास आदि भी इनको ही मिल गए। इन गैर-आदिवासियों में ज्यादातर ठेकेदारी करते हैं। वो जो काम करवाते हैं उसमें कम मजदूरी का भुगतान कर जनता का शोषण करते हैं। हाट बाजारों के जरिए भी जनता पर मनमानी लूटखसोट चलती है। हाट बाजार में आदिवासी कुछ भी खरीदते हैं या बेचते हैं, तो दोनों स्थितियों में उनका शोषण ही होता है।

इस तरह आदिवासियों का खून-पसीना चूसकर वो करोड़पति बन गए। नारायणपटना में बनी इन लोगों की इमारतें इनकी लूटखसोट और आदिवासियों की बदहाल जिंदगी की तस्वीर हैं। अंधाधुंध संपदाओं के स्वामी बनने के बाद ये लुटेरे यहां की बुर्जुआई राजनीतिक पार्टियों को भी अपने इशारों पर चलाने लायक बन गए हैं। इन सभी ने भाजपा, बीजेडी (बिजू जनतादल) और कांग्रेस में नेता के रूप में स्थापित होकर राजनीतिक सत्ता पर अपना शिकंजा कसा। इस तरह वो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी लूटखसोट की राह में कोई बाधा उत्पन्न न हो। जमीनें देने से इनकार करने वालों पर शारीरक हमले, जुल्म और हत्या तक करते हैं। इनके जुल्मों का शिकार कई लोग स्थाई रूप से अपंग हुए हैं या फिर बीमार हुए हैं। महिलाओं के साथ घोर अत्याचारों की कई घटनाएं घटी हैं। यौन अत्याचार को वो अपनी लूटपाट को जारी रखने के लिए एक मजबूत साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आदिवासियों को झूठे मामलों में फंसाकर पुलिस थानों व अदालतों का चक्कर लगवाने जैसी कई प्रताड़नाएं भी दी जाती हैं। गांव के सुअर या मुरगे को काटकर खाने से भी जंगली पशुओं का शिकार करने का इलजाम लगाकर झूठे मामलों में फंसाया करते हैं।

इस इलाके के किसी भी आदिवासी से बात करें तो वह आपको आपबीती बताएगा कि जमींदारों और दबंग लोगों के हाथों उन्हें क्या-क्या तकलीफें सहनी पड़ती थीं। इन तकलीफों के कारण तथा वहां रोटी का जुगाड़ मुश्किल हो जाने से कई लोग तमिलनाडु, केरल, बेंगुलूरु और विशाखापटनम जैसी जगहों में पलायन कर गए। मिसाल के तौर पर पोडापद्रा गांव में एक समय 300 कुई परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब 70 परिवार ही रह गए। ये भी अपने गांव में हो रहे जुल्मों से तंग आकर पुराने गांव को छोड़कर नदी के पार नए मकान बनाकर रह रहे

हैं। इस तरह कुई आबादी घटती जा रही है।

इन आदिवासियों पर इस प्रकार का शोषण, दमन, जुल्म और अत्याचार पिछले साठ सालों से जारी हैं। आखिर इनको कब तक सहते रहा जाए? और तो और, देश भर में दमन के खिलाफ कई विद्रोह करने का इतिहास आदिवासियों का रहा है। इसके तहत ओड़िशा में भी कुई लोगों के विद्रोह हुए थे। कोरापुट में लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में होने वाला ब्रिटिश-विरोधी विद्रोह सुविख्यात है। ऐसी विरासत आखिर उन्हें कब तक सिर झुकाकर जीने की इजाजत देगी?

इसीलिए उनमें इस परिस्थिति को लेकर तीखे विचार शुरू हुए थे कि वो कैसे अपनी ही जमीनों में पराए बन चुके हैं और अपनी ही जमीनों में गुलाम बन गए हैं। एक जमींदार के पास नौकर के रूप में काम करने वाले नाचिका लिंगा के मन में भी ऐसे विचार शुरू हुए थे। जनता में धीरे-धीरे चेतना जाग उठी। उन्होंने मान लिया कि उन्हें गुलामी सी जिंदगी से मुक्ति तभी मिल सकती है जब उनकी खोई हुई जमीनें वापस मिल जाएं। नाचिका लिंगा एक नेता के रूप में उभरकर सामने आया। उसी समय, यानी 2004 में सीपीआई (एमएल) कानू सान्याल के गुट से सम्बद्ध 'छसि मुलिया आदिवासी संघो' (किसान मजदूर आदिवासी संगठन) का इस इलाके में विस्तार हुआ। नाचिका लिंगा और दूसरे लोगों ने सोचा कि इस संगठन में शामिल होकर लड़ने से वे खोई हुई उनकी जमीनों को फिर से हासिल कर सकते हैं। उन्होंने संगठन में शामिल होकर सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया। इसी सिलसिले में सिंगन्ना नामक एक और जुझारू नेता उभरकर सामने आए। परिणामस्वरूप कम समय में ही यहां पर छसि मुलिया आदिवासी संघो मजबूत बन गया। संगठन के नेतृत्व में जून-जुलाई 2004 में नारायणपटना पंचायत के तहत बसनापुट, डेक्कापारा, पोडापद्रा और बलियापुट गांवों में सबसे पहले जमीन-संघर्ष की शुरूआत हुई। इस संघर्ष की बदौलत 118 एकड़ जमीन जमींदारों के कब्जे से आजाद होकर फिर से आदिवासियों के पास आ गई। तब तक आदिवासियों का निर्मम शोषण करने वाले चित्रा बिडिके, महंकालि बिडिके, कोंटो पोरिडि आदि गैर-आदिवासी जमींदारों को गांवों से भगा दिया गया। सहज ही, इस संघर्ष ने जहां एक तरफ यहां की उत्पीड़ित जनता में उल्लास, उत्साह और उत्तेजना का संचार किया, वहीं दूसरी तरफ लुटेरे शासक वर्गों में डर और चिंता पैदा की।

आज जिस तरह सभी आदिवासी इलाकों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गिद्ध दृष्टि है, उसी प्रकार इस इलाके पर भी है क्योंकि यहां कई प्रकृतिक सम्पदाओं, खासकर उच्च कोटि के बॉक्साइट का भण्डार है। ऐसे इलाके में किसी भी संघर्ष या चेतना को शासक वर्ग क्यों बर्दाश्त करेंगे?

इसीलिए इस चेतना को नोचने की कोशिशें शुरू कीं। फरवरी 2004 में कोरापुट के शस्त्रागार पर माओवादियों ने हमला किया था। 2005 में नाचिका लिंगा पर यह मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला गया जबकि उनका न उस हमले से कोई सम्बन्ध था, न ही माओवादियों से। नेता को जेल में डालकर संघर्ष को रोकना चाहा। लेकिन संघर्ष रुका नहीं। जेल के अंदर से और जेल से रिहा होकर नाचिका लिंगा ने जनता का मार्गदर्शन करना जारी रखा। जुझारू संघर्षों के अलावा अदालतों में भी संघर्ष करने का फैसला लिया गया। जमीन पर अपने मालिकाना हक को साबित करने के लिए उन्होंने अदालतों का चक्कर काटा। एक मामले में 50 सेंट की जमीन के लिए अदालत जाकर लोगों ने जीत हासिल की। लेकिन इस जीत के लिए उन्हें 50 हजार रुपए खर्च करने पड़े। इस केस में स्थानीय कलेक्टर ने आदिवासियों का पक्ष लिया। फिर भी खर्च करना ही पड़ा। अदालत के अंदर और कागजों पर उन्होंने जमीन भले ही जीत ली हो, पर अदालत के बाहर और व्यवहार में जमीन को वो हासिल नहीं कर सके। सिर्फ इस जमीन को ही नहीं, कई जमीनें अदालतों में जीत ली गईं। लेकिन किसी भी अदालत ने जमींदारों के शिकंजे से उन जमीनों को छुड़वाकर आदिवासियों को सुपुर्द नहीं किया। इस तरह जनता ने अदालतों के ढोंग व निष्क्रियता को अपने अनुभव के जरिए समझ लिया। उसी समय इसी ब्लॉक के बोरिगि और नागुलाबेड्डा पंचायतों में माओवादी पार्टी के नेतृत्व में जनता ने बड़े पैमाने पर गोलबंद होकर शराब की भट्टियों पर हमले किए और 150 एकड़ जमीन को जमींदारों के कब्जे से मुक्त किया जिसका आदिवासियों के बीच बंटवारा किया गया। इन संघर्षों ने छसि मुलिया आदिवासी संघो को उत्साहित किया।

इसी प्रेरणा से नारायणपटना के आदिवासियों ने जनवरी 2009 में देशी व अंग्रेजी शराब के खिलाफ एक जुझारू संघर्ष शुरू किया। चूंकि वे जानते हैं कि शराब के जरिए उनकी जमीनों को जमींदारों ने कैसे हड़प लिया था, इसलिए उन्होंने अपने संघर्ष का निशाना शराब के धंधे पर और शराब बनाने वालों पर साधा। पूरे ब्लॉक में मौजूद सरकारी व निजी शराब दुकानों और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर हजारों जनता ने हमले

किए। शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। शराब ले जाने वाले वाहनों को ध्वस्त कर दिया। इसका नतीजा ही है कि तबसे लेकर आज तक ब्लॉक के ज्यादातर गांवों में शराबबंदी लागू है। दरअसल इस संगठन का शराब विरोधी संघर्ष का लम्बा इतिहास रहा है। दूसरे जिलों में भी इस संगठन ने यह संघर्ष चलाया था। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ता कई बार गिरफ्तार हुए थे और जेल भी जा चुके थे। लेकिन चूंकि वह संघर्ष सिर्फ धरना, प्रदर्शन और आवेदन देने तक ही सीमित रहा, उसे जुझारू तरीके से नहीं चलाया गया था, इसलिए कोई नतीजा नहीं निकला था। जुझारू रूप से चलाने से अच्छा नतीजा निकलकर आया।

नाचिका लिंगा आदि लोगों के क्रांतिकारी विचार उस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को रास नहीं आए। उसने दबाव डाला कि मौजूदा परिस्थितियों में जमींदारों के कब्जे वाली जमीनों के लिए संघर्ष न करें और वन जमीनों के कब्जे तक ही सीमित रहें। लेकिन नारायणपटना ब्लॉक इकाई प्रदेश नेतृत्व के तर्कों से सहमत नहीं थी। नाचिका लिंगा और उनके साथियों ने प्रस्ताव किया कि अप्रैल 2009 में आए चुनावों का बहिष्कार कर जमीन कब्जाने के लिए आदिवासियों को गोलबंद किया जाए। इस प्रस्ताव को मानने से इनकार करते हुए उस पार्टी की राज्य कमेटी ने नाचिका लिंगा, गणनाथ पात्रो, तपन मिश्र जैसे नेताओं को बहिष्कार किया।

उक्त कार्रवाई से एक प्रकार से एक फायदा यह हुआ कि नारायणपटना संघर्ष में दक्षिणपंथी पार्टी द्वारा डाली जा रही रुकावटें दूर हो गईं। पार्टी से बरखास्त किए गए नाचिका लिंगा का नारायणपटना संगठन ने पूरा समर्थन किया। उन्होंने खुद को अलग संगठन के तौर पर अपने संघर्ष को जारी रखने का फैसला लिया।

लेकिन इस संघर्ष को किसी भी तरह कुचलने की ठान लेने वाले शासक वर्गों ने दमन की तैयारियां तेज कीं। गैर-आदिवासी जमींदारों और विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने मिलकर पुलिस की मदद से 5 मई 2009 को सलवा जुडुम की तर्ज पर 'शांति सेना' के नाम से एक निजी गुण्डा सेना का गठन किया। जिस दिन इसका गठन हुआ, उसी दिन इसने नारायणपटना में चार हजार की संख्या में एक जुलूस निकाला। इसने मांग की कि नाचिका लिंगा के नेतृत्व वाले छसि मुलिया आदिवासी संघो पर प्रतिबंध लगाया जाए; संगठन के नेताओं को गिरफ्तार किया जाए; और संगठन की अगुवाई में छीन ली गई जमीनों को फिर से जमींदारों के हवाले कर दिया जाए। अगले दिन से शांति सेना के गुण्डों ने गांवों पर हमले छेड़कर आतंक का तांडव शुरू किया। संगठन नेताओं के घरों को ध्वस्त करना, जो भी दिखता है उसकी पिटाई करना, यातनाएं देना, हवा में गोलियां दागना, घरों से अनाज, पैसा, बकरों और मुरगियों को लूटकर ले जाना उनका रोजमर्रा का काम बन गया। खाने के अन्न में एंड्रिन व मिट्टी तेल मिलाना, खाने के बरतनों में तम्बाकू चबाकर थूकना जैसी कई घिनौनी कार्रवाइयों को इन गुण्डों ने अंजाम दिया। इन तमाम हमलों में शांति सेना के साथ पुलिस भी भाग ले रही है।

अगर जमीन पर अपना हक कायम करना है और अपने अस्तित्व को बचाना है तो इस दमन का मुकाबला किए बिना जनता के सामने कोई चारा ही नहीं था। हथियारबंद हमलों का निहत्थे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध करना भी संभव नहीं है, इस बात को अनुभव से समझते हुए इस संगठन ने 'घेनुवा वाहिनी' के नाम से एक मिलिशिया का निर्माण किया। (घेनुवा एक आदिवासी योद्धा था जो बढ़िया तीरंदाज भी था। उसकी प्रेरणा से यह नाम रखा गया।) घेनुवा वाहिनी परम्परागत हथियारों से लैस हो गई। करीब 250 गांवों के हजारों लोग इस वाहिनी में शामिल हो गए। घेनुवा वाहिनी ने 'शांति सेना' का बहादुराना मुकाबला कर जहां-तहां उसके हमलों को नाकाम कर गुण्डों को मार-मार कर भगा दिया। इस प्रतिरोध का सिंगन्ना ने नेतृत्व किया।

शांति सेना को मार भगाने के बाद उत्साह के साथ संगठन ने 12 जून को जमीन-कब्जा दिन के रूप में घोषित किया। इसके अनुसार 12 जून को ब्लॉक के सात पंचायतों से करीब 250 गांवों से लोग निकले थे जिन्होंने जमींदारों के आक्रमण में रही 2,500 एकड़ जमीनों पर कब्जा कर उनमें लाल झण्डे गाड़कर हल चलाए। इसमें 700 एकड़ जमीन कोसाराजू और कुंजापोड़ी जैसे बड़े जमींदारों की थी जो नारायणपटना के पास रहते हैं। इसके बाद 159 गांवों में इन जमीनों का बंटवारा किया गया। कब्जाई गई जमीनों को ज्यादातर व्यक्तिगत तौर पर न बांटते हुए गांव के तौर पर सामूहिक रूप से बांटा गया।

यह संघर्ष सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रहा। इसका विस्तार खनन कार्यों के खिलाफ भी हुआ जो वर्तमान में आदिवासियों के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। इसी जिले के पोट्टंगी ब्लॉक के कोटिया, तुरिया और कंटी पंचायतों में फैली हुई पहाड़ियों को देवमाली पर्वतमाला कहा जाता है। समुद्रतल से 4,385 फुट की ऊंचाई पर 17 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यह फैली हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन पहाड़ियों में 3,700 लाख टन बाक्साइट के भण्डार हैं। इस पर्वतमाला से सटे हुए सिमिलिगुड़ा ब्लॉक में स्थित पंचमहल पर्वतमाला से नाल्को (राष्ट्रीय अल्यूमिनियम निगम) पिछले 30 सालों से बाक्साइट का उत्खनन करते हुए दामनजोड़ी (जहां अल्यूमिनियम प्लांट मौजूद है) रवाना कर रही है। अब देवमाली की पहाड़ियों को भी नाल्को ने पट्टे पर ले लिया। बाक्साइट निकालकर ले जाने के लिए उसने जरूरी सड़कें और अन्य ढांचा तैयार कर रखा है। किसी भी दिन वह खुदाई शुरू कर सकती है। गांवों को खाली कराने का आदेश निकल चुका है। इस तरह जिंदगी और मौत की समस्या से जूझ रही जनता ने कुछ संगठनों के साथ मिलकर 'देवमाली सुरक्षा समिति' का गठन कर संघर्ष शुरू किया। इस संघर्ष के समर्थन में छसि मुलिया आदिवासी संघो खड़ा हो गया। इस संगठन के समर्थन से 'देवमाली सुरक्षा समिति' ने सभी उत्पीड़ित तबकों की जनता को साथ लेकर

अप्रैल 2009 में 12 हजार लोगों से एक भारी आम सभा कर संघर्ष का आह्वान दिया। इस तरह जमींदारों के खिलाफ शुरू हुआ छसि मुलिया आदिवासी संघो का संघर्ष दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों के खिलाफ भी संघर्ष में बदल गया। इस तरह इस संगठन ने जनता को विभिन्न समस्याओं पर गोलबंद कर संगठित करते हुए छह ब्लॉकों में विस्तार किया।

सरकारी व्यवस्था पर बहुत पहले ही पूरी तरह विश्वास खो चुकी यहां की जनता ने संगठन को एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था के रूप में भी देखना शुरू किया है। वह हर समस्या के समाधान के लिए संगठन की तरफ देख रही है।

इसीलिए यह संगठन लुटेरी ताकतों की आंखों में किरकिरा बना है। मुख्य रूप से इस इलाके के जमींदारों, शराब माफिया, खदान माफिया और सरकार ने सांठगांठ के साथ संगठन पर, उसके नेतृत्व में जारी संघर्षों पर निशाना साधा। इनका दमन करने के लिए कई और योजनाएं बनाईं। इसके तहत नाचिका लिंगा, सिंगन्ना और रामपाडी (ये भी एक मुख्य नेता हैं) को असामाजिक तत्व बताते हुए पोस्टर चिपका दिए। ऐसी धमकी भरी घोषणा भी की कि अगर वे आंध्रप्रदेश में कदम रखते हैं तो पकड़कर गोली मार दी जाएगी। अपने प्यारे नेताओं को असामाजिक तत्व बताए जाने पर जनता में आक्रोश भड़क उठा। अक्टूबर महीने में करीब दो हजार लोगों ने नारायणपटना पुलिस थाने का घेराव कर पुलिस से माफी मंगवाई। इस तरह जनता की संगठित ताकत के सामने फिर एक बार पुलिस और सरकार को झुकना पड़ा।

संगठित चेतना से आगे बढ़ रही जनता अपने संघर्ष की बदौलत हासिल जमीनों में बोई गई फसलें काटने को तैयार हुई। संघर्ष को तोड़ने की ताक में बैठी पुलिस ने 19 नवम्बर 2009 को सुनियोजित तरीके से डुम्बागुड़ा गांव जाकर जनता को डराया-धमकाया कि वह माओवादियों को सहयोग दे रही है। महिलाओं के साथ अपमानजनक बातें कीं। संगठन को गालियां दीं। (दरअसल चार महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया जिसकी जानकारी देर से प्रकाश में आई।) इसका विरोध करते हुए, पुलिस से जवाब तलब करने का फैसला लेकर जनता 20 नवम्बर को नारायणपटना पुलिस थाने में गई। पहले करीब 200 लोग गए थे। और भी लोगों की कई कतारें आती ही रहीं। जो लोग पहले पहुंचे थे उन्होंने पुलिस से पूछना शुरू किया कि 'डुम्बागुड़ा जाने का क्या कारण था और जनता के साथ बदसलूकी क्यों की'। लेकिन पुलिस वाले बिना कोई जवाब दिए घमण्ड के साथ थाने में ताले लगाकर अंदर चले गए। इससे गुस्से में आए सिंगन्ना समेत घेनुवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ता फाटक को फांदकर अंदर चले गए। जाकर थाने के अधिकारी से जवाब मांगा। जब दोनों के बीच वाद-विवाद चल ही रहा था, ऊपरी मंजिल और नीचे मौजूद पुलिस वालों ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में सिर पर गोली लगने से आंद्रु नामक कार्यकर्ता मौके पर ही मारे गए। सिंगन्ना घायल होकर गिर पड़े थे। बाद में पुलिस वालों ने उन्हें पाशविकता के साथ कुल्हाड़ियों से काटकर मार डाला। इस घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल होकर तितर-बितर हो गए।

इस जघन्य कार्रवाई का राज्य और देश की कई जनवादी ताकतों ने पुरजोर विरोध किया। लेकिन सरकार ने, जो 'लोकतंत्र' शब्द को रटती तो है लेकिन उसके अर्थ को कभी नहीं समझती है, ने किसी भी जनवादी आवाज की बर्दाश्त नहीं की। तथ्यान्वेषण के लिए जाने वाले जनवादियों और महिला टीमों को 'शांति सेना' ने रोककर उन पर जुल्म किए। वहां जाने वाले सभी जनवादियों ने यही खुलासा किया कि नारायणपटना कस्बा एक यातना-शिविर में तब्दील हो गया। सिर्फ नारायणपटना में ही नहीं, बल्कि बंदुगांव, लकिमपुर, दामनजोड़ी जैसे कस्बों में भी कुल 8 शिविर हैं। इन सभी शिविरों में शांति सेना के गुण्डे मौजूद हैं। इन कस्बों में लोगों को चैन से सांस लेने का मौका भी नहीं है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जन जीवन पूरा कितना अस्तव्यस्त हुआ होगा।

अभी भी शांति सेना और उसके हमराह अर्ध-सैनिक बल लगातार गश्त और हमले करते हुए इस पूरे इलाके में आतंक का माहौल कायम रखे हुए हैं। कुई जनता के अस्तित्व के संघर्ष का नेतृत्व करते हुए जनता का अपार स्नेह व सम्मान प्राप्त करने वाले नाचिका लिंगा की हत्या करने के लक्ष्य से 'ऑपरेशन लिंगा' के नाम से बर्बर दमनचक्र चला रहे हैं। इस तरह हमले करते हुए जनता को गिरफ्तार कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, आत्मसमर्पण के लिए दबाव डाल रहे हैं और संगठन में सक्रिय काम करने वालों के घरों को ध्वस्त कर रहे हैं। इस प्रकार कुछ गांवों पर 15-20 बार हमले किए गए हैं, इससे परिस्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। 20 नवम्बर के बाद से अभी तक किए गए हमलों में 135 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें 20-30 प्रतिशत महिलाएं हैं। इनमें कई नन्हे शिशुओं की माताएं भी हैं। गिरफ्तार नेताओं में कुमुदिनी और गोपाल सिरिका शामिल हैं। 9 किशोर भी हैं। 14 फरवरी 2010 को बलियापुट गांव पर हमले के दौरान पुलिस ने एक युवती के साथ बलात्कार भी किया। डुम्बागुड़ा गांव के निवासी नारी की बेटी रिश्तेदारी के तौर पर बलियापुट गई हुई थी तो वहां चार पुलिस वालों ने उसके साथ पाशविकता के साथ बलात्कार किया।

इस तरह गिरफ्तारी के बाद जेल में डाले गए लोगों का हाल भी बहुत बुरा है, बुरा रहेगा भी। सरकार यह रट लगाती है कि जेल सुधार के मंदिर हैं, पर वास्तव में वह ऐसा कभी नहीं मानती। इसी का परिणाम है कि अप्रैल 2010 में पग्गम गांव के कोण्डागोर्रे गंगुलू की जेल में मौत हुई थी। उनकी लाश को घर पहुंचाने में जेल अधिकारियों ने लापरवाही बरती। इसके अलावा, जून 2010 में एक और व्यक्ति की मौत हुई है थी।

इस तरह आम जनता पर, या छसि मुलिया आदिवासी संघो, जो एक कानूनी संगठन है, पर किए जाने वाले इन फासीवादी हमलों को केन्द्र और राज्य सरकारें यह कहते हुए जायज ठहरा रही हैं कि ये माओवादियों के खिलाफ हमले थे। दरअसल

जायज ठहराने के लिए ही इसे माओवादी संघर्ष के रूप में चित्रित कर रही हैं।

दरअसल यहां की जनता ने आखिर क्या मांगा? अन्यायपूर्ण तरीके से हड़पी गई उनकी जमीनें लौटा देने की मांग की। यह मांग न सिर्फ न्यायपूर्ण है, बल्कि विधिसम्मत भी है। क्योंकि 2/56 कानून के मुताबिक आदिवासियों की जमीनों की खरीद-फरोख़्त और उन पर पराए लोगों का कब्जा अवैध है। जब जनता यह मांग रही है कि 'हमारी जमीनें हमें दो' तो उसका सारांश यह है कि वह सिर्फ उपरोक्त कानून को लागू करने की मांग कर रही है।

क्यों सरकार अपने ही बनाए हुए कानून को लागू करने से कतरा रही है? क्यों वह कानून का उल्लंघन करने वालों का पक्ष लेकर, उसे लागू करने की मांग करने वाले लोगों का दमन कर रही है?

जवाब साफ है! सरकार लुटेरे वर्गों के हितों के लिए कटिबद्ध है। वह कानून बनाती भी है, लागू करती है और उल्लंघन भी करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लुटरे वर्गों के हितों के लिए। कुछेक बार जनवादी ताकतों के दबाव में सरकार मजबूरन कुछ कानून बनाती तो है जो जनता के हित में हों, पर वह उन्हें कभी लागू नहीं करती। लागू करने की मांग को भी बर्दाश्त नहीं करती।

फिलहाल यहां की जनता यही मांग कर रही है कि उनकी जमीनें उन्हें लौटा दीं जाएं, जोकि सहज मांग है। लेकिन यह मांग शासग वर्गों के गले नहीं उतरेगी। क्योंकि यह ऐसी मांग है जो लुटेरे वर्गों की नींव को हिलाने का माद्दा रखती है। यह मांग वहां जड़ें जमा चुके जमींदारों के गले नहीं उतरेगी। वहां पैठ बनाई हुई और पैठ बनाने की कोशिश कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के गले भी नहीं उतरेगी।

इसलिए सरकार यही चाहती है कि इस संघर्ष को हर हाल में कुचल दिया जाए। अपने दमनचक्र को वैधता हासिल करने के लिए माओवादी का ठप्पा लगाने का हथकण्डा तैयार है। किसी भी जायज संघर्ष का दमन करना चाहे तो सरकारों ने नायाब तरकीब यह खोज निकाली कि उस पर 'माओवादी' होने का ठप्पा लगाओ। सरकार सोच रही है कि इससे जनता और नागरिक समाज से उसकी दमनकारी कार्रवाइयों के लिए समर्थन मिलेगा। लेकिन वो भूल रही हैं कि आखिरकार इससे उलटा नतीजा ही निकलेगा। क्यों सरकारों को जनता के हर न्यायपूर्ण संघर्ष के पीछे 'माओवादी' ही नजर आ रहे हैं, यह सवाल अपने आप में बहुत सारे सवालों का जवाब है। लुटेरी सरकारें यह भी भूल रही हैं कि इससे वो खुद ही माओवादियों के फैलने की उर्वरा जमीन तैयार कर रही है - उन जगहों में भी जहां अभी तक वे नहीं थे। आशा करेंगे कि नारायणपटना के संग्रामी आदिवासी अपने इस संघर्ष के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं का विश्लेषण कर, उसे नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए दीर्घकालीन जनयुद्ध के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और जमींदारों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों को धूल चटाकर शोषणविहीन व खुशहाल नए जनवादी भारत के निर्माण के लिए हो रहे जन संग्राम का अभिन्न हिस्सा बनेंगे। ✶

(... पेज 34 का शेष)

एक और दस्ते के साथ तालमेल करते हुए दूसरे रोज भी दिन भर जब तक दुश्मन रहा उसका पीछा करते रहे और हैरान-परेशान करते रहे। इस तरह पीएलजीए के बहादूर जवानों ने लगातार 13 घंटे तक दुश्मन के साथ जबरदस्त मुठभेड़ की और उसका डटकर मुकाबला किया और इसके अलावा भी 18-19 घंटे तक दुश्मन का पीछा करते हुए उसे हैरान-परेशान करने के लिए संघर्षरत रहे।

दुश्मनों ने एक भारी योजना के तहत इस कैम्प पर बहुत बड़ा हमला किया था। कैम्प में मौजूद नेतृत्वकारी कामरेडों की हत्या करना उसका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए 'ऑपरेशन ग्रीन हण्ट' का कमाण्डर-इन-चीफ विजय रमण जिला मुख्यालय चाईबासा में बैठकर इसका दिशा-निर्देश कर रहा था तथा आईजी रेजी डुंगडुंग और डीआईजी मनोज कुमार मिश्रा बंदगांव थाना से इसका संचालन कर रहे थे। इसमें उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कोबरा के चार बटालियान और खुंटी से दो, चाईबासा से छह, राँची से चार यानी सीआरपीएफ के 12 बटालियन और झारखण्ड जागुआर के बल इसमें शामिल थे। 13 जून 2010 के 'दैनिक जागरण' के अनुसार कुल मिलाकर इस कार्रवाई में 7,000 फोर्स को उतारा गया था। इसके अलावा ऑपरेशन को केन्द्रित कर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी 4-5 सौ की संख्या में फोर्स को तैनात किया गया था। इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक उपकरण जीपीएस का उपयोग किया गया था।

इस संघर्ष में पीएलजीए के बहादूर योद्धाओं ने बहुत ही शानदार मिसाल पेश की। अत्याधुनिक हथियारों, 2 हेलीकॉप्टर, जीपीएस जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित दुश्मन के इतनी काफी तदाद में बलों का 13 घंटे तक लगातार डटकर मुकाबला करते हुए उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। कई दुश्मनों को मार गिराया, घायल किया और हेलीकॉप्टर पर गोलियां दगीं। अन्ततः धूल चटाते हुए उसके बुरे मंसूबे को नाकाम कर दिया। इस संघर्ष में पीएलजीए के जवानों ने कॉमरेड माओ की छापामार युद्ध नीति के अनुसार राणनीतिक तौर पर 10 का मुकाबला 1 से और कार्यनीतिक तौर पर 1 का मुकाबला 10 से करते हुए संघर्ष के मैदान में एक हिस्से को घेरकर मार गिराते हुए आखिरकार दुश्मन को परास्त किया। आइए, पीएलजीए के हमारे इन जांबाज कॉमरेडों का लाल अभिनंदन करें और ममाइल की तर्ज पर दुश्मन का सफाया करते हुए पार्टी, जनताना सरकार और जनता की हिफाजत करने की कसम खाएं। ✶

मामाइल (पोरहाट) में पीएलजीए का शानदार प्रतिरोध - हजारों शत्रु बलों को दिया मुंहतोड़ जवाब!

झारखण्ड के पोरहाट इलाके में ममाइल गांव के पास एक राजनीतिक कार्यक्रम के तहत पार्टी का एक कैम्प चल रहा था, जिस पर 12 जून 2010 को हजारों शत्रु बलों ने एक भारी हमला किया। इस हमले का हमारी बहादुर पीएलजीए ने जबर्दस्त मुकाबला कर दुश्मनों को मार भगा दिया। पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनुवां थानान्तर्गत आने वाले इस गांव के पास लगे हमारे कैम्प को ध्वस्त कर नेतृत्वकारी शक्तियों की हत्या करने के बूरे मंसूबे से 'ऑपरेशन ग्रीन हॉक' के नाम से दुश्मन द्वारा किये गये हमले का पीएलजीए के बहादूर योद्धाओं ने डटकर मुकाबला करते हुए उसके बूरे मंसूबे को नाकाम कर दिया। इस जवाबी हमले में कोबरा के कम से कम 3 भाड़े के जवानों की मौत हुई तथा 6 को घायल कर दिया गया। घायलों को ले जाने आये हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया जिसमें तीन गोलियां लगीं और सुराख हो गई।

इस शौर्यपूर्ण प्रतिरोधी कार्रवाई में हमारे एक साथी कॉमरेड डेविड ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। लड़ाई के दौरन तुरंत कवर में नहीं जा पाने के कारण दुश्मन की गोली लगने से वह शहीद हो गये। हालांकि दुश्मन द्वारा 10 माओवादियों को मार गिराने का दावा जो किया गया था केवल सफेद झूठ था। 'प्रभात' कॉमरेड डेविड को पूरी विनम्रता के साथ श्रद्धांजली पेश करती है और तमाम पीएलजीए योद्धाओं का अभिनंदन करती है जिन्होंने दुश्मन के इस आक्रमण को नाकाम कर उसे शर्मनाक पराजय झेलने को विवश कर दिया।

दरअसल उस दिन ममाइल गांव में पार्टी का एक राजनीतिक कार्यक्रम चल रह था जिसकी सुरक्षा में पीएलजीए मुस्तैदी से तैनात थी। इसी दौरान सुबह बगल के गांव में दुश्मन के आने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही सभी को अपना-अपना पोस्ट और आर्क में तैनात होने का निर्देश दिया गया। सब अपने कवर में पहुंचे ही नहीं थे कि पूरब दिशा की संतरी पोस्ट पर दुश्मन पहुंच गया और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग हमारे पीएलजीए के जवानों की तरफ से ही शुरू हुई और पहली राउंड की फायरिंग में कम से कम 2 कोबरा को मार गिराया। दूसरे और तीसरे दौर की फायरिंग में भी 8-10 पुलिस वालों को गोली लगी, इसमें से लगभग 2-3 गम्भीर घायल थे जिनके बाद में मरने का अनुमान है।

चूंकि भौगोलिक धरातल पर पीएलजीए की अच्छी-खासी पकड़ थी, इसलिए हमारे साथी काफी अनुकूल स्थिति में थे। हमारे साथी पहाड़ के ऊपरी हिस्सा पर थे और चारों तरफ टीलानुमा पहाड़ी थी। चारों तरफ कई संतरी पोस्ट थे जो सभी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर थे।

हमें सूचना यह मिली थी कि दुश्मन पश्चिम दिशा से आ रहा है। पर पूरब दिशा से ही दुश्मन एकदम संतरी पोस्ट तक पहुंच गया जिसके बाद ही हमें पता चला। पश्चिम दिशा से दुश्मन नहीं हिला, दूर में ही रहा। पूरब दिशा से तीन संतरी पोस्ट पर दुश्मन ने हमला किया। दो पोस्ट से तो दुश्मन को जल्दी ही खदेड़ दिया गया, एक पोस्ट पर दुश्मन के तीन बार के प्रयास को तो विफल कर दिया गया, चौथी बार में कुछ तकनीकी कारणों से वहां से हमारे कॉमरेडों के हट जाने से दुश्मन संतरी पोस्ट को कब्जा कर लिया। इसकी सूचना कमाण्डर-इन-चीफ को दी गई तो तुरंत सभी साथी फ्लैंक में चले गये और दुश्मन को मार गिराते हुए पुनः खदेड़ दिया गया तथा दुश्मन के कब्जे से पोस्ट को मुक्त कर लिया गया।

मुठभेड़ सुबह 10.45 बजे से शुरू हुई और रात 11.30 बजे तक चलती रही। 13 घण्टे तक पीएलजीए के योद्धों ने शत्रु हमले का डटकर मुकाबला करते हुए उस रोज दुश्मन को कैम्प में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद एक बैच बगल टोला तक गया जहां से एसपी इस संघर्ष का संचालन कर रहा था। वहां भी हमला किया गया, हालांकि रात होने के कारण एक बार हमला करके पीछे हट गया। कुछ साथियों को कैम्प के सामानों को हटाने में मदद देने के लिए भेजा गया। वो लोग जाकर सामानों को इकठ्ठा कर ही रहे थे, तभी रात 11.30 बजे दुश्मन ने उस पोस्ट पर हमला कर दिया। उसका भी प्रतिरोध करते हुए दुश्मन को रोक दिया गया। तब तक हमारे साथी बुरी तरह थक चुके थे, फिर भी उसकी कोई परवाह नहीं थी।

चूंकि हमारे पीएलजीए के साथी थक चुके थे, खाने-पीने की भी तुरन्त व्यवस्था करना सम्भव नहीं था और दुश्मन बाहर से भी फोर्स की संख्या बढ़ा रहा था, इसलिए रिट्रीट करने का निर्णय लेकर वहां से हमारे कॉमरेड हट गये। फिर भी दुश्मन रात को संतरी पोस्ट से आगे नहीं बढ़ा। वहीं बंकर बनाकर रात भर रहा। भोर में पुलिस हमारे कैम्प के अंदर घुसी और खाद्य सामग्रियों, प्रिंटर के इंक और स्क्रीन प्रिंटिंग के कुछ सामानों, दो जेनरेटर और तीन मोटर साईकिलों को जला दिया। हमारा एक बैच जो आगे बढ़कर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, मौका मिलते ही दुश्मन पर हमला करने की ताक में था। वह रात में ममाइल गांव के बगल में रहा। दुश्मन ने दूसरे रोज फिर से कैम्प स्थल की तलाशी करने की योजना बनाई। हमारे साथियों को इसकी सूचना मिली तो फिर से जहां मौका मिले दुश्मन पर हमला करने की योजना बनाई गई और एक दस्ते को भेजा गया। यह दस्ता जाकर उस तरफ पहले से मौजूद हमारे

(शेष पेज 33 में...)

पार्टी की ऐतिहासिक 6वीं वर्षगांठ को ऊंचा उठाए रखो!
फासीवादी ऑपरेशन ग्रीन हंट को हरा दो!!
देश की लूटखसोट के खिलाफ सांझे संघर्ष के लिए एकजुट हो!!!

हमारी पार्टी की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर 21 से 27 सितम्बर तक क्रांतिकारी जोशोखरोश के साथ मनाने का पोलिटब्यूरो का आह्वान

प्यारे कॉमरेडो और लोगो,

21 सितम्बर 2010 को हमारी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जन कमेटियों और जन संगठनों के तमाम कॉमरेडों और क्रांतिकारी जनता को, जो दुश्मन के देशव्यापी भारी प्रति-क्रांतिकारी फौजी आक्रमण - ऑपरेशन ग्रीन हंट का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं, तहेदिल से क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करती है। इस अवसर पर हमारी पोलिटब्यूरो जेलों में कैद उन तमाम कॉमरेडों को क्रांतिकारी बधाई देती है जो अदम्य साहस के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं।

हमारी पोलिटब्यूरो उन 10 हजार से ज्यादा महान शहीदों को जो पिछले 45 सालों के दौरान शहीद हुए थे, और 2004 में एकीकृत पार्टी की स्थापना के बाद से अब तक शहीद हुए 1500 से ज्यादा शहीदों को और पिछले एक साल के दौरान शहीद हुए 300 से ज्यादा शहीदों को विनम्र श्रद्धांजली पेश करती है, जिन्होंने भारत की नई जनवादी क्रांति की सफलता के लिए तथा मानवजाति के महानतम लक्ष्य समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना के लिए अपने अनमोल प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इनमें से ज्यादातर शहीद आम लोग थे और क्रांतिकारी जन संगठनों व जन मिलिशिया के सदस्य थे। इस सचाई से यह साफ हो जाता है कि भारत के व्यापक जन समुदाय क्रांति में कूद पड़ रहे हैं।

पिछले साल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के बाद से क्रांति और प्रति-क्रांति के बीच युद्ध और ज्यादा तीखा हुआ। इस अवधि में रणनीतिक महत्व रखने वाले कई बदलाव हुए हैं जिससे आने वाले लम्बे समय तक भारतीय क्रांति पर प्रभाव पड़ेगा। इस अवसर पर हमारी ताकत और कमजोरियों को तथा क्रांति के लिए अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों को जनता और पार्टी के कतारों के सामने पेश करने की जरूरत है।

सबसे पहले - मई 2009 से जुलाई 2010 तक पोलिटब्यूरो सदस्य और प्यारे नेता कॉमरेड आजाद समेत आठ अग्रणी नेताओं और राज्य स्तर के दस नेताओं को दुश्मन ने या तो पकड़कर मार डाला या फिर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। जिला स्तर और निचले स्तरों के कई कॉमरेड गिरफ्तार कर लिए गए या फिर मार डाले गए। इन सभी नुकसानों ने हमारी पार्टी और आंदोलन पर गंभीर प्रभाव डाला। खासकर कॉमरेड आजाद हमारी पार्टी की उच्चतम कमेटी में अहम जिम्मेदरियां निभाने वाले कॉमरेड थे और उन्होंने कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली तरीके से बहुमुखी योगदान दिया था। इस तरह यह हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है।

2004 में स्थापना के बाद नई पार्टी ने देश की जनता के सामने समृद्ध राजनीतिक, सांगठनिक व सैनिक लाइन को, मजबूत पार्टी-नेतृत्व को, एक जन सेना - पीएलजीए, व्यापक जनाधार तथा संघर्ष के व्यापक इलाकों को प्रस्तुत किया। इससे क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ। इन अनुकूल परिणामों को देख घबरा जाने वाले दुश्मन ने हमारी पार्टी को कुचलने का फैसला लिया और 2005 व 2006 में हुए सारे नुकसान इसी साजिश का परिणाम थे। फिर भी 2007 में सफलतापूर्वक आयोजित पार्टी की एकता कांग्रेस - 9वीं कांग्रेस ने हमारी पार्टी की एकता और पार्टी नेतृत्व को मजबूत बनाया और क्रांति को आगे बढ़ाने की सटीक योजना बनाई। हालांकि आंध्रप्रदेश और उत्तर छत्तीसगढ़ में आंदोलन को धक्का लगा था और उत्तर ओड़िशा में भारी नुकसान हुए थे, फिर भी हमारी कामयाबियों ने क्रांतिकारी खेमे को आत्मविश्वास से लबालब कर दिया।

एकता कांग्रेस के सफल आयोजन और बाद में अर्जित कामयाबियों ने दुश्मन के खेमे को बेहद डरा दिया, इसलिए दुश्मन ने जनता के खिलाफ अभूतपूर्व स्तर पर युद्ध छेड़ दिया ताकि पार्टी नेतृत्व का सफाया किया जा सके। मई 2009 के बाद हुए ये नुकसान संख्या और तीव्रता के हिसाब से पिछले नुकसानों से भारी हैं। नुकसान चाहे कितने ही गंभीर हों, क्रांतिकारी आंदोलन के पिछले 45 सालों के इतिहास में नया नेतृत्व हमेशा उभरता ही रहा और आगे भी यह सिलसिला जारी ही रहेगा। जब तक जन समुदायों को क्रांति की जरूरत रहेगी, वे अपने नेताओं को पैदा भी करेंगे।

दूसरा - यूपीए-2 ने फासीवादी 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' छेड़ दिया जोकि चौतरफा आक्रमण की रणनीति का ठोस स्वरूप है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए भारतीय शासक वर्गों द्वारा अब तक बनाई गई सभी आक्रमणकारी रणनीतियों में से 2009 के मध्य से शुरू होकर चल रहा यह हमला अभूतपूर्व है, देशव्यापी है, तीव्रतम है, धोखाधड़ीपूर्ण है, केंद्रीकृत है और दीर्घकालीन है। यह दमनकारी सैन्य अभियान

हमारे मजबूत ग्रामीण इलाकों तथा गुरिल्ला जोनों में, खासकर दण्डकारण्य, बिहार-झारखण्ड, लालगढ़ तथा झारखण्ड-ओड़िशा, आंध्रप्रदेश-ओड़िशा और तेलंगाना-छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में केन्द्रीकृत है। इस 'जनता के खिलाफ युद्ध' ने सामाजिक अंतरविरोधों को तीखा कर दिया। पिछले 45 सालों में ऑपरेशन ग्रीन हंट की तुलना में दूसरे किसी भी दमनकारी अभियान को जनता की तरफ से इतना विरोध व प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था।

तीसरा - यूपीए-2 के दौरान विद्रोह-विरोधी सिद्धांतों को, जिसके तहत राज्य यंत्र, भारतीय संविधान, न्यायव्यवस्था, विधायिका, प्रशासन-तंत्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, मीडिया आदि को या तो पुनरनिर्माण या फिर प्रभावित कर रहे हैं, लागू करने में एक गुणात्मक बदलाव आया है। अमेरिकी साम्राज्यवादियों के नेतृत्व में साम्राज्यवादियों द्वारा छेड़े गए 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' से इसे संबल मिला हुआ है। यह हमारे देश को एक विनाशकारी परिस्थिति की तरफ धकेल देगा। इस बर्बर युद्ध को जारी रखने की वो जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा विरोध और प्रतिरोध का सामना उन्हें व्यापक जन समुदायों की तरफ से करना पड़ेगा। देश भर में इस तरह के प्रतिरोध को हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं।

पिछले एक साल के दौरान सभी मोर्चों पर चलाए गए संघर्षों और हमारे करीब तीन सौ आदरणीय व प्यारे कॉमरेडों की शहादत की बदौलत हमने कुछ महत्वपूर्ण कामयाबियां हासिल की हैं। वो हैं:

1) छत्तीसगढ़ में सिंगनमडुगु, मुकरम (ताड़िमेटला) और कोंगेरा; महाराष्ट्र में लाहेरी; पश्चिम बंगाल में संकरेल और सिल्दा; झारखण्ड में विष्णुपुर व लातेहार; बिहार में सोनो, सरकारी टोल प्लाज़ा (गया) और टांडवा बाजार; ओड़िशा में पोतकल और बैफरगुड़ा के पास किए गए हमलों ने, खासकर ऐतिहासिक मुकरम (ताड़िमेटला) हमले ने दुश्मन के मनोबल को तोड़ दिया और गुरिल्ला बलों की पहलकदमी को दोगुना कर दिया। इन हमलों ने पीएलजीए को ज्यादा हथियारों और नए अनुभवों से लैस कर दिया। ताड़िमेटला का अनुभव इन सभी में उच्च स्तर का है। अगर इस तरह हमारे बलों और जनता का सक्रिय प्रतिरोध न होता, तो दुश्मन को हमारे आंदोलन का सफाया करने के लिए ज्यादा मौका मिल जाता। इन महान अनुभवों से उन शत्रु बलों का मुकाबला करने में हमें निश्चित रूप से मदद मिलेगी जो एक भारी हमले के लिए तैनात किए जा रहे हैं। यह जनता का सक्रिय समर्थन ही है जिसकी नींव पर हमने ये तमाम कामयाबियां हासिल कीं।

2) कलिंगनगर, सिंगूर और नंदीग्राम के संघर्षों और बाद में व्यापक और उन्नत स्तर पर फूट पड़े लालगढ़ व नारायणपटना के संघर्षों ने शासक वर्गों को झकझोर दिया। संशोधनवाद या दक्षिणपंथी अवसरवाद के खिलाफ तथा दुश्मन वर्ग साम्राज्यवादियों व राज्य के खिलाफ चले इन संघर्षों का हमारी पार्टी ने नेतृत्व किया। पिछले 25 बरसों में इस तरह के व्यापक, जुझारू और लम्बे समय तक चले जन विद्रोहों का उभार कभी नहीं देखा गया। जनयुद्ध के विकास के लिए इन क्रांतिकारी जन विद्रोहों से मिली शिक्षा अनमोल है।

3) जबकि दुश्मन ने अपने बलों को बड़े पैमाने पर तैनात कर किसान विद्रोह को कुचलने की कोशिश कर रहा था, लालगढ़ सशस्त्र किसान आंदोलन फूट पड़ा, उसका फैलाव हुआ और वह मजबूत हुआ, जोकि बेहद महत्वपूर्ण है। और इसने भारत के सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी संघर्ष के इतिहास के पन्नों में एक खास स्थान प्राप्त किया।

4) भारत के पूर्वी और मध्य इलाकों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े पूंजीपतियों के कॉर्पोरेशनों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए की गई कोशिशों को व्यापक जनता ने हमारी पार्टी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। हमारी पोलिटब्यूरो तमाम जनता का, क्रांतिकारी, जनवादी, प्रगतिशील व देशभक्तिपूर्ण संगठनों तथा शख़्सों का क्रांतिकारी अभिनंदन करती है जो इन संघर्षों में मजबूती से डटे रहे। और हम वादा करते हैं कि हमारी पार्टी इन संघर्षों की अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहेगी।

5) दुश्मन के मनोवैज्ञानिक युद्ध के खिलाफ हमारी पार्टी ने कॉमरेड आजाद के नेतृत्व में विचारधारात्मक व राजनीतिक प्रचार-युद्ध चलाया। कॉमरेड आजाद के साथ-साथ हमारी समूची पार्टी विभिन्न स्तरों पर अगर इस तरह नहीं लड़ती तो जनयुद्ध को इतना सम्मान नहीं मिलता। इस मोर्चे पर उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण व सर्वोच्च रहा। आइए, कॉमरेड आजाद की प्रेरणा से हम इस क्षेत्र में लड़ाई को जारी रखें।

इन पांच प्रमुख सफलताओं के साथ-साथ, कुछ राज्यों में हमारा संघर्ष नए इलाकों में फैल गया। पार्टी और पीएलजीए राजनीतिक व फौजी तौर पर मजबूत हुईं। मौजूदा क्रांतिकारी जन कमेटियों/जनताना सरकारों को नए इलाकों में विस्तारित किया गया। इन सभी सफलताओं की बदौलत हम कई क्रांतिकारी ताकतों, बुद्धिजीवियों, जनवादियों, प्रगतिशील व देशभक्तिपूर्ण ताकतों का समर्थन जुटाने में कामयाब हो गए।

कॉमरेडो,

हमारे नुकसान बेहद गंभीर थे। अगर केन्द्रीय कमेटी से लेकर निचली कमेटियों तक सभी कमेटियां और समूची पार्टी सुनियोजित तरीके से और भी बड़े पैमाने पर नई ताकतों का निर्माण करने के लिए पूरा जोर लगाकर काम नहीं करती हैं और भूल-सुधार अभियान को सुचारू रूप से जारी नहीं रखती हैं, तो हमें हुए नुकसानों, खासकर कॉमरेड आजाद और केन्द्रीय व

(शेष पेज 47 में...)

प्रेस विज्ञप्तियां

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति : **दिनांक - 20 जुलाई 2010**

28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद-सप्ताह सफल मनाएं!
भारतीय क्रांति के महान नेता आजाद (राजकुमार), शाखामूरी अप्पाराव, जीवन (सूर्यम) समेत जनता के हित में अपने प्राणों को अर्पित करने वाले तमाम वीर शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करते हुए गांव-गांव में सभा-सम्मेलनों का आयोजन करें - शहीदों के अधूरे मकसद को पूरा करने की शपथ लें!!
पार्टी के संस्थापक-नेता व महान शिक्षक कॉमरेड्स चारु मजुमदार और कन्हाई चटर्जी को लाल-लाल सलाम!!!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी समूची क्रांतिकारी जनता व पार्टी/पीएलजीए के कतारों का आह्वान करती है कि आगामी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक देश भर में गांव-गांव में शहीद सप्ताह जोर शोर से मनाया जाए। इस अवसर पर, सबसे पहले, हमारी केन्द्रीय कमेटी अपनी पार्टी के संस्थापक-नेता व महान शिक्षक कॉमरेड्स चारु मजुमदार और कन्हाई चटर्जी को श्रद्धांजलि पेश करती है। हम फिर एक बार शपथ लेते हैं कि जब तक उनके सपनों का नया भारत, जोकि हर प्रकार के शोषण व उत्पीड़न से मुक्त हो, स्थापित किया नहीं जाता, तब तक विश्राम नहीं करेंगे।

पिछले 28 जुलाई से अभी तक एक साल में शोषित जनता की कई प्यारी संतानों ने नई जनवादी क्रांति की विजय के लिए मुस्कराते हुए अपने अनमोल प्राणों की आहुति दी है। इनमें से कइयों को पुलिस ने पकड़ने के बाद हत्या कर 'मुठभेड़' की कहानियां गढ़ दीं। कुछ और कॉमरेडों ने दुश्मन के साथ आमने-सामने लड़ते हुए अपनी जानें कुरबान कर दीं। और कई आम लोगों की मौत 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के तहत पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों द्वारा जारी अंधाधुंध गोलीबारियों व नरसंहारों में और यातनाओं से हुई। चंद कॉमरेडों की शहादत बीमारी के चलते या हादसों में हुई। इस तरह देश भर में 250 से ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन के नेता, कार्यकर्ता, सदस्य और जनता शहीद हुए हैं। शहीदों में पार्टी के पोलिटब्यूरो सदस्य व प्रवक्ता कॉमरेड आजाद (चेरुकूरी राजकुमार); पार्टी के मिलिटरी इंटलिजेन्स के केन्द्रीय निर्देशक व वरिष्ठ राज्य स्तर के नेता कॉमरेड शाखामूरी अप्पाराव; और पीएलजीए की मध्य रीजनल कम्पनी-2 के राजनीतिक कमिस्सार व राज्य स्तर के नेता कॉमरेड जीवन (सूर्यम) समेत विभिन्न स्तरों के पार्टी नेता, पीएलजीए कमाण्डर व पार्टी/जन संगठन सदस्य शामिल हैं। कॉमरेड्स शारदा (रामक्का), नर्मदा, स्वर्णा जैसी वरिष्ठ महिला साथियों समेत कई महिलाएं भी शहीद हुई हैं। 12 मार्च को तकनीकी विभाग के वरिष्ठ कॉमरेड कोण्डलरेड्डी (रमणा) को महाराष्ट्र शहर से पुलिस ने उठाया था और बाद में आंध्रप्रदेश के वरंगल जिले के जंगलों में ले जाकर गोली मार दी। कॉमरेड आजाद के साथ सफर कर रहे हेमचंद्र पाण्डे को भी आजाद के साथ ही पुलिस ने गोली मार दी। उत्तर तेलंगाना में कॉमरेड्स दया, रमेश, भास्कर, पुन्नम और सुरेश दुश्मन के हमलों में शहीद हुए।

दण्डकारण्य में गड़चिरोली डिवीजनल कमेटी सदस्य कॉमरेड मंगेश (साईनाथ) ने पिछले 8 अक्टूबर को लहेरी के पास दुश्मन के कमाण्डो बलों के साथ बहादुराना लड़ाई लड़ते हुए शहादत को हासिल किया। 6 अप्रैल को हुए ऐतिहासिक ताड़िमेट्ला ऐम्बुश में आठ नौजवान कॉमरेडों - रुकमति, वागाल, विज्जाल, इंगाल, राजू, मंगू, रामाल और रतन ने शौर्यपूर्ण लड़ाई लड़ते हुए अपनी जानें कुरबान कीं। 29 जून को नारायणपुर जिले के कोंगेरा के पास किए गए एक और साहसिक कारनामे में कम्पनी पार्टी कमेटी सदस्य/प्लटून कमाण्डर कॉमरेड्स बण्डू और शंकर तथा प्लटून पार्टी कमेटी सदस्य कॉमरेड रमेश - तीन कॉमरेडों ने अनुपम पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अपने प्राणों को अर्पित किया। 15 फरवरी को पश्चिम बंगाल के सिल्दा में दुश्मन के कैम्प पर किए गए जबर्दस्त हमले में पांच कॉमरेड शहीद हुए थे। जून महीने में पश्चिम बंगाल के जंगलमहल में हुए दुश्मन के हमले में 8 कॉमरेडों की जानें गईं। 16 जून को झारखण्ड के सरंडा इलाके में पार्टी के उच्च नेतृत्व का उन्मूलन करने की साजिश के तहत 2,000 पुलिस, अर्ध-सैनिक व कोबरा बलों ने तीन वायुसैनिक हेलिकॉप्टरों की मदद से एक कैम्प पर हमला किया था। इस हमले को विफल करते हुए, पार्टी-नेतृत्व की रक्षा करते हुए और शत्रु बलों का सफाया करते हुए सेक्शन कमाण्डर कॉमरेड डेविड ने अपने प्राणों का बलिदान किया। इन तमाम शहीदों को हमारी केन्द्रीय कमेटी

विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि पेश करती है... शहीदों के परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है।

देश के शासक वर्गों द्वारा लागू साम्राज्यवाद-परस्ती लूटखसोट की नीतियों के खिलाफ जनता हर जगह सड़कों पर उतरकर लड़ रही है। देश के कई इलाके जन संघर्ष के गढ़ों के रूप में उभरकर आ रहे हैं। शासकों ने यह सोचकर कि इन जन संघर्षों को कुचल दिए बिना अपनी लूटखोर नीतियों को लागू करना नामुमकिन है, उन्हें खून की नदियों में डुबोने की कोशिशें कर रहे हैं। ओड़िशा के कलिंगनगर में अपनी जमीनें सौंपने से इनकार करने वाले आदिवासियों पर गोलियां बरसाकर कई लोगों की जानें लेना और अभी-अभी 13 जुलाई को आंध्रप्रदेश के सोंपेटा में प्रस्तावित थर्मल बिजली परियोजना से अपने अस्तित्व को हो सकने वाले खतरे के मद्देनजर विरोध जता रही जनता पर गोलीबारी कर तीन लोगों की हत्या करना इसके चंद उदाहरण हैं। शोषक शासक यह दिवास्वप्न देख रहे हैं कि वे जन संघर्षों की अगुवाई करने वाली ताकतों का भौतिक रूप से उन्मूलन कर उन आंदोलनों की कमर तोड़ पाएंगे। जमीन के लिए संघर्ष कर रहे नारायणपटना (ओड़िशा) इलाके में आंद्रू और सिंगन्ना तथा पुलिसिया दमनचक्र के खिलाफ लड़ रहे लालगढ़ (पश्चिम बंगाल) इलाके में लालमोहन टुडू जैसे जन नेताओं की गोली मारकर हत्या कर मुठभेड़ के रूप में चित्रित करना इसका उदाहरण है। उन तमाम लोगों और जन नेताओं को हमारी केन्द्रीय कमेटी सिर झुकाकर लाल सलाम करती है जो पिछले एक साल के दौरान देश भर में लुटेरे शासक वर्गों के खिलाफ जन आंदोलन चलाते हुए हत्या का शिकार हुए थे।

क्रांतिकारी आंदोलन का समूल उन्मूलन कर देश की सभी संपदाओं और प्राकृतिक संसाधनों को साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और दलाल पूंजीपतियों के हाथों लुटवाने के इरादे से देश के शासक गिरोह द्वारा छेड़े गए ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत, खासकर दण्डकारण्य के बस्तर इलाके में बड़े पैमाने पर आदिवासियों का नरसंहार किया जा रहा है। पिछले 10 महीनों के दौरान अकेले दण्डकारण्य में ही करीब 150 आदिवासियों को पुलिस, अर्ध-सैनिक बलों और एसपीओ ने मौत के घाट उतार दिया। इनमें से ज्यादातर लोगों की मौतों को 'मुठभेड़' के रूप में घोषित किया गया जबकि कुछ लोगों की हत्याएं दर्ज तक नहीं हुईं। गोल्लागूड़ेम, वेच्चापाड़, सिंगनमडुगू, पालाचेलमा, गोमपाड़, टेट्टेमडुगू, गुमियापाल, कुटरेम, ताकिलोड़, ओंगनार, राजूवेड़ा... ऐसे कई गांवों में आम जनता को गोली मारकर 'मुठभेड़' की कहानियां गढ़ दी गईं। दूसरे राज्यों में भी आम जनता को गोली मारकर मुठभेड़ की कहानियां गढ़ देने की कई घटनाएं हुई हैं। जनता के खिलाफ शोषक शासक वर्गों द्वारा छेड़े गए युद्ध के तहत सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा मचाए जा रहे अंधाधुंध हत्याकाण्डों में अपनी जानें गंवाने वाली तमाम जनता को हमारी केन्द्रीय कमेटी विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि पेश करती है।

इसके साथ-साथ महान विश्व समाजवादी क्रांति के तहत दुनिया के कई देशों में जारी साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्षों और सभी न्यायपूर्ण संघर्षों में तथा कश्मीर व पूर्वोत्तर के इलाकों में जारी राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में प्राण गंवाने वाले योद्धाओं और जनता को हमारी केन्द्रीय कमेटी तहेदिल से श्रद्धांजलि पेश करती है।

वीर शहीदों के आदर्शों, लड़ाकूपन, दृढ़ संकल्प और बलिदान की भावना को ऊंचा उठाए रखें!

1 जुलाई को खून के प्यासे एपीएसआईबी और केन्द्रीय खुफिया संस्थाओं के हत्यारों ने पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड आजाद को उनके साथ सफर कर रहे एक स्वतंत्र पत्रकार हेमचंद्र पाण्डे के साथ महाराष्ट्र के नागपुर इलाके से उठाकर आंध्रप्रदेश के आदिलाबाद के जंगलों में ले जाकर 'मुठभेड़' के नाम से गोली मार दी। कॉमरेड आजाद की मृत्यु से भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। वरंगल रीजनल इंजिनीयरिंग कॉलेज में क्रांतिकारी छात्र के रूप में शुरू कर पिछले करीब चार दशकों से भारतीय क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले कॉमरेड आजाद ने मुख्य रूप से सैद्धांतिक व राजनीतिक मोर्चों पर बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, क्रांतिकारी प्रचारक के रूप में, कई क्रांतिकारी पत्रिकाओं के सम्पादक के रूप में, लेखक के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में, साहित्यकार के रूप में, रंग-बिरंगे संशोधनवादियों व कई प्रतिक्रियावादियों के सड़े-गले सिद्धांतों व कुतर्कों को चकनाचूर कर मार्क्सवाद को अपराजेय बताकर बुलंद रखने वाले सर्वहारा बुद्धिजीवी के रूप में, देश में क्रांतिकारी ताकतों के एकीकरण के लिए प्रयास करने वाले कम्युनिस्ट योद्धा के रूप में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी संगठनों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भरसक प्रयास करने वाले सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवादी के रूप में.... कॉमरेड आजाद ने अतुलनीय योगदान दिया। पिछले 40 सालों से जारी भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के विकासक्रम से कॉमरेड आजाद को अलग करना असंभव है। हमारी केन्द्रीय कमेटी देश की युवा पीढ़ी, छात्र-बुद्धिजीवियों और मजदूर-किसानों का आह्वान करती है कि कॉमरेड आजाद के आदर्शों को आत्मसात करते हुए उनके द्वारा सौंपे गए लाल झण्डे को गर्व के साथ ऊंचा उठाए रखें।

12 मार्च को आंध्रप्रदेश के एसआईबी हत्यारों ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और मिलिटरी इंटलिजेन्स विभाग के केन्द्रीय निर्देशक कॉमरेड शाखामूरी अप्पाराव की गोली मारकर मुठभेड़ की कहानी प्रसारित की। पिछले 32 सालों से ज्यादा समय से क्रांतिकारी आंदोलन से गुंथी हुई कॉमरेड शाखामूरी की जिंदगी आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। क्रांतिकारी छात्र आंदोलन में शामिल होकर इंजिनीयरिंग की पढ़ाई छोड़कर जल्द ही पूर्णकालीन क्रांतिकारी बनकर कुरियर (संदेशवाहक) के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में, जिला, रीजनल व राज्य कमेटियों में सदस्य के रूप में, मिलिटरी इंटलिजेन्स विभाग के

केन्द्रीय निर्देशक के रूप में उभरने वाले कॉमरेड शाखामूरी खासकर आंध्रप्रदेश के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में अपनी छाप छोड़ गए। कइयों के लिए प्रेरणा बनकर, कइयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़कर और अनगिनत लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाले कॉमरेड शाखामूरी दुश्मन के लिए आखिर तक एक चुनौती बनकर डटे रहे। दुश्मन के दावपेंचों का हमेशा अध्ययन कर पार्टी व पीएलजीए को उसके अनुरूप तैयार करने के काम में उन्होंने जो भूमिका अदा की उसे सदा याद रखा जाएगा। 8 मई को शत्रु बलों पर किए गए ऐम्बुश में घायल होकर बाद में दम तोड़ने वाले कॉमरेड जीवन (सूर्यम) की मृत्यु मध्य रीजियन के जनयुद्ध के क्षेत्र में काफी बड़ा नुकसान है। आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य के तौर पर काम कर चुके कॉमरेड सूर्यम पिछले कुछ समय से मध्य रीजियन के दायरे में - दण्डकारण्य, आंध्र-ओड़िशा सीमांत स्पेशल जोन और उत्तर तेलंगाना में जन सेना द्वारा अंजाम दी गई कई सैन्य कार्रवाइयों में अहम भूमिका निभाते रहे। नयागढ़ जैसी सैन्य ऑपरेशन्स को सफल बनाने में उनका खासा योगदान रहा। उनकी मृत्यु से पार्टी और पीएलजीए जनयुद्ध के एक जबर्दस्त कमाण्डर से वंचित हो गई।

क्रांति में कुरबानियां अनिवार्य हैं। यह क्रांतियों का युग है। जनता ही इतिहास का निर्माता है। जनता और जन आंदोलन ने ही आजाद जैसे महान क्रांतिकारी बुद्धिजीवी को, शाखामूरी जैसे मंजे हुए कम्युनिस्ट योद्धा को, सूर्यम जैसे जनयुद्ध के बहादुर कमाण्डर को, आंद्रू, सिंगन्ना, लालमोहन जैसे जन नेताओं को पैदा किया... और करते करेंगे। जनयुद्ध ने ही मंगेश, रुकमति, डेविड, बंण्डू, रमेश जैसे जांबाजों को पैदा किया... और करता करेगा। इसलिए क्रांतिकारी जन आंदोलनों और जनयुद्ध को तेज करते हुए उन्हें और भी उन्नत स्तर पर विकसित करके ही तथा सैकड़ों-हजारों की संख्या में नई ताकतों को क्रांतिकारी आंदोलन में आकर्षित करके ही हम शहीदों के सपनों को साकार कर सकेंगे.... उनकी कमी को पाट सकेंगे। जनता और पार्टी के कतारों से हमारी केन्द्रीय कमेटी का आह्वान है कि शहीद सप्ताह के मौके पर यही संकल्प लिया जाए।

अभय, प्रवक्ता, केन्द्रीय कमेटी, भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केन्द्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति : **दिनांक - 23 सितम्बर 2010**

अपनी आजादी के लिए आंदोलन कर रहे कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे भारतीय शासक वर्गों की दरिंदगी की निंदा करो!
सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा लगातार जारी हत्याओं के खिलाफ तथा कश्मीरी जनता के न्यायपूर्ण आंदोलन के समर्थन में...
30 सितम्बर 2010 को 24 घण्टों का 'भारत बंद' सफल बनाओ!!

कश्मीर में सरकार द्वारा लोगों की हत्याओं का सिलसिला बेलगाम जारी है। सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा लगातार जारी मनमानी हत्याओं, अत्याचारों, बिना रुके जारी कर्फ्यू आदि की अवहेलना करते हुए पूरी कश्मीर की घाटी में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। 'आजादी' का नारा समूची घाटी में गूंज रहा है। 11 जून से शुरू कश्मीरी जनता के इस न्यायपूर्ण संघर्ष को कुचलने के लिए अर्ध सैनिक, सैनिक व पुलिस बलों द्वारा की जा रही गोलीबारियों में अभी तक सौ से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। (इनमें अत्यधिक बीस साल से कम उम्र के किशोर व नौजवान हैं।) सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। निहत्थे, शांतिपूर्ण व न्यायपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे कश्मीरियों पर भारत के विस्तारवादी लुटेरे शासक वर्ग, जो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं, बेशर्मी के साथ सशस्त्र बलों को उकसाकर बेहद क्रूरता से दमन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार, खुद को वामपंथी कहने वाली सीपीएम व सीपीआई समेत सभी शासक पार्टियां कश्मीरियों पर हो रहे इस दमनचक्र का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन कर रही हैं, वहीं हिंदू साम्प्रदायिकतावादी भाजपा सरकार को बार-बार उकसा रही है कि वह कश्मीरियों का बेहद सख्ती से दमन करे। केन्द्र सरकार द्वारा कश्मीरी जनता पर जारी हिंसा में भाग लेने वाले भारतीय शासक वर्गों का वफादार सेवक ओमर अब्दुल्ला की सरकार जनता से पूरी तरह अलग-थलग पड़कर उनकी तीखी नफरत का शिकार बन रही है। लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ने के साथ-साथ हर प्रदर्शन पर गोलीबारी करना एक रिवाज सा बन गया है। इसी पृष्ठभूमि में कश्मीरी जनता, खासकर नौजवान हाथ में आए पथ्तरों से ही इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। इस अमानवीय दमनचक्र के विरोध में और अपनी आत्मरक्षा के लिए किया जा रहा यह प्रतिरोध पूरी तरह न्यायपूर्ण व लोकतांत्रिक है।

कश्मीरी जनता ने खुद को कभी भी भारत का हिस्सा नहीं माना। 1947 में अंग्रेजी शासकों से भारत और पाकिस्तान को मिली झूठी आजादी के पहले तक कश्मीर राजा हरिसिंह के शासन में एक स्वतंत्र देश के रूप में था। लेकिन कुटिलता में

माहिर ब्रितानी साम्राज्यवादियों के पिट्ठू भारतीय व पाकिस्तानी लुटेरे शासक वर्गों ने अपने हितों के मद्देनजर कश्मीर को अपने देशों में जबरन मिला लिया जोकि कश्मीरियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं से पूरी तरह खिलाफ था। एक हिस्से पर भारतीय शासक वर्गों ने कब्जा किया तो बाकी हिस्से को पाकिस्तान ने हड़प लिया। इस तरह बेहद निंदनीय तरीके से इन्होंने कश्मीर को दो टुकड़ों में बांट दिया। उस समय कश्मीरियों के विरोध को ठण्डा करने के लिए नेहरू सरकार ने लिखित रूप से कश्मीरी जनता व संयुक्त राष्ट्र संघ से यह वादा किया था कि कश्मीर में रायशुमारी (जनमत संग्रह) कराई जाएगी और जनता अगर आजादी चाहती है तो दे दी जाएगी। नेहरू ने इस वादे को कई बार दोहराया भी था। लेकिन कुछ ही समय बाद से उन्होंने सैन्य जूतों तले कश्मीर को रौंदना शुरू किया। नेहरू से लेकर आज के सोनिया-मनमोहन तक दिल्ली में गद्दी संभालने वाली हर शासक पार्टी ने कश्मीरियों के साथ वादाखिलाफी ही की। जब भी आजादी के लिए आवाज उठी, भारतीय विस्तारवादी सरकारों ने कश्मीरियों पर दमन का ही प्रयोग किया। आंखों के सामने घट रहे इतिहास को और अपने ही किए हुए वादों को छुपाते हुए भारतीय शासक सुनियोजित तरीके से यह प्रचार करते आ रहे हैं कि 'कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।' तबसे कश्मीरियों के दिलों में सुलगती आई आजादी की अदम्य इच्छा ने 1990 के दशक में मिलिटेंट हथियारबंद आंदोलन का रूप ले लिया। कई मिलिटेंट संगठनों ने हथियारबंद संघर्ष चलाया। उन संगठनों के राजनीतिक लक्ष्यों में कुछ फर्क होने के बावजूद उन्हें जनता का समर्थन हासिल हुआ था क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों की राष्ट्रीय मुक्ति की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया। लेकिन उस संघर्ष को कुचलने के लिए भारत के फासीवादी शासक वर्गों ने 7 लाख से ज्यादा सैनिक और अर्ध सैनिक बलों को तैनात कर समूची कश्मीर की घाटी का सैन्यीकरण किया और अभी तक 80 हजार से ज्यादा कश्मीरियों की जानें लीं। हजारों लोगों को सरकार ने लापता कर दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की किसी भी राष्ट्रीयता के संघर्ष पर किसी भी सरकार ने इतने ज्यादा समय तक, इतनी तीव्रता से, इतनी भारी संख्या में सशस्त्र बलों को उतारकर, इतने क्रूर तरीके से दमन नहीं किया। जब मिलिटेंट आंदोलन तीखे रूप से चल रहा था, तभी भारतीय शासक वर्गों ने कई साजिशों और षड़यंत्रों को रचकर 'फूट डालो और राज करो' वाली नीति से कश्मीरी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ा पैदा किया। कश्मीरी जनता के जायज आंदोलन के खिलाफ कश्मीरी पंडितों को खड़ा करने की साजिशें लगातार जारी हैं। इसमें विशेषकर विस्तारवादी देशीय अंधराष्ट्रवादी कांग्रेस और हिंदू धार्मिक साम्प्रदायिकतावादी फासीवादी संघ गिरोह की भूमिका बेहद नीचतापूर्ण है। 'मिलिटेन्सी' के रूप में प्रचलित कश्मीरियों के उस संघर्ष में कुछ पाकिस्तान-अनुकूल ताकतों और इस्लामिक ताकतों के शामिल होने के बहाने भारतीय शासकों का यह प्रचार कि कश्मीरियों का राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम पूरी तरह पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आंदोलन है तथा उनके आंदोलन का लक्ष्य भारत से अलग होकर पाकिस्तान में शामिल हो जाना है, सरासर झूठ है। कश्मीरी जनता की आकांक्षा शुरू से ही अपनी राष्ट्रीयता की आजादी रही है। यही वजह है कि कश्मीर में मिलिटेन्सी को खत्म करने के दावे भले ही भारतीय शासक करते रहें, दरअसल यह संघर्ष रुका ही नहीं। अलग-अलग मौकों पर जिस किसी भी मुद्दे को लेकर यह आंदोलन उफान पर आया हो, 'आजादी' का नारा ही उसमें प्रमुखता से उठाया जाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दृढ़तापूर्वक घोषणा करती है कि अपनी राष्ट्रीयता की आजादी के लिए तथा आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए कश्मीरी जनता द्वारा जारी आंदोलन पूरी तरह न्यायपूर्ण है और कश्मीर पर न तो भारत को न ही पाकिस्तान को कोई हक है।

आजादी-पसंद कश्मीरी लोगो,

अपनी आजादी के लिए तथा आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गों के खिलाफ जारी आपके संघर्ष का हमारी पार्टी समर्थन करती है और तहेदिल से भाईचारा प्रकट करती है। गोलीबारियों, लाठीचार्ज, कर्फ्यू, लगातार जारी तलाशी मुहिमों और अंतहीन अपमानों का मुकाबला करते हुए दृढ़ता के साथ जारी आपके संघर्ष का हमारी पार्टी भारत की समूची क्रांतिकारी, जनवादी व संघर्षरत जनता की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। अंधाधुंध गोलीबारियां करते हुए दर्जनों की संख्या में युवक-युवतियों का कत्लेआम करने के बावजूद भी शहीदों के शवों को कंधों पर उठाकर जनाजों में हजारों की संख्या में भाग लेते हुए 'आजादी' का नारा बुलंद करने का आपका जज़्बा और कुरबानी का जोश इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेंगे। भारतीय विस्तारवादियों के भाड़े के सशस्त्र बलों की गोलीबारियों में अपनी जानें गंवाने वाले शहीदों के परिजनों, दोस्तों और समूचे कश्मीरी कौम के प्रति हमारी पार्टी गहरी संवेदना प्रकट करती है। आज जो भारतीय शासक वर्ग आपके संघर्ष पर विघटनकारी और देशद्रोहपूर्ण आंदोलन का ठप्पा लगाकर आपको अलग-थलग करने के नापाक मंसूबे से मनमानी हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, वे ही आज भारत की समूची शोषित जनता, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं और व्यापक जन समुदायों के घोर दुश्मन हैं। इसलिए, आइए, अपने सांझे दुश्मनों के खिलाफ हम सब एकजुट होकर लड़ें। इस लड़ाई को और तेज करें।

भारत के इंसाफ-पसंद लोगो,

कश्मीरी जनता के जायज संघर्ष के खिलाफ भारतीय लुटेरे शासक वर्ग, खासकर कांग्रेस व भगवा आतंकी गिरोह सुनियोजित तरीके से जो भड़काऊ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उससे प्रभावित न होवें। हमारी पार्टी आप सभी से अपील करती है कि आप सच्चाई को समझते हुए न्याय के पक्ष में मजबूती से खड़े होवें।

इस मौके पर हमारी पार्टी की ठोस मांगें ये हैं –

1) **कश्मीर में भारत के सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा जारी हत्याओं को फौरन रोको।**
2) **सैन्य बलों को जनता को मनमाने ढंग से मार डालने का अधिकार देने वाले फासीवादी कानून – 'सशस्त्र बलों का विशेष अधिकार कानून' (एफपीएसए) को फौरन रद्द करो।**
3) **कश्मीर से अर्ध सैनिक व सैनिक बलों को फौरन वापस लो।**
4) **कश्मीर में रायशुमारी (जनमत संग्रह) करवाकर कश्मीरी जनता को अपने भविष्य का फैसला खुद ही करने का अधिकार दो।**
5) **तमाम राजनीतिक बंदियों को फौरन रिहा करो।**

आप सभी से हमारा आह्वान है कि कश्मीरी जनता पर सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा जारी हत्याकाण्डों के खिलाफ तथा कश्मीरियों के जायज संघर्ष के प्रति भाईचारा प्रकट करते हुए आप 30 सितम्बर को 24 घण्टों का 'भारत बंद' सफल बनाएं। इस 'भारत बंद' के दौरान छह राज्यों – बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र के गड़चिरोली, गोंदिया व चंद्रपुर जिलों तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में रेलवे, सड़कें, बैंक, सरकारी व निजी कार्यालय, उद्योग-धंधे, शिक्षा व व्यापार संस्थानों को बंद रखने व उसमें उपस्थित न होने का हम जनता से आह्वान कर रहे हैं। हालांकि हम मेडिकल आदि अत्यावश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखेंगे।

आनंद
सचिव
मध्य रीजनल ब्यूरो
भाकपा (माओवादी)

अभय
प्रवक्ता
केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति : **दिनांक – 1 जुलाई 2010**

कोंगेरा में सीआरपीएफ जवानों की मौत के लिए सोनिया-मनमोहन-चिदम्बरम गिरोह और रमनसिंह जिम्मेदार हैं!

कोंगेरा हमला : ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा लगातार जारी आदिवासियों के नरसंहारों, सामूहिक बलात्कारों, घरों को जलाने की घटनाओं, यातनाओं, अवैध धरपकड़ आदि तमाम दमनकारी नीतियों का अनिवार्य परिणाम!!

इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने के सिलसिले में अपनी जानें कुरबान करने वाले वीर योद्धा कॉमरेड्स बंडू, शंकर और रमेश को लाल-लाल सलाम!!!

29 जून 2010 के दोपहर 1 बजे हमारी पीएलजीए के सैकड़ों बहादुर सैनिकों ने नारायणपुर जिले के धौड़ाई के पास झाराघाटी में सीआरपीएफ की 39वीं बटालियन की एक कम्पनी पर हमला कर तीन अधिकारियों समेत 27 बलों का सफाया किया और 7 अन्य को घायल किया। जबकि बाकी सभी जवान व अधिकारी हमारे आक्रमण के सामने टिक नहीं सके और जंगे मैदान से भाग खड़े हुए। 4 घण्टों तक चले इस घमासान में मारे गए सरकारी भाड़े के बलों से 26 अत्याधुनिक हथियार और अन्य फौजी साजोसामान छीन लिए गए ताकि जन सेना की शस्त्रास्त्र सम्पत्ति को बेहतर बनाया जा सके। छीने गए हथियारों में 9 एके-47, 10 इन्सास रायफलें, 3 एसएलआर, 2 दो इंची मोर्टार और 2 इन्सास एलएमजी शामिल हैं। इस शौर्यपूर्ण हमले को सफलता दिलाने की खातिर हमारी पीएलजीए के तीन बहादुर कमाण्डरों ने अपने अनमोल प्राणों को भारत की नई जनवादी क्रांति की बलिवेदी पर अर्पित किया। ये तीन कॉमरेड थे – बण्डू (प्लटून कमाण्डर), शंकर (प्लटून कमाण्डर) और रमेश (सेक्शन कमाण्डर)। संघर्षरत विरासत की धनी बस्तर माटी में पैदा हुए इन बहादुर बेटों ने पिछले कई सालों से क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बनकर, देश को सामंतवादी, दलाल नौकरशाही पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शोषण व उत्पीड़न से आजाद कर, जनता का सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के लक्ष्य से अपना सब कुछ न्यौछावर कर संघर्ष का झण्डा ऊंचा उठाया। आइए, इन बस्तर के इन बहादुर बेटों को अपना सिर झुकाकर सलाम करें।

यह हमला खासकर अगस्त 2009 से आपरेशन ग्रीन हंट के तहत सीआरपीएफ, कोबरा, राज्य पुलिस और एसपीओ द्वारा लगातार जारी आतंक के नंगानाच के खिलाफ हुआ है। और सीआरपीएफ के इन जवानों की मौत के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। खासतौर पर सोनिया-मनमोहनसिंह-चिदम्बरम गिरोह के साथ-साथ रमनसिंह जिम्मेदार हैं जो देश की समूची जनता के खिलाफ जारी इस बर्बरतापूर्ण युद्ध की अगुवाई कर रहे हैं। 2005 से जारी पाशविक सलवा जुडूम अभियान के

आतंकी हमलों के चलते जो विनाशलीला रची गई थी, उससे कई गुना ज्यादा तीव्रता से अब 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' जारी है। इसके तहत पिछले 10 महीनों से आदिवासियों की सामूहिक हत्याओं का एक सिलसिला ही चल पड़ा। 8 जनवरी 2009 के सिंगारम सामूहिक हत्याकाण्ड के बाद कोकावाड़ा, वेच्चापाड़, पालाचेलमा, गोमपाड़, गुमियापाल, कुटरेम, ओंगनार, ताकिलोड़ आदि गांवों में नरसंहार कर पुलिस, एसपीओ और अर्ध-सैनिक बलों ने दर्जनों आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। दो साल के नन्हे बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों को अपनी पाशविकता का शिकार बनाया। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर 'मुठभेड़' के नाम से कई लोगों की हत्या की। इस ऑपरेशन ग्रीन हंट में सरकारी बलों ने सिर्फ दण्डकारण्य में अभी तक 150 से ज्यादा लोगों की हत्या की है। देश भर में यह संख्या कहीं ज्यादा होगी। मारे गए लोगों में अत्यधिक आम जनता ही है। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और गांवों को जलाने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। एक शब्द में कहें तो यहां की समूची जनता का अस्तित्व ही जबर्दस्त खतरे में है आज।

मिसाल के तौर पर यह देखें कि हाल की कुछ घटनाओं में सरकारी सशस्त्र बलों ने क्या-क्या किया?

वर्ष 2009 में नारायणपुर जिले के ग्राम इन्नर (हिंदी में चिनारी) में दिलीप और सोनारू नाम के दो युवकों को गोली मार दी। 3 फरवरी को माड़ डिवीजन के इंद्रावती इलाके के गांव ताकिलोड़ में 7 आदिवासियों की निर्मम हत्या कर दी। बर्बरता का आलम यह है कि उन्हें कुल्हाड़ियों से काट-काटकर मार डाला गया। 5 फरवरी को नारायणपुर जिले के ओंगनार गांव में 2 युवतियों समेत 5 नौजवानों को दौड़ा-दौड़ाकर मार डाला गया और हमेशा की तरह मुठभेड़ की कहानी गढ़ दी गई। 10 फरवरी को माड़ क्षेत्र के दुमनार गांव में कुमली नामक एक 22 साल की युवती के साथ, जो जनताना सरकार की कृषि कार्यकर्ता थीं, सामूहिक बलात्कार कर गला रेतकर मार डाला। 4 मई को राजूबेड़ा में दो युवकों - एक का नाम लालसिंह है - को मुठभेड़ के नाम से मार दिया गया। 3 अप्रैल को इन्नर गांव के 5 घरों में आग लगा दी। मई महीने के आखिर में कज्जुम गांव में 5 घरों में आग लगा दी। गांवों में छापेमारियों के दौरान तथा हाट बाजारों से लोगों को अगवा कर हफ्तों तक थानों में रखकर बर्बर यातनाएं देना और झूठे केसों में फंसाकर जेलों में ठूंसना पुलिस व अर्ध-सैनिक बलों का रोजमर्रा का काम बन गया। एक शब्द में कहें तो दक्षिण में कोंटा से लेकर उत्तर में मानपुर इलाके तक सरकारी बलों द्वारा आदिवासियों पर अकथनीय अत्याचारों का सिलसिला लगातार जारी है।

ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने इन बलों के खिलाफ सशस्त्र जन प्रतिरोध को तेज करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। सरकारी आक्रमण के खिलाफ आत्मरक्षात्मक संघर्ष तेज करना जरूरी हो गया ताकि दण्डकारण्य में पिछले 30 वर्षों से जारी क्रांतिकारी संघर्ष की उपलब्धियों को सुरक्षित रखा जा सके तथा यहां के आदिवासियों के अस्तित्व को बचाया जा सके। 6 अप्रैल की ताड़िमेटला कार्रवाई के बाद, पीएलजीए के हमारे जन सैनिक अपनी जान को दांव पर लगाकर आतंकी सरकारी बलों के खिलाफ एक और जबर्दस्त जवाबी हमला किया है।

भले ही शोषक सरकारें माओवादी संघर्ष को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में चित्रित कर प्रचारित कर रही हों, लेकिन उनका ऑपरेशन ग्रीन हंट सिर्फ माओवादियों के खिलाफ नहीं है। देश के हर जनवादी संघर्ष और हर न्यायपूर्ण आंदोलन का गला घोंटना उनका लक्ष्य है। देश की सार्वभौमिकता की खिल्ली उड़ाकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने नतमस्तक हुई यूपीए सरकार ने कार्पोरेट लूट के लिए देश के सारे दरवाजे खोल रखे हैं। खासकर आदिवासी इलाकों में छिपी खनिज संपदा को लूटने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े पूंजीपतियों की कम्पनियों ने एड़ी-चोटी एक कर रखी है। उनकी निर्बाध लूटखसोट को सुनिश्चित करने के लिए ही दलाल सरकारों ने माओवादी आंदोलन पर मुख्य निशाना साधते हुए यह भारी हमला छेड़ रखा है। भोपाल गैसकाण्ड के लिए जिम्मेदार वारेन एंडरसन जैसे कातिलों को देश से बाहर सुरक्षित निकल जाने का मौका देकर, बाकी अभियुक्तों को 26 सालों के आपराधिक विलम्ब के बाद नाम मात्र की सजाएं देने वाली इस व्यवस्था को आज देश के आदिवासी और अन्य शोषित तबके बहुत बड़े दुश्मन नजर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि खासकर आदिवासियों ने कार्पोरेट लूटखसोट के खिलाफ संघर्ष का झण्डा बुलंद कर रखा है। यही वजह है कि आदिवासियों और अन्य शोषितों के खिलाफ हर जगह सरकारी सशस्त्र बलों ने कहर ही ढाया, चाहे वो माओवादी आंदोलन में शामिल हों या न हों। कलिंगनगर, नारायणपटना, जगतसिंगपुर, लालगढ़ जैसे इलाकों में जबरिया जमीन-अधिग्रहण व पुलिसिया दमन के खिलाफ संघर्ष कर रही जनता पर तथा कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता पर, जो दशकों से अपने आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए व आजादी के लिए संघर्षरत है, सरकारी बलों के हमले लगातार जारी हैं। खासकर कश्मीर में आम नागरिकों को भी गोलियों से भून डालना सीआरपीएफ का रोजमर्रा का काम बन गया जिसका सबूत कश्मीरियों के हाल के संघर्ष से भी मिल जाता है। सरकारी आतंक, दमनचक्र और शोषण से दबे-कुचले जा रहे तमाम शोषित जनता की तरफ से हमने इस प्रतिरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया।

एक तरफ जनता के खिलाफ लगातार वहशी हमलों को अंजाम देते हुए ही दूसरी तरफ माओवादियों को 'हिंसा रोकने' की अपील करना शोषक सरकार के दोगलेपन का साफ सबूत है। '72 घण्टे तक माओवादियों को हिंसा रोकने' की बातों से तिकडमबाजी करने वाले चिदम्बरम अपने सशस्त्र बलों द्वारा जारी हिंसा और आतंक को एक पल के लिए भी बंद नहीं करवा रहे हैं। चिदम्बरम अपने झूठे व मनगढ़ंत बयानों से कार्पोरेट मीडिया के सहारे शहरी मध्यम वर्ग को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन बंगाल से लेकर आंध्रप्रदेश तक फैले हुए विशाल आदिवासी अंचलों में जीने वाले लोगों को तो कतई नहीं

कर सकते। जब चिदम्बरम हमें हिंसा रोकने की रट लगा रहे होते हैं, हकीकत में उनके ही निर्देश पर उनके भाड़े के बल बड़े-बड़े नरसंहारों को अंजाम दे रहे होते हैं या फिर उसकी तैयारियां कर रहे होते हैं। एक ही समय वे खुद को 'शांति के पुजारी' साबित करने की कोशिश करते हैं और सेना के प्रयोग के प्रस्ताव पर जोर भी देते हैं।

लेकिन मीडिया का एक हिस्सा इन तथ्यों पर नजर डालने की कोशिश नहीं कर रहा है। ज्ञानेश्वरी रेल हादसे में माओवादियों का हाथ होने के आरोप को हमारी पार्टी की पश्चिम बंगाल की इकाई द्वारा कई बार खरिज करने के बावजूद भी सरकारी व प्रशासन तंत्र के अधिकारी झूठ-मूठ के सबूत इकट्ठे कर माओवादी आंदोलन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। 18 मई को दंतेवाड़ा जिले के चिंगावरम के पास सवारी बस में 45 से ज्यादा आतंकी कोया कमाण्डो व एसपीओ बल बैठने के कारण, और खासकर बस की छत पर उन्हीं लोगों के बैठे रहने के कारण धोखे से हमारे कॉमरेडों ने उसे विस्फोट से उड़ाया था। उन्हें यह मालूम नहीं हो सका था कि उसमें आम यात्री भी सवार थे, बल्कि वे यह समझ बैठे थे कि पूरी बस को ही आतंकी बलों ने अपने कब्जे में ले रखा था। इस पर हमारी दण्डकारण्य पार्टी की दक्षिण रीजनल कमेटी ने खेद प्रकट किया और इस गलती के लिए क्षमायाचना भी की। फिर भी वे यह कहते हुए कि हमने जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाया, हमारे खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यह भी नहीं मालूम कि यहां सैकड़ों 'रुचिकाएं' हैं जो आए दिन पुलिसिया पाशविकता से रौंदी जाती हैं और यहां सैकड़ों 'सोहराबुद्दीन' हैं जो फर्जी 'मुठभेड़' में मार दिए जा चुके हैं। और न जाने कितने और लोग हैं जिनकी लाशें नदियों में फेंक दी गई थीं और जिनके मारे जाने की रिपोर्ट तक कहीं दर्ज नहीं हुई है। लेकिन इन सच्चाइयों से इन लोगों ने अपनी आंख बंद कर रखी है। कुछ जनवादी व उदारवादी बुद्धिजीवियों और जन पक्षधर मीडियाकर्मियों ने यहां हो रही सरकारी हिंसा व आतंक के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो उनका गला घोंटने की कोशिशें की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून (सीएसपीएसए) और गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत उन्हें जेलों में ठूंसने की साजिशें भी रची जा रही हैं। सरकारें फासीवादी दमन का पंजा दंतेवाड़ा के जंगलों से दिल्ली तक फैला रहा है, जो जनता के हितैषियों के लिए खतरे की घण्टी है।

हम फिर एक बार मीडियाकर्मियों व सम्पादकों समेत देश के तमाम बुद्धिजीवियों से विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि आप सरकारी या राजकीय आतंक की अनगिनत ज्ञात व अज्ञात घटनाओं की तह तक जाने की कोशिश करें। ओंगनार, चिनारी, राजूबेड़ा, कज्जुम जैसे गांवों का दौरा कर स्थानीय लोगों से सरकारी आतंक के बारे में जानकारी लें और उसकी निशानियों को अपनी आंखों से देखें। आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों यहां पर उरपलमेट्टा, रानीबोदली, मदनवेड़ा, ताड़िमेटला, और अब झाराघाटी जैसी घटनाएं घटती हैं।

हम देश के तमाम जन-पक्षधर बुद्धिजीवियों और समूची मेहनतकश अवाम से अपील करते हैं कि वे देश के शासकों से मांग करें कि देश की जनता के खिलाफ युद्ध, यानी ऑपरेशन ग्रीन हंट को फौरन व बिना शर्त बंद कर आदिवासी इलाकों से सारे अर्ध-सैनिक बलों को वापस बुला लें; देश की जनता के खिलाफ सेना को उतारने की कोशिशें बंद करें; आदिवासियों के नरसंहार तुरंत बंद करें; आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाओं में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें; गांवों को जलाना बंद करें; जेलों में बंद तमाम निरपराध आदिवासियों को बिना शर्त रिहा करें। हम वादा करते हैं कि अगर सरकारें ये कदम उठाने को आगे आती हैं, सरकारी हिंसा पर रोक लग जाती है तो हमारी तरफ से जवाबी हिंसा रोक दी जाएगी।

गुड्सा उसेण्डी, प्रवक्ता,
डीकेएसजेडसी, भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति : **दिनांक - 9 अगस्त 2010**

कॉमरेड मालती (शांतिप्रिया) और सुरेन्द्र कोसरिया को सजा:
प्रतिक्रियावादी रमन सरकार और तानाशाह पुलिस-प्रशासन की साजिश का परिणाम!
सजा मालती और सुरेन्द्र को नहीं, बल्कि रमनसिंह और महेन्द्र कर्मा को दो, जिनके हाथ सैकड़ों आदिवासियों के खून से रंगे हैं!!

29 जुलाई 2010 को रायपुर के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हमारी पार्टी कार्यकर्ता कॉमरेड मालती उर्फ शांतिप्रिया और केड़िया डिस्टिलरीज में काम करने वाले मजदूर सुरेंद्र कोसरिया को बहुचर्चित सीडी काण्ड में दोषी ठहराते हुए कई धाराओं के तहत अधिकतम 10 साल की सजा सुनाई। फरवरी 2006 में रायपुर के किसी पुलिस थाने में यह मामला दर्ज हुआ था कि छत्तीसगढ़ के विधायकों के बीच एक सीडी बांटी गई थी। वास्तव में उस सीडी को हमारी दण्डकारण्य स्पेशल जोनल

कमेटी के प्रचार ब्यूरो ने बनाया था जिसमें हमने बस्तर के कुछ इलाकों में जारी बर्बरतापूर्ण सलवा जुडूम की भयावह सच्चाइयों का चित्रण किया था। रमनसिंह और महेंद्र कर्मा की सांठगांठ से चलाए गए उस सरकार-प्रायोजित फासीवादी दमन अभियान के तहत किस तरह गांवों को जलाया जा रहा था, किस तरह लोगों की मनमानी हत्याएं हो रही थीं और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, इस सबको उस सीडी में हमारे प्रचार ब्यूरो ने कई सबूतों के साथ वीडियो फिल्मांकन किया था। पहले तो इस केस को कुछ महीनों बाद बंद कर दिया गया था क्योंकि विधायकों के पास कथित रूप से सीडी भेजने वालों का कोई पता नहीं लगाया जा सका था। लेकिन जनवरी 2008 में रायपुर में हमारी दो कॉमरेड्स मालती और मीना के साथ-साथ कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद सरकार के आदेश पर पुलिस अधिकारियों ने इस केस में कॉमरेड मालती के अलावा कुछ अन्य लोगों को फंसा दिया।

फासीवादी रमन सरकार, डीजीपी विश्वरंजन और तमाम पुलिस-प्रशासन ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय मानकर, किसी भी तरह इस केस में हमारे कॉमरेडों को सजा दिलवाने की ठान ले रखी थी। झूठे व सिखाए-पढ़ाए स्टॉक गवाहों के द्वारा गवाहियां दिलवाकर उन्होंने 10 साल की सजा दिलवा दी। यहां तक कि इसके लिए जज पर भी दबाव डाला गया था और कई अन्य गैर-लोकतांत्रिक हथकण्डों को अपनाया गया था। कॉमरेड्स मालती व मीना समेत सभी राजनीतिक कैदियों के साथ जेलों में काफी बुरा बरताव व मारपीट की भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। जेल अधिकारी शुरू से ही उन्हें तमाम मानसिक व शारीरक यातनाएं दे रहे हैं ताकि उनके मनोबल को तोड़ा जा सके। हमारी स्पेशल जोनल कमेटी उन्हें दी गई सजा और जेल में उनके साथ हो रहे बुरे बरताव का खण्डन करती है। और हमारी कमेटी यह मानती है कि यह दण्डकारण्य में जारी क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ रमन सरकार द्वारा छेड़े गए अन्यायपूर्ण युद्ध का हिस्सा ही है।

आज बड़े-बड़े नरसंहारों और मानवता को कलंकित करने वाले जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार लोग पूरे ऐशोआराम के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। बहुचर्चित भोपाल गैस काण्ड में, जिसमें 25 हजार से ज्यादा लोगों की बेमौत हुई थी, दोषी लोगों को 26 सालों के आपराधिक विलंब के बाद महज 2 साल की न्यूनतम सजा देना, सजा सुनाने के कुछ ही मिनटों बाद उन्हें जमानत पर छोड़ देना, और तो और इसका मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन को बाइज्जत देश से बाहर चले जाने की छूट देना इस बात का उदाहरण है कि देश की न्यायव्यवस्था बड़े व विदेशी पूंजीपतियों की पक्षधरता करती है। 1984 के सिख-विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार कांग्रेसी नेताओं को और 2002 में गुजरात में हुए मुसलमानों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी समेत कई संघ गिरोह के कातिलों को अभी तक सजा नहीं मिलना इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश की न्यायव्यवस्था जन विरोध ी और अल्पसंख्यक-विरोधी भी है। हजारों करोड़ों के जनधन के भारी घोटाले करने वालों को सजा देने का एक भी उदाहरण हमारे सामने नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि देश की न्यायव्यवस्था वाकई निष्पक्ष है। रुचिका का मामला और इस तरह के कई मामलों में, जिसमें महिलाओं के साथ जुर्म करने में बड़े-बड़े लोग अभियुक्त रहे हैं, अभी तक पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिला है। आश्चर्य की बात यह है कि इस रायपुर सीडी केस में कोई पीड़ित ही नहीं था और यह किसी भी तरीके से उनके संविधान का खिलाफ भी नहीं था। अगर कोई भी न्यायपसंद या जनवाद-पसंद इंसान उस सीडी को देखेगा तो सबसे पहले सवाल यह उठाएगा कि उसमें दर्शाई गई हिंसा, बलात्कार, हत्या और आतंक की घटनाओं के असल सूत्रधार रमनसिंह और महेन्द्र कर्मा को अभी तक सजा क्यों नहीं दी गई। लेकिन इस लूटखोर व्यवस्था के एक अंग के रूप में काम करने वाली इस न्यायव्यवस्था को सीडी में बताए गए विषयों के बनिस्बत सीडी बांटना ही गुनाह हो गया। अगर सीडी बांटना या पर्चा बांटना ही अपराध है तो इस अपराध को इस देश के करोड़ों लोग पहले ही अंजाम दे चुके हैं। एक बार नहीं, कई बार!

सरकार ने एक षड़यंत्र के तहत ही इस केस को चलाकर बिना किसी स्पष्ट सबूत के ही, कई झूठे व किराए के सरकारी गवाहों के जरिए तथा कई प्रकार के दबावों से हमारी पार्टी कार्यकर्ता मालती और गरीब मजदूर सुरेन्द्र कोसरिया को सजा सुनवाई। सरकार सोच रही है कि इस तरह सजाएं देने से क्रांतिकारियों, खासकर जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों का मनोबल तोड़ा जा सकता है। वह यह दिवास्वप्न देख रही होगी कि इस तरह झूठे मुकदमे चलाकर कड़ी सजाएं देकर लोगों को, खासकर शहरी इलाकों के लोगों को आतंकित किया जा सकता है और उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन से दूर रखा जा सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जेल की सलाखों और फांसी के तख़्तों ने क्रांतिकारियों के फौलादी संकल्प को और मेहनतकश जनता के इंकलाबी जज़्बे को न कभी तोड़ा है और न आगे तोड़ पाएंगे। हम देश के तमाम जनवादी बुद्धिजीवियों और मजदूर-किसानों से अपील करते हैं कि कॉमरेड मालती और सुरेन्द्र कोसरिया को दी गई अन्यायपूर्ण सजा का विरोध करें। इस मौके पर पुलिसिया दलालों व झूठे सरकारी गवाहों को चेतावनी देते हैं कि तुम लोग अदालतों में इस तरह की झूठी व सिखाई-पढ़ाई गई गवाहियां देकर दरअसल जनता के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं, अत: जनता आपको माफ नहीं करेगी। जनता की जनवादी अदालतें तुम लोगों का मुकदमा जरूर चलाएंगी।

गुड्सा उसेण्डी, प्रवक्ता,
डीकेएसजेडसी, भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति : **दिनांक - 18 अगस्त 2010**

कुटरेम गांव में निहत्थे आदिवासी युवक कुंजामी जोगा की निर्मम हत्या कर मुठभेड़ की कहानी गढ़ने वाले एसएसपी कल्लूरी और आईजी लांगकुमेर को सजा दो!

4 अगस्त 2010 के दोपहर से मीडिया में दंतेवाड़ा जिला, किरंदुल थाना क्षेत्र के तहत बैलाडीला खदानों से 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित गुमियापाल और कुटरेम के जंगलों में एक भारी मुठभेड़ होने की खबर चलाई गई थी। दोपहर को आईजी लांगकुमेर ने पत्रकारों को बताया था कि वहां पर गणेश उइके (हमारी पार्टी के दरभा डिवीजन के सचिव) के नेतृत्व में माओवादी गुरिल्लों की एक कम्पनी होने की सूचना पर उनके कोया कमाण्डो और एसपीओ के 110 लोग जंगलों में गए हुए थे और नक्सलवादियों के साथ 3-4 घण्टे की मुठभेड़ हुई थी। उन्होंने यह भी बताया था कि जवानों के साथ संपर्क टूट जाने के कारण पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। इस तरह उन्होंने मीडिया समेत पूरे प्रदेश की जनता को दिन भर सस्पेन्स में रखा था। और शाम ढलने के बाद यह घोषणा की कि भीषण मुठभेड़ के बाद नक्सलवादी जंगलों में भाग गए थे जबकि उनके 5-7 लोग मारे गए। उन्होंने 'एक नक्सलवादी का शव बरामद करने' का दावा किया था और कहा था कि बाकी शवों को नक्सलवादी अपने साथ ले गए थे। पीएलजीए कम्पनी के साथ 3-4 घण्टों तक मुठभेड़ होने के बावजूद भी उनके लोगों को खरोंच तक नहीं आना ही चूंकि अपने आप सच्चाई को बयान कर रहा था, इसलिए कई मीडियाकर्मियों ने सचाई का पता लगाने के लिए कुटरेम गांव की ओर जाने की कोशिश की। पर पुलिस वालों ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी।

अगले दिन यह खबर आई थी कि कुटरेम गांव के लोग, खासकर महिलाओं ने किरंदुल थाना में पहुंचकर पुलिस द्वारा 'नक्सलवादी' घोषित व्यक्ति के शव की अपने गांव के निवासी कुंजाम जोगा के रूप में पहचान की थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के सारे बयान झूठे ही थे। कथित 'मुठभेड़' के स्थल पर हमारे कॉमरेड गणेश उइके के होने का दावा एक कोरा झूठ था। हमारी पीएलजीए का कोई भी कॉमरेड उस समय वहां था ही नहीं। इसलिए 3-4 घण्टों की मुठभेड़ होने का दावा भी सचाई से कोसों दूर था। हममें से किसी के हताहत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिस शव को नक्सलवादी का बताया गया था वह भी पूरी तरह झूठ था। वास्तव में एसएसपी कल्लूरी, जिसके हाथ दर्जनों आदिवासियों के खून से रंगे हैं और जो खुद महिलाओं के साथ बलात्कार के कई आरोपों में लिप्त है, की सोची-समझी साजिश के तहत ही पुलिस ने कुटरेम गांव में यह हत्या की। दरअसल उस दिन उन्होंने चार गांवों हिरोली, गुमियापाल, कुटरेम और मड़कामगूड़ेम पर हमला किया था। पिछले 15 दिनों में 6 बार, यानी 20 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, 2 अगस्त, 4 अगस्त और 7 अगस्त को लगातार इन गांवों पर हमले किए। जब कोया कमाण्डों, जिन्हें एसएसपी कल्लूरी ने खासतौर पर पाल रखा है, 4 अगस्त को कुटरेम पर धावा बोला था, उस समय कुंजाम जोगा नामक 23 साल का नौजवान अपनी बहन बुदरी के घर से बाहर निकल रहा था। देखते ही पुलिस ने उस पर गोलियां चला दीं। गोली उसकी पीठ पर जा लगी थी जिससे वह बुरी तरह घायल हुआ था। कोया कमाण्डों ने नजदीक जाकर छुरों से उसके गले पर वार कर पाशविकता का प्रदर्शन किया। और तुरंत ही उसने दम तोड़ दिया। गांव के कुछ लोग इस हत्या के चष्मदीद गवाह रहे हैं। जोगा निहत्था था और वह गांव का निर्दोष नौजवान था।

7 अगस्त को हत्यारे कोया कमाण्डो फिर कुटरेम पहुंचे और गांव के स्कूल के सामने लोगों को बुलाकर एक सभा की। उसमें ग्रामीणों को बिस्कुट, मिक्चर, पैसे आदि बांटकर लोगों पर यह दबाव डाला कि मीडिया वाले आएंगे तो उनको वे सच नहीं न बताएं। बल्कि यह बताएं कि जोगा कुंजाम की मौत गांव में नहीं, जंगल में मुठभेड़ के दौरान हुई थी। सचाई बताने से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ने की धमकी भी दी।

क्यों की यह हत्या?

दण्डकारण्य में, खासकर ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत अभी तक जितनी भी 'मुठभेड़ें' हुईं, सभी की सच्चाई करीब-करीब यही है। अगर इसी इलाके की बात की जाए तो, 12 अप्रैल 2009 को पुलिस ने मड़कामगूड़ेम गांव में तीन लोगों की झूठी मुठभेड़ में हत्या की थी। 27 नवम्बर 2009 को हिरोली गांव के बीचोंबीच मड़काम मंगू नामक युवक की हत्या कर दी थी। 11 दिसम्बर 2009 को गुमियापाल के छह किसानों की एक फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई थी। 23 जनवरी 2010 को इसी कुटरेम गांव के चार आदिवासियों की गोली मार कर हत्या की गई थी और मठभेड़ की कहानी फैला दी गई थी। 16 मई 2010 को गुमियापाल के पास वंजामी मल्ला और कुटरेम के पास कुंजामी आयतू - दो किसानों को पुलिस द्वारा मार डाला गया था। लोगों की हत्याओं के अलावा गांवों को घेरना और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करना और कहीं-कहीं घरों में आग लगा देना - यही सब पिछले एक साल से चल रहा है बस्तर में।

खासकर बैलाडीला खदानों से सटे हुए इस इलाके को

निशाने पर लेने के पीछे टाटा, एस्सार और एनएमडीसी माइनिंग माफिया का हाथ है। जनता में आतंक फैलाना ही ऐसी हत्याओं के पीछे उनकी एक मात्र मंशा है ताकि उनके माइनिंग हित पूरे हो सकें और लोगों के विरोध का दबा दिया जा सके। इसीलिए वे हत्याएं करते हैं, इसीलिए महिलाओं के साथ पाशविकता बरतते हैं और इसीलिए ऑपरेशन ग्रीन हंट को चला रहे हैं। और उन्हें किसी चीज का डर भी नहीं है। उन्हें मालूम है कि बस्तर के आदिवासियों के मामले सोहराबुद्दीन मामला जैसे नहीं बन पाएंगे और बस्तर की किसी आदिवासी युवती को मीडिया में उतनी सहानुभूति तो नहीं मिलने वाली है जितनी कि रुचिका को मिली थी। और उन्हें यकीन है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनके इशारों पर ही बनेगी। मेजिस्टीरियल इंक्वाइरी से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वे मीडिया वालों पर भी दबाव बना सकते हैं ताकि वे वही रिपोर्ट करे जो पुलिस बताती है।

इतना प्रचार क्यों?

इसे बहुत बड़ी मुठभेड़ के रूप में दिन भर मीडिया के जरिए प्रचारित करने के लिए सिर्फ कल्लूरी, कोया कमाण्डो नंदा जिम्मेदार नहीं हो सकते। इसके पीछे डीजीपी विश्वरंजन, बस्तर के आईजी लांगकुमेर जैसे बड़े-बड़े अधिकारी थे जिन्होंने एक बड़े षड़यंत्र के तहत इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया था। चूंकि पिछले कुछ समय से बस्तर में सीआरपीएफ बलों पर पीएलजीए के हमले हो रहे थे, इसलिए सीआरपीएफ के जवान स्थानीय पुलिसिया महकमे से नाराज भी चल रहे हैं। विश्वरंजन ने यह कहकर कि 'हम सीआरपीएफ वालों को चलना नहीं सिखा सकते' जले पर नमक छिड़क दिया था। इसलिए एक भ्रामक मुठभेड़ का झूठा प्रचार कर उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि 'हम पुलिस वाले या कोया कमाण्डो और एसपीओ माओवादी छापामारों द्वारा घेरे जाने के बावजूद भी सीआरपीएफ वालों की तरह मार नहीं खाने वाले हैं, बल्कि उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसाकि 4 अगस्त को कुटरेम में किया।'

हम छत्तीसगढ़ के मेहनतकश लोगों, बुद्धिजीवियों और इंसाफ-पसंद मीडियाकर्मियों से अपील करते हैं कि वे मुठभेड़ की हरेक घटना पर निष्पक्ष जांच की मांग करें। मुठभेड़ में शामिल पुलिस अफसरों और जवानों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करें। आज बस्तर की जनता अपने अस्तित्व के लिए, अपने जल-जंगल-जमीन को बचाने के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। आपसे हमारी विनम्र अपील है कि आप इस संघर्ष में उनके पक्ष में खड़े होने के लिए आगे आएं। बस्तरिया निहत्थे व निर्दोष आदिवासी युवक-युवतियों के हत्यारों को सजा देने की मांग करें। इन हत्याओं और ऑपरेशन ग्रीन हंट अभियान को फौरन रोकने की मांग करें।

गुड्सा उसेण्डी, प्रवक्ता,
डीकेएसजेडसी, भाकपा (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति : **दिनांक - 6 अगस्त 2010**

परमाणु दायित्व विधेयक का अनुमोदन देश की सार्वभौमिकता को विदेशी कम्पनियों के चरणों में गिरवी रखना ही है! सांठगांठ के साथ कांग्रेस और भाजपा द्वारा देश की जनता के हितों पर किए जा रहे कुठाराघात का विरोध करो!!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कल लोकसभा में अनुमोदित परमाणु दायित्व (न्यूक्लियर लियबिलिटी) विधेयक को देशवासियों के हितों का पूरी तरह खिलाफ समझती है और इसका यह कहकर खण्डन करती है कि यह देश की सार्वभौमिकता को विदेशी कम्पनियों के पैरों में गिरवी रखना ही है। हालांकि शुरू में भाजपा ने दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर यह बताया था कि यह विधेयक जन-विरोधी है, लेकिन बाद में यूपीए सरकार द्वारा किए गए चंद संशोधनों से 'संतुष्ट' होकर लोकसभा में इस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी। यह दरअसल उसके साम्राज्यवाद-परस्ती और जन-विरोधी चरित्र के अनुरूप ही है। लेकिन उसने इस विधेयक का विरोध करने का ढोंग सिर्फ इसलिए किया था ताकि जनता को धोखे में रखा जा सके। 'वामपंथी' पार्टियों समेत सभी पार्टियों ने यह कोशिश नहीं की कि इस विधेयक से देशवासियों के हितों को क्या नुकसान हो सकता है, बल्कि खुद को सिर्फ संसदीय तिकड़बाजी तक सीमित रखा।

दरअसल भोपाल गैसकाण्ड के बाद करीब 25 हजार लोगों की बेमौत और लाखों लोगों के स्वास्थ्य को हुई अपूरणीय हानि के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड (अब डाउ केमिकल्स जिसने उसे खरीदा) को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं करना, इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को 26 सालों

की लम्बी 'न्याय' प्रक्रिया के बाद सिर्फ दो साल की सजा देना, और उसमें मुख्य आरोपी वारन एंडरसन को बाइज्जत देश से बाहर चले जाने का मौका देना आदि से देश की सरकारों ने पहले ही अपने साम्राज्यवाद-अनुकूल चरित्र को साबित कर लिया। देश की समूची जनता से उठे विरोध के बावजूद अमेरिका के साथ यूपीए सरकार ने परमाणु करार कर देश की सार्वभौमिकता का ही मजाक उड़ाया था। वास्तव में परमाणु रिएक्टरों का दुनिया भर में जनता और प्रगतिशील लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब इस परमाणु दायित्व कानून के जरिए भोपाल, चेर्नोबिल जैसी कई और दुर्घटनाएं होने पर भी विदेशी कम्पनियों पर कम से कम 'दायित्व' सुनिश्चित किया जाएगा। दरअसल देश में अभी तक ऐसा कोई कानून ही नहीं था। यानी हादसा होने की सूरत में पूरी जिम्मेदारी सरकार की ही है। अब इस तरह 'दायित्व' सुनिश्चित करने का साफ मतलब यह है कि इस क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां, खासकर अमेरिकी कम्पनियां अपने रिएक्टर हमारे देश में बेचने को उतावली हो रही हैं। इन रिएक्टरों के कारण हादसे होने और उनमें बड़े पैमाने पर भारतवासियों की मौत होने पर भी जहां तक संभव हो कम से कम खर्च से और कम 'दायित्व' से बच निकल जाने की सुविधा इन कम्पनियों को दी जाने वाली है। यूपीए सरकार ने इस विधेयक की रूपरेखा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में इसलिए तैयार की ताकि उनके मुनाफों को पूरी गारंटी हो सके। वास्तव में पिछले 30 सालों से परमाणु रिएक्टर बनाने वाली कम्पनियों को कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यह कानून बन जाने से इन कम्पनियों के लिए भारत एक लुभावने बाजार बन जाएगा। इसलिए हमारी पार्टी यह अपील करती है कि समूचे देशवासी इस कानून का और इस कानून की आड़ में परमाणु क्षेत्र में अमेरिकी कम्पनियों की घुसपैठ का विरोध करें। और इस सबके लिए कारण बने भारत-अमेरिका परमाणु करार को रद करने की पुरजोर मांग करें। हम यह भी अपील करते हैं कि इस जन-विरोधी और देशद्रोहपूर्ण कानून का अनुमोदन करने वाली कांग्रेस, भाजपा आदि संसदीय पार्टियों की धोखेबाजपूर्ण नीतियों का पर्दाफाश करें।

भोपाल दुर्घटना को लेकर देश में मुखर हो रहे विरोध के मद्देनजर कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी सरकार ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेकसिंह अहलूवालिया को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें यह चेतावनी थी कि यह माहौल यूं ही रहे तो पूंजीनिवेश पर असर पड़ सकता है। अब आनन-फानन में इस परमाणु दायित्व कानून को अनुमोदित करने के पीछे भी बेशक अमेरिकी साम्राज्यवादियों का दबाव है, जोकि जगजाहिर भी है। 26 साल पहले लाखों भारतवासियों की जिंदगियों में हुई तबाही के बावजूद भी वारन एंडरसन और यूनियन कार्बाइड (डाउ केमिकल्स) को जिस तरह का 'इंसाफ' मिला है उसी प्रकार का 'इंसाफ' आगे भी मिलता रहे, इसी को सुनिश्चित करना इस कानून को सामने लाने का असल मकसद है।

माओवादी आंदोलन को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बताते हुए घोर नरसंहार और अमानवीय अत्याचारों को अंजाम देने वाले शसक वर्ग खुद ही देशवासियों के हितों के खिलाफ जाकर बड़ी और विदेशी कम्पनियों के सामने किस तरह माथा टेक रहे हैं, इसे समझने का यह एक ताजा उदाहरण है। हम जनता और जनवादी शख़्सों व संगठनों से अपील करते हैं कि वे यह समझें कि देश के लिए असली खतरा किन लोगों से है और देशवासियों के हितों के घोर विरोध ी असल में कौन हैं।

गुड्सा उसेण्डी, प्रवक्ता,
डीकेएसजेडसी, भाकपा (माओवादी)

(... पेज 36 का शेष)

राज्य स्तर के खोए हुए दूसरे नेतृत्वकारी कॉमरेडों की भरपाई असंभव है।

इन नुकसानों के वास्तविक कारणों को समझने से ही हम उनकी रोकथाम कर पाएंगे और तभी हमारी पार्टी को मजबूत व दुश्मन के लिए अभेद्य बना पाएंगे। हमारी पार्टी और दूसरे देशों की माओवादी पार्टियों के अनुभवों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए ताकि असली कारणों को चिन्हित किया जा सके।

देश में और दूसरे देशों में संघर्षरत ताकतों से एकजुटता कायम करते हुए हमें अपने आत्मरक्षात्मक युद्ध को विस्तारित व तेज करना चाहिए जिसे हमारी पार्टी की अगुवाई में पीएलजीए और जनता अंजाम दे रही हैं। अगर हम जनता पर मजबूती से निर्भर करते हैं और इस युद्ध में पीएलजीए का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ऑपरेशन ग्रीन हंट को पराजित करने में हम निश्चित रूप से सक्षम हो जाएंगे।

आइए, हम जनयुद्ध को बेहद साहस और दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखने के लिए खुद को तैयार कर लें। हमारी पार्टी की 6वीं वर्षगांठ को पूरे इंकलाबी जोशोखरोश के साथ मनाएं। पिछले एक साल की अवधि में घोर दमन के बीचोबीच भी अर्जित की गई सफलताओं का व्यापक रूप से प्रचारित करें।

प्यारे कॉमरेडो व देशवासियो!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) देश की समूची जनता का आह्वान करती है कि हमारे देश को साम्राज्यवादियों के हाथों बेचने वाले सामंती व दलाल शासकों के खिलाफ हमारी पार्टी के नेतृत्व में एकजुट हों। एक क्रांतिकारी पार्टी के बिना इन शोषकों के शिकंजे से हमारे देश को आजाद करना नामुमकिन है। देश में मची हुई लूटखसोट के खिलाफ जारी विभिन्न प्रतिरोधी संघर्षों में डटे हुए तमाम लोगों का हमारी पार्टी आह्वान करती है कि वे एकजुट हो जाएं ताकि एक व्यापक संयुक्त मोर्चे का रास्ता साफ हो सके। जोतने वालों को जमीन

(शेष पेज 51 में...)

(... अंतिम पेज का शेष)

आइये, जनता की मुक्ति के लिए अपनी जानें कुरबान कर जाने वाले इन वीर शहीदों व बस्तर माटी के इन बहादुर बेटों को अपना सिर झुकाकर पूरी विनम्रता से सलामी दें।

कॉमरेड बण्डू (बारसू कोरसा)

करीब 26 साल के नौजवान कॉमरेड बण्डू का जन्म माड़ इलाके के काकूर गांव में हुआ था। यह गांव नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड में आता है। माड़िया समुदाय के कोरसा परिवार में जन्मे बण्डू का माता-पिता ने उनका नाम 'बारसू' रखा था। वह अपने माता-पिता की तीसरी संतान थे। जब वह छोटे थे तब उनके बड़े भाई की मृत्यु हुई थी। उनकी दो बहनें और दो भाई हैं। काकूर ऐसा गांव है जो माड़ को गड़चिरोली डिवीजन से जोड़ता है। इधर से उधर और उधर से इधर आने-जाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और गुरिल्ला बलों को यह गांव अपनी गरीबी के बावजूद भी कुछ न कुछ खिलता-पिलाता है। इस गांव का नाम सरकार को पता है भी या नहीं, किसी को नहीं पता। लेकिन इस गांव ने वर्तमान जनयुद्ध के पन्नों पर तो जगह बना ही ली। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक 'परालकोट विद्रोह' (1825) का केन्द्र परालकोट यहां से ज्यादा दूर नहीं है। आंग्ल-मराठा शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने वाले पहले शहीद गेंदसिंह को जिस जगह पर फांसी दी गई थी, वहां से यह गांव काफी करीब है। शुरू से ही क्रांतिकारी राजनीति से प्रेरित इस गांव ने कभी सरकार की तरफ, उसके झूठे सुधारों की जूठन की तरफ नहीं देखा। चूंकि 'विकास' के शब्द तक से वे सदियों से अछूते थे, इसलिए यहां शिक्षा का नामोनिशान तक नहीं था। काकूर के बड़े ही नहीं, बच्चे भी गुरिल्ला दस्तों के गीतों और स्नेहपूर्ण व्यवहार से प्रेरित होने लगे थे। इस तरह बच्चे बढ़ते गए और ठीक से जवानी की दहलीज में कदम तक नहीं रखे थे कि उनके दिलों में गुरिल्ला बनने की इच्छा पैदा हो गई। आने-जाने वाले हर कॉमरेड से, हर जिम्मेदार साथी से वो अपनी दिली इच्छा प्रकट करते थे कि वो बंदूक उठाना चाहते हैं और फौजी पोशाक पहनना चाहते हैं। लेकिन हर कॉमरेड ने उन्हें यही समझाने की कोशिश की कि तुम लोग अभी छोटे हों, जरा बड़े हो जाओ ताकि गुरिल्ला जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना किया जा सके। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे।

कई दौर के मान-मनौवल के बाद जुलाई 1999 में इस गांव के चार किशोर थोड़ा आगे-पीछे पीएलजीए में भर्ती हो गए। इन चारों में तीन चचेरे भाई और एक बहन शामिल थे। कुछ ही दिनों बाद दुर्भाग्य से 20 जुलाई 2000 को इन तीन भाइयों की बहन कॉमरेड राजे सांप काटने से शहीद हो गई। इस गम को भुलाकर इन तीनों कॉमरेडों ने अलग-अलग इकाइयों में अपनी जिम्मेदरियों का निर्वाह जारी रखा। उनमें से एक थे कॉमरेड बण्डू जो भर्ती के समय सिर्फ 16 साल के थे।

कॉमरेड बण्डू को पहले परालकोट दल का सदस्य बनाया गया था। उसके बाद वह माड़ डिवीजन के सीएनएम दल में सदस्य बनाए गए थे। वर्ष 2002 में उन्हें एसजेडसी के विशेष दस्ते में सदस्य के रूप में लिया गया था। बाद में उस दस्ते का उप-कमाण्डर भी बने थे। बण्डू में हर चीज को जानने-समझने की बढ़िया जिज्ञासा और क्षमता थीं। वह दिखने में अपने उम्र से भी छोटा व दुबला-पतला आकार के थे, इसलिए हर कॉमरेड ने उन्हें प्यार बांटा था। कई नेतृत्वकारी कॉमरेडों ने उन्हें विकसित करने के लिए विशेष ध्यान दिया और मदद की। कॉमरेड बण्डू ने भी इस मदद का फायदा उठाया और पढ़ने-लिखने के मामले में बाकी कॉमरेडों की तुलना में आगे निकल गए। 2004 में उन्होंने अपने ही दस्ते की सदस्या कॉमरेड रामे से प्यार कर पार्टी की सहमति से शादी कर ली। कॉमरेड रामे 2009 में धमतरी में गिरफ्तार हुई थी और फिलहाल वह जेल में है।

जुलाई 2004 में दण्डकारण्य में पहली बार गठित पीएलजीए की कम्पनी-1 में उन्हें शामिल करते हुए सेक्शन कमाण्डर की जिम्मेदारी दी गई। तबसे लेकर अपनी शहादत तक पूरे छह साल उनकी क्रांतिकारी जिन्दगी कम्पनी-1 में ही बीती। पार्टी के राजनीतिक व सैद्धांतिक विषयों को वह ध्यान लगाकर पढ़ते थे और समझने की कोशिश करते थे। हर विषय को जानने के लिए उनके दिमाग में सवाल उठते रहते थे। और अपने सवालों को कॉमरेडों के सामने पेश करने में वह हिचकते नहीं थे जिससे उन्हें और भी सीखने का मौका मिल जाता था। वो एक विनम्र कॉमरेड थे जो साथियों से हर चीज को ध्यान से सुनते थे और

कोंगेरा शहीदों की बहादुराना शहादत जिंदाबाद!

अपनी शंकाओं को सामने रखकर जानकारी हासिल करते थे। कॉमरेड बण्डू फौजी मोर्चे पर और राजनीतिक समझदारी में तेजी से उभरने वाले कॉमरेड थे। सीखना, समझना और साथी गुरिल्लों को समझाना - इस तरह कॉमरेड बण्डू कम्पनी-1 में एक चहेते कॉमरेड बन गए। पीएलजीए के अनुशासन का पालन करना, मेहनत करना, लड़ाई के दौरान वीरता का प्रदर्शन करना और साथियों के साथ विनम्र व्यवहार - इन गुणों को देखते हुए कॉमरेड बण्डू को पदोन्नति भी मिलती रही। पहले उन्हें प्लटून के उप-कमाण्डर और फिर प्लटून कमाण्डर और प्लटून सचिव की जिम्मेदारियां देकर सितम्बर 2008 में कम्पनी पार्टी कमेटी में सदस्य के रूप में चुन लिया गया। इस तरह कम उम्र में ही उच्च जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ने के दौरान ही कॉमरेड बण्डू का शहीद हो जाना खासकर फौजी मोर्चे के लिए बड़ा नुकसान है।

फौजी कार्रवाइयों में कॉमरेड बण्डू का योगदान

अपनी 11 साल की क्रांतिकारी जिंदगी में कॉमरेड बण्डू ने कई ऐम्बुशों और रेडों में भाग लिया। दुबले-पतले शरीर वाले कॉमरेड बण्डू फौजी कार्रवाइयों में तेजतर्रार योद्धा के रूप में भाग लेते थे। डौला शार्ट सरप्राइज एटैक, मुरकीनार, एनएमडीसी बारूद गोदाम, कुरसनार, झाराघाटी, कुदुर, रानीबोदली, नारायणपुर जिला मुख्यालय में एसपीओ के घरों पर हमला, रिसगांव, बेरेवेड़ा-1 व बेरेवेड़ा-2, बट्टुम, मल्लेचूर, मूंडपाल, बजरंगबलि के पास विक्रम उसेण्डी के काफिले पर हमला, करकेली आदि कई ऐम्बुश और रेड की कार्रवाइयों में उन्होंने अनुपम शूरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। कम्पनी-1 द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों में उन्होंने न सिर्फ भाग लिया, बल्कि उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई। लड़ाइयों को सफल करने में वह अपनी जान पर खेलते थे। 2010 की गर्मियों में अमोनियम नाइट्रेट की गाड़ी पर कब्जा करने की कार्रवाई में भी कॉमरेड बण्डू की भागीदारी रही।

2005 से जारी फासीवादी सलवा जुडूम को हराने के लिए चलाए गए प्रतिरोधी अभियान को सफल बनाने तथा हर साल लिए जाने वाले टीसीओसी को सफल बनाने में कॉमरेड बण्डू ने बहादुरी से का प्रदर्शन करते हुए भाग लिया, नेतृत्व किया। खासकर इंद्रावती और पश्चिम बस्तर के इलाकों में जनता पर जारी जुडूम के आतंक को रोकने और जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए कॉमरेड बण्डू ने भरपूर प्रयास किया। वह जनता के बीच एक लोकप्रिय कॉमरेड थे। माड़ के अलावा, पूर्व बस्तर, पश्चिम बस्तर, गढ़चिरौली - वह जहां भी गए जनता में लोकप्रियता हासिल की।

29 जून 2010 के दोपहर अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़कर कॉमरेड बण्डू अपनी शहादत से हमें गम के साथ-साथ सफलता दे गए। उस लड़ाई में उन्होंने एक प्लटून के कमाण्डर के रूप में नेतृत्व करते हुए फायर एण्ड मूवमेंट में अपने बलों का बढ़िया तालमेल किया। शुरू में ही दो दुश्मनों का सफाया कर और कुछ को घायल कर दिया जिससे बाकी जवानों को वहां से भागना पड़ा। और वहां अपनी एक सेक्शन को छोड़कर वह दूसरी जगह में दुश्मन से लड़ रहे अपने साथियों से जा मिले। वहां पर शत्रु बलों का पूरी तरह से घेराव करने में उन्होंने कमाण्ड के संपर्क करते हुए साथियों से तालमेल बनाया। युद्ध के मैदान में वह जो काशन दे रहे थे, दुश्मनों के दिलों में घबराहट पैदा कर रहे थे, जबकि हमारे साथियों के हौसलों को और भी बुलंद कर रहे थे। करीब-करीब ऐम्बुश समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। सिर्फ 4 या 5 दुश्मन ही बचे हुए थे जो अपने प्रतिरोध से हथियार छीनने की पक्रिया को रोक रहे थे। इस परिस्थिति में हेडक्वार्टर ने कॉमरेड बण्डू के नेतृत्व में छह कॉमरेडों की एक टीम बनाकर तेजी से आगे बढ़ते हुए बचे हुए दुश्मनों को मार गिराने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन करते हुए कॉमरेड बण्डू अपनी जान की जरा भी परवाह किए बिना अपनी टीम के साथ आगे बढ़ गए। इसी इंतजार में बैठे दुश्मन के एक निशानेबाज ने गोलियां चला दीं जिससे कॉमरेड बण्डू और कॉमरेड रमेश मौके पर ही शहीद हो गए। कॉमरेड बंडू को सिर में और कॉमरेड रमेश को छाती पर गोलियां लगी थीं। इसके तुरंत बाद टीम के बाकी कॉमरेडों ने सारे दुश्मनों का सफाया कर ऐम्बुश को जबर्दस्त कामयाबी दिलवाई। विजय की कगार पर पहुंचने के बाद, मात्र 10 मिनट पहले इन दोनों कॉमरेडों के शहीद हो जाने से सभी साथियों को सदमा सा लगा था। लेकिन, आखिर यह युद्ध है, इसमें हर कामयाबी कुरबानियों की मांग करती है। जिस तरह आठ जांबाज कॉमरेडों की शहादत के बिना 6 अप्रैल 2010 वाली ऐतिहासिक ताड़िमेट्ला कार्रवाई की कल्पना नहीं कर सकते, उसी तरह कॉमरेड्स बण्डू, शंकर और रमेश की शहादत के बिना हम कोंगेरा कार्रवाई की सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते।

कॉमरेड बण्डू से हमें सीखना है -

1) उन्होंने खुद को एक बहादुर कमाण्डर के रूप में विकसित किया। कमांडिंग, कंट्रोल और समन्वय की कला में उन्होंने अच्छी-खासी पकड़ हासिल की।

2) वह सीखने की बढ़िया क्षमता रखते थे। परिस्थितियों के अनुसार चलने का हुनर था उनमें। भौगोलिक धरातल को नजर में रखते हुए शत्रु बलों के खिलाफ रणकौशल का बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। राजनीतिक व फौजी विषयों को सीखने में उनकी गहरी दिलचस्पी रही।

3) सामूहिकता की भावना को वह हमेशा प्राथमिकता देते थे। अपनी प्लटून पार्टी कमेटी को वह सामूहिक इकाई के रूप में संचालित करते थे। सामूहिक कार्य-पद्धति को महत्व देते थे।

4) वह मेहनती कॉमरेड थे। कोई भी काम बताने पर इनकार उनके मुंह से कभी निकलता ही नहीं था। किसी भी काम को पूरा करने की कोशिश जरूर करते थे। रसोई के लिए लकड़ी लाने से लेकर पानी लाने तक पीएलजीए की रोजमर्रा

जिंदगी का हर काम करते थे।

5) गलतियां होने पर निराश नहीं हुआ करते थे। गलती से सबक लेते हुए आगे बढ़ने को ही सोचते थे।

6) वह हर समय दुश्मन पर हमले के बारे में सोचा करते थे। दूसरे जोनों और राज्यों में होने वाले सफल हमलों की खबरों से वह प्रेरणा पाते थे।

ऐसे समय, जबकि 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' को पराजित कर क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हम लड़ रहे हैं, कॉमरेड बण्डू की कमी हमें खलेगी। कॉमरेड बण्डू ने कोंगेरा ऐम्बुश में जो पहलकदमी, सूझबूझ, बहादुरी, बेहतरीन कमाण्डिंग, अपनी जान की जरा भी परवाह न करने वाली आत्म-बलिदान की उच्च भावना आदि का प्रदर्शन किया उससे पीएलजीए के हर कमाण्डर को, हर लड़ाकू को प्रेरणा मिलेगी।

कॉमरेड शंकर (पुनाऊ हलामी)

कॉमरेड पुनाऊ हलामी (27) का जन्म केशकाल इलाके के किसकोड्डो के निकट ऊचाकोट गांव में हुआ था। यह गांव नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब है। उनका परिवार लोहार काम करने वाला मध्यम आदिवासी परिवार था। वह माता-पिता का बड़ा बेटा था। ऊचाकोट गांव विकास से वंचित और वन विभाग के अधिकारियों के जुल्मों से त्रस्त गांवों में से एक था। वन विभाग वाले और पटवारी क्या-क्या करते थे, इसे बचपन में ही कॉमरेड पुनाऊ ने देख लिया था। उनके गांव के नजदीक रावघाट पहाड़ है जिसमें सरकार खदान खोलकर आदिवासियों का विनाश करने पर आमादा है। शहीद कॉमरेड सुखदेव के नेतृत्व में इस इलाके में पहली बार गुरिल्ला दस्ते का प्रवेश हुआ। तबसे यह इलाका क्रांतिकारी संघर्ष का हिस्सा बन गया। जन संगठनों का निर्माण होने लगा। कॉमरेड सुखदेव की अगुवाई में जनता ने वन विभाग व पटवारियों के जुल्मों को बंद करवाया। रावघाट लोहा खदान और कुव्वेमारी बाक्साइट खदान के खिलाफ लोगों की लामबंदी हुई। रावघाट खदान शुरू होने से लोहा साफ करने के लिए जो बांध बनाया जाएगा, उसमें ऊचाकोट गांव डूब जाने वाला है। इस खतरे को समझते हुए ऊचाकोट गांव के लोग मजबूती से संगठनों में गोलबंद हो गए।

बचपन में कॉमरेड पुनाऊ बाल संगठन का सदस्य बने थे। उनका परिवार पूरा क्रांतिकारी समर्थक था। गांव के मुखिया संगठनों को हतोत्साहित करने की कोशिश करते थे। लेकिन कॉमरेड पुनाऊ शुरू से ही क्रांतिकारी संघर्ष के प्रति उत्साहित थे। उन्होंने अपनी बहन को भी प्रोत्साहित कर पार्टी में भर्ती करवाया। और तीन-चार युवकों को पार्टी में शामिल करने में उनका योगदान रहा। वह खुद मई 2001 में केशकाल दस्ते में सदस्य के रूप में भर्ती हो गए। पार्टी की जरूरतों के मुताबिक उन्होंने रावघाट और परतापुर इलाकों में भी दस्ता सदस्य के रूप में काम किया। एक साल तक उन्होंने एक डीवीसी सदस्य के गॉर्ड के रूप में भी काम किया। उन्होंने पार्टी में भर्ती होने के बाद अपना नाम 'आजाद' बदला था।

बाद में उन्हें परतापुर एलजीएस का उप-कमाण्डर बनाया गया। फिर परतापुर एरिया कमेटी का सदस्य बन गए। फिर रावघाट में एलजीएस कमाण्डर के साथ-साथ एरिया कमाण्डर-इन-चीफ की जिम्मेदारी भी निभाई। उसके बाद उन्हें फिर से 2007 में परतापुर इलाके में भेज दिया गया। वहां जन मिलिशिया को प्रशिक्षण देते हुए उसे विकसित करने पर जोर दिया। 2008 में उन्हें पलटन-17 में कमाण्डर और सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और उन्हें उत्तर बस्तर डिवीजनल कमाण्ड के सदस्य के रूप में लिया गया। 2009 में गठित कम्पनी-6 में उन्हें कम्पनी पार्टी कमेटी सदस्य और कम्पनी उप-कमाण्डर के रूप में शामिल किया गया। उन्होंने एसजेडसी के इस फैसले को सहर्ष स्वीकार किया और इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आपको विकसित करने की पूरी कोशिश की। कम्पनी में स्थानांतरित होने के बाद उन्होंने अपना नाम शंकर बदला।

उत्तर बस्तर में काम करने के दौरान ही उन्होंने अपनी पसंद की एक कॉमरेड से शादी की। दोनों ने अलग-अलग जिम्मेदारियों में रहकर पार्टी में अपना-अपना योगदान दिया।

फौजी हमलों में कॉमरेड शंकर

एक दस्ता सदस्य के रूप में और एक कमाण्डर के रूप में कॉमरेड शंकर ने कई कार्रवाइयों में भाग लिया। 2005 में दुर्गकोंदल के पुलिस वालों के साथ मेंडो गांव के पास दो घण्टे तक हुई घमासान लड़ाई में कॉमरेड शंकर शामिल थे। कई जन विरोधी दुश्मनों को दण्डित करने में कॉमरेड शंकर भागीदार रहे। एक एक्शन टीम के कमाण्डर के रूप में उन्होंने पखांजूर कस्बे में एक मुखबिर को मार गिराया था।

अपनी अंतिम लड़ाई में कॉमरेड शंकर ने बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन से लोहा लिया। पहली असल्ट टीम के कमाण्डर के रूप में उन्होंने अपने सेक्शन का नेतृत्व किया। पहले ही दौर में उन्होंने दुश्मन पर धावा बोलते हुए एक दुश्मन को मार गिराया। उसके बाद उन्होंने दूसरी जगह पर दुश्मन का घेराव करने वालों से मिलकर लड़ाई जारी रखी। इस बीच जब वह दुश्मन पर निशाना साध रहे थे तभी एक दुश्मन ने उन पर गोली चला दी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

कॉमरेड शंकर ने हमेशा जनता और कार्यकर्ताओं के साथ बढ़िया सम्बन्ध बनाए रखा। गांवों में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के साथ उनका बेहतर सम्बन्ध रहता था। कॉमरेड शंकर सीधा और स्पष्ट बोलने वाले इंसान थे। घुमा-फिराकर बात करना उन्हें आता नहीं था। उन्होंने कम्बैट बलों में रहकर काम करना चाहा। फौजी मोर्चे पर उभरते हुए इस नौजवान की शहादत से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हम अपने दुख को दृढ़ संकल्प में बदलकर कॉमरेड शंकर के आदर्शों और अधूरे सपनों को साकार बनाने के लिए हिम्मत के साथ कदम बढ़ाएंगे।

कॉमरेड रमेश (ओड़ी उंगाल)

करीब 30 वर्षीय कॉमरेड रमेश का जन्म दरभा डिवीजन के गांव टीटो में हुआ था। बाद में वह अपने चाचा के पास गांव पुव्वार जिला दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर डिवीजन) में आ गए थे। पुव्वार गांव एक क्रांतिकारी किला है, जो हमेशा दुश्मनों के लिए चुनौती रहा है। पुव्वार गांव की माताओं ने कई वीर योद्धाओं को जन्म दिया। इस गांव के कॉमरेड शहादतों व लड़ाइयों में कभी पीछे नहीं रहते। कॉमरेड रमेश को घर में ओड़ी उंगाल के नाम से पुकारा जाता था। वह सितंबर 2001 में दल में भर्ती हुए थे। 2001 के आखिर से उन्होंने पलटन-5 में सदस्य के रूप में काम किया। 2002 के आखिर में उन्हें पलटन-1 में स्थानांतरित किया गया। जुलाई 2004 तक उन्होंने उसी में काम किया था।

शुरू से ही वह बहुत मजबूत व मेहनती कामरेड थे। कंपनी-1 के गठन के साथ ही वह उसके सदस्य बने थे और आखिर तक कम्पनी में ही बने रहे। कम्पनी के जीवन में उन्होंने संतरी, किचेन आदि जिम्मेदारियों को निभाया। उन्होंने मैकानिक काम भी सीखा था। कम्पनी में हथियारों में छोटी-छोटी खराबियों को वह ठीक कर देते थे। हथियारों को रंग चढ़ाकर सुंदर बनाते थे। उन्हें मैकेनिक काम में और ज्यादा प्रशिक्षण दिलवाने का कम्पनी पार्टी कमेटी ने निर्णय लिया था। लेकिन इसे लागू करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।

उन्होंने कई सैनिक कार्रवाइयों में भाग लिया। डौला हमले में, एनएमडीसी, मुरकीनार, रानिबोदली आदि हमलों में उन्होंने भाग लिया था। रानिबोदली कार्रवाई में वह हल्के से जख्मी हो गए थे। कुछ दिन तक चले इलाज के बाद वह फिर अपनी जिम्मेदारी में आ गए। टेकानार, कड़ियानार, बोदली, मूंडपाल, मल्लेचूर, बेरेवेड़ा, कुरसनार, जारावेड़ा (गढ़चिरोली), झाराघाटी, कुदूर, मैनपुर आदि कई ऐम्बुशों में उन्होंने भाग लिया। इंद्रावती और नेशनल पार्क इलाकों में सलवा जुडूम के जुल्मों के खिलाफ जनता को लामबंद करते हुए प्रतिरोधी कार्रवाइयों को अंजाम देने में भी कॉमरेड रमेश की अहम भूमिका रही।

कंपनी-1 में उनको बाद में सेक्शन कमांडर व एलएमजी मैन की जिम्मेदारी प्रदान की गई। उन्होंने कोंगेरा ऐंबुश में जबर्दस्त भूमिका निभाकर उसकी सफलता में उल्लेखनीय योगदान दिया। जब आखिरी मौके पर दुश्मनों के नजदीक तक जाकर भिड़ना था, तब वह बेझिझक और बेखौफ अपने कमाण्डर कॉमरेड बण्डू के साथ एलएमजी से आग उगलते हुए आगे बढ़ते गए। मात्र 30 गज की दूरी से जब वह दुश्मन से दो-दो हाथ कर रहे थे दुश्मन की एक गोली उनके सीने को चीरते हुए निकल गई। इससे बस्तर का यह प्यारा बेटा, शोषित जनता का यह सच्चा सेवक वहीं धराशायी हो गया। लेकिन उनके साथी नहीं रुके, इधर बण्डू और रमेश की लाशें गिरती रहीं, दूसरे साथी रमेश की एलएमजी उठाकर दुश्मनों पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उन्हें ढेर कर पूरी सफलता दिलवा दी।

इन तीन कॉमरेडों की मृत्यु से हमें बड़ा नुकसान हुआ है, फिर भी जैसा कि माओ ने भी कहा - हर लड़ाई कुरबानी मांगती है। और दुश्मन के बलों का भारी संख्या में उन्मूलन कर बड़ी-बड़ी कामयाबियां हासिल करनी हैं तो हमें भी जरूर खून बहाना ही पड़ेगा। रानीबोदली (2007) में छह कामरेडों व अभी 6 अप्रैल को ताड़िमेटला में हमारे आठ कॉमरेडों ने अपना खून बहाकर ही हमें सफलता दिलाई थी। इसी सिलसिले में आज कॉमरेड बण्डू, कॉमरेड शंकर और कॉमरेड रमेश की शहादतों से ही यह ऐतिहासिक कार्रवाई 4 घण्टों की लड़ाई के बाद सफल हो पाई। ये शहादतें पीएलजीए के हर योद्धा के लिए ऊर्जा व प्रेरणा के स्रोत सिद्ध होंगी। आने वाले दिनों में ऐसे हजारों बण्डू, शंकर व रमेश बन निकलेंगे जो इस शोषणकारी व्यवस्था को दफनाकर ही दम लेंगे। ★

(... पेज 47 का शेष)

के लिए, जनता को जनवादी सत्ता के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए जारी संघर्षों तथा सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्रों), विस्थापन, कॉर्पोरेट खनन परियोजनाओं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, महंगाई, भ्रष्टाचार और ऐसी तमाम ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ संघर्षों को एकजुटता के साथ चलाना चाहिए। हम अपनी एकजुट ताकत के जरिए ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ज्यों-ज्यों हमारी लड़ाई तेज होगी, सभी जनवादी व क्रांतिकारी संघर्षों के खिलाफ राज्य का हमला भी तीखा होगा। आइए, हम खुद को इसके लिए तैयार कर लें। जन जागरण, सलवा जुडुम, सेंदेरा, ग्रीन हंट आदि कोई भी प्रतिक्रियावादी ताकत दृढ़ संकल्प से लैस जनता या उनकी क्रांतिकारी पार्टी को तोड़ नहीं सकती। अंतिम जीत जनता की ही है।

- **हमारी पार्टी को एक अभेद्य किले के रूप में मजबूत करेंगे और नेतृत्व व कतारों में भारी नुकसानों की रोकथाम करेंगे!**
- **ताड़िमेटला लड़ाई को ऊंचा उठाकर तथा इस बेजोड़ नमूने का अनुसरण करते हुए 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' को हराएंगे!**
- **सभी प्रतिरोधी आंदोलनों में एकजुटता कायम कर तथा उनके साथ एकजुट होकर एक मजबूत व देशव्यापी संयुक्त मोर्चे की नींव रखेंगे!**
- **कॉमरेड आजाद के आदर्शों को ऊंचा उठाकर उनके योगदान को मिसाल बनाकर दुश्मन के मनोवैज्ञानिक युद्ध का सुचारू तरीके से मुकाबला करेंगे!**
- **जनयुद्ध के बहुमुखी कार्यभारों की पूर्ति के लिए व्यापक इलाकों में विस्तार करेंगे!**

30 अगस्त 2010

सरकारी ग्रीन हंट अभियान को करारा जवाब देते हुए कोंगेरा (नारायणपुर) शौर्यपूर्ण कार्रवाई में अपनी जानें कुरबान करने वाले जांबाज वीर योद्धा कॉमरेड्स बण्डू, शंकर और रमेश को लाल सलाम!

कॉमरेड बण्डू

कॉमरेड शंकर

कॉमरेड रमेश

जब्त किए गए शस्त्रास्त्र

एके-47 -	9
इन्सास -	10
एसएलआर -	3
दो इंची मोर्टार -	2
इन्सास एलएमजी -	2
कुल हथियार -	26 और

सैकड़ों गोलियां और ढेर सारा फौजी साजोसामान

29 जून 2010 के दिन पीएलजीए के हमारे जांबाज लाल योद्धाओं ने अपने बहादुर कमाण्डरों के नेतृत्व में और क्षेत्र की संघर्षशील जनता की सक्रिय मदद से हत्यारे, अत्याचारी व आतंकी सीआरपीएफ बलों पर नारायणपुर जिले के कोंगेरा गांव के पास एक और शौर्यपूर्ण हमला किया। चार घण्टों तक चले इस जबर्दस्त घमासान में 27 भाड़े के जवान मारे गए और 8 अन्य घायल हुए। ताड़िमेट्ला की तर्ज पर चले इस ऐम्बुश में मारे गए सरकारी बलों से 26 अत्याधुनिक हथियार छीन लिए गए ताकि जन सेना की शस्त्र सम्पत्ति को बेहतर बनाया जा सके। खासकर 'ऑपरेशन ग्रीनहंट' के तहत पुलिस व अर्ध-सैनिक बलों द्वारा पिछले 10 महीनों में दण्डकारण्य में 150 से ज्यादा लोगों की हत्या कर, कई गांवों को जलाकर और कई महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर घोर आतंक जो मचाया गया, उसके जवाब में ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जिस जगह पर यह ऐम्बुश हुआ, उसके आसपास के गांवों ओंगनार, चिनारी (इन्नर), राजूबेड़ा, कज्जुम आदि में अर्ध-सैनिक बलों द्वारा जिस प्रकार लोगों की अंधाधुंध हत्याएं की गईं और घरों में आग लगा दी गई, उसके खिलाफ जनता आक्रोशित थी। जनता के बचाव में, जनता की मांग पर और जनता के गुस्से को अभिव्यक्ति देते हुए पीएलजीए ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

इस शौर्यपूर्ण हमले को सफल बनाने की खातिर हमारी पीएलजीए के तीन बहादुर कमाण्डरों ने अपने अनमोल प्राणों को भारत की नई जनवादी क्रांति की बलिवेदी पर अर्पित किया। ये तीन कॉमरेड थे - बण्डू (कम्पनी पार्टी कमेटी सदस्य/प्लटून कमाण्डर), शंकर (कम्पनी पार्टी कमेटी सदस्य/कम्पनी उप-कमाण्डर) और रमेश (सेक्शन कमाण्डर/एलएमजी मैन)।

(शेष पेज 48 में...)